हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 मार्च, 2002

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 6 मार्च, 2002

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एंव उत्तर	(3) 1
वाक आउट	(3) 3
तारांकित प्रश्न एंव उत्तर (पुनरारम्भ)	(3) 4
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये	(3) 22
तारांकित प्रश्नो के लिखित उत्तर	(3) 28
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 31
सदन में मर्यादा कायम रखना	(3) 33
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-	
रोग फैलने सम्बन्धी	(3) 34
वक्तव्य	(3) 34
स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(3) 34
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(3) 38
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3) 38

मूल्य : 63 00

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री बंसी लाल, एम0एल0 ए0 द्वारा (3) 55

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) (3) 58

बैठक का समय बढ़ाना (3) 72

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) (3) 73

बैठक का समय बढ़ाना (3) 75

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) (3) 76

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 6 मार्च, 2002

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब सवाल होंगे।

Addition in Generation

@ *918. Shri Banta Ram Balmiki,

Shri Bhupinder Singh Hooda: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is an increase in the generation of power, if so, the year-wise detail from 1999 onwards ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : हां श्री मान। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम के अपने उत्पादन केन्द्रों द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान वर्ष 1998-99 की तुलना में विद्युत उत्पादन में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्षवार ब्यौरा सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

ब्यौरा

वर्ष	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम द्वारा अपने उत्पादन केन्द्रों से उत्पादित बिजली/मिलियन यूनिट में
1998-99	3783.55
1999-2000	4050.98
2000-2001	3792.41
2001-2002	4330.29/जनवरी तक/ 5220/ 31-3-02 तक अनुमानित

श्री बन्तराम बाल्मिकी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार बिजली के कितने नये प्लांटस लगाने जा रही है?

चौ0 भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन ऑवर शुरू करने से पहले एक मिनट के लिए आप हमारी बात सुन लें। कल आपने हमारी पार्टी के जिन सदस्यों को हाउस से निकाला है कृपया उनको हाउस में वापस बुलाइये।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, अभी आप बैठें।

@ Put by Sh. Banta Ram Balmiki

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुन लें। * * * *

श्री अध्यक्ष : अब जो भी भजन लाल जी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए ।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठें । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सभी माननीय सदस्य हाउस की वैल में आ गए।)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें । (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह इनका किस तरह का व्यवहार है। इनको कुछ तो शर्म आनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) मैं सारे तरीके जानता हूं । (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठें।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, आप इनसे कहें कि ये अपनी सीट पर जाकर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) इनको अपनी-अपनी सीट पर जाकर बात करनी चाहिए। भजन लाल जी, आप इनके लीडर हैं इसलिए आप अपने मैम्बर्ज को अपनी सीटों पर बैठाएं। अगर ये आपकी बात नहीं मानते तब बात और है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, आप को सबको एक आँख से देखना चाहिए। * * * *

श्री अध्यक्ष : जो ये बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। भजनलाल जी, आप बैठें ।

चौ० भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर हम अपनी सीट पर जाकर अपनी बात कहेंगे तो क्या आप हमारी बात सुनेंगे?

श्री अध्यक्ष : यह तो आप कंडीशन लगा रहे हैं। You are imposing condition, भजनलाल जी, कल आप कह रहे थे कि क्वैश्चन ऑवर से पहले मैंने दूसरा बिजनैस क्यों शुरू किया और आज आप स्वयं ही ऐसा करने जा रहे हैं जिससे क्वैश्चन ऑवर का काम नहीं चल पा रहा है।

चौ० भजनलाल : स्पीकर साहब, आप हमारे मैम्बर्ज को वापस हाउस में बुलाएं। मुख्यमंत्री जी, पता नहीं आज हैं या नहीं लेकिन अगर वह नहीं हैं तो उनके अलावा सम्पत सिंह जी, धीरपाल सिंह जी तो हैं इनको भी इस बात के लिए फैसला करना चाहिए और बाहर निकाले हुए सदस्यों को वापस हाउस में बुलाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : जब आपका समय था और हमारी पार्टी के सदस्यों को सस्पैंड किया गया था तब मैंने हाथ भी जोड़ लिए थे लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा : आप क्या उस समय का हमसे बदला ले रहे हैं ?

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री धीर पाल सिंह : बदला नहीं ले रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ0 भजन लाल : चोर दरवाजे से बिना ऐजैंडे के आपने अविश्वास प्रस्ताव मूव कर दिया ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। क्वेश्चन ऑवर कभी भी सस्पैंड नहीं होता।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के जो सदस्य बाहर बैठे हुये हैं उनके भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं इसलिए उनको आप बुला लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : यह जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। चौधरी भजन लाल जी, आप बगैर परमीशन के खड़े हुए हैं। आप बैठ जाइए । (शोर एवं व्यवधान)

चौ0 भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, आप उन को बुलाने का फैसला कीजिए।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही इम्पौरटैंट बात कहना चाहता हूं। आज हमें हाउस में आने से रोका गया है और आपका नाम लेकर रोका गया है कि स्पीकर साहब कह रहे हैं इसलिए अंदर नहीं जाने देते । फिर हमने यह कहा कि लिखित में कोई ऑर्डर दिखाओ नहीं तो हम प्रिविलेज मोशन डालेंगे। नहीं तो हमें अंदर आने दीजिए। तब जाकर अंदर आने दिया है।

श्री अध्यक्ष : आज तो आप अंदर समय पर आए हैं अगर आपको रोका गया होता तो आपको यहां आने में देरी होती। कल आप समय पर नहीं थे।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर सर, कल मैं तो समय पर था लेकिन आप सिर झुकाकर जाने क्या बोलते चले गए कुछ समझ में ही नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : मैं शुद्ध हिन्दी में बोल रहा था मैं कोई ऐसी भाषा नहीं बोल रहा था कि जो मैंने कहा वह आपकी समझ में नहीं आया होगा।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी, उर्दू या इंग्लिश आप जो भी भाषा बोलें वह सब मेरी समझ में आती है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान) अब श्री बन्ता राम जी अपनी सप्लीमैंट्री पूछें।

श्री बन्ता राम बाल्मिकी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कितने प्लांट लगा रही है ?

वाक आउट

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए हम ऐज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदन में उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री रामपाल माजरा : हुड्डा साहब, आप बाक आउट करके जा रहे हैं आपका बहुत ही इम्पोरटेंट क्वैश्चन बिजली के बारे में लगा हुआ है आपको वह क्वैश्चन पूछना चाहिए, यहां बैठना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए और देखना चाहिए कि सत्तापक्ष ने बिजली के मामले में कितना काम किया है। अध्यक्ष महोदय, बिजली की ओर बहुत ध्यान दिया गया है। बंता राम जी ने जानना चाहा है कि आने वाले समय में कितने नये प्लांट लगाना सरकार के विचाराधीन है। स्पीकर साहब, बिजली परियोजना 2 यमुनानगर में 14.4 मैगावाट क्षमता का पॉवर स्टेशन लगाना विचाराधीन है और ताऊ देवीलाल थर्मल पावर स्टेशन पानीपत की 7वीं 8वीं यूनिट लगाना विचाराधीन है। यमुनानगर थर्मल पावर स्टेशन का चरण एक व दो एवं मैसर्स आई0ओ0सी0 पैट्रो कोक आधारित परियोजना पानीपत व फरीदाबाद गैस आधारित परियोजना चरण 2 व नाथपा झाकरी पन बिजली परियोजना, दुलहस्ती पन बिजली परियोजना व हिसार थर्मल परियोजना चरण एक ये सभी पावर स्टेशन लगाने व जनरेशन के लिए विचाराधीन हैं।

श्री कृष्ण लाल पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी0पी0एस0 महोदय से जानना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य में बिजली कहां-कहां से प्राप्त होती है, थर्मल प्लांट के सुधारीकरण के लिए क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं और कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी ने यह जानना चाहा है कि हरियाणा प्रदेश में कितनी बिजली कहां से प्राप्त हो रही है और इसके क्या-क्या सोर्सिज हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में फरीदाबाद थर्मल विद्युत केन्द्र से हमें बिजली मिलती है जो हमारा अपना थर्मल विद्युत केन्द्र है। ताऊ देवीलाल थर्मल विद्युत केन्द्र, पानीपत पश्चिमी यमुना नहर पनबिजली केन्द्र, यमुनानगर से भी हमें बिजली मिलती है, यह कुल मिलाकर 1073 मैगावाट है। संयुक्त परियोजनाओं में बिजली का जो हमारा हिस्सा है वह इस प्रकार है- भाखड़ा नांगल कम्पलैक्स से 492 मैगावाट, देहर पावर प्लांट से 317 मैगावाट, पौंग पावर प्लांट से 60 मैगावाट, इन्द्रप्रस्थ थर्मल स्टेशन, दिल्ली से 62.50 मैगावाट। इस प्रकार संयुक्त परियोजनाओं से कुल हमें 931.50 मैगावाट बिजली मिलती है। केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाओं में जो हमारा हिस्सा है वह इस प्रकार है- बैरासूल पनबिजली परियोजना से 54.90 मैगावाट, सिंघरौली सुपर थर्मल परियोजना से 200 मैगावाट, सलाल हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना से 104 मैगावाट, रिहन्द सुपर थर्मल परियोजना से 65 मैगावाट, आंटा गैस से 25.30 मैगावाट, औरिया गैस से 38.20 मैगावाट, नरोरा से 28.10 मैगावाट, दादरी गैस से 40.60 मैगावाट, फरीदाबाद गैस से 432 मैगावाट, टनकपुर हाइडल से 6 मैगावाट, उच्चाहार सुपर थर्मल प्लांट से 34 मैगावाट, चमेरा हाइडल से 85 मैगावाट, उरी हाइडल से 26 मैगावाट, आर0ए0पी0पी0 से 12.50 मैगावाट। इस प्रकार केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाओं से हमें कुल बिजली 1151.60 मैगावाट मिलती है। स्वतंत्र और निजी बिजली परियोजनाओं में जो हरियाणा का हिस्सा है वह इस प्रकार है, मारूति उद्योग से हमें 30 मैगावाट, मैगनम अन्तर्राष्ट्रीय बिजली से 25 मैगावाट, उपयोग/डी से 55 मैगावाट। इस प्रकार स्वतंत्र और निजी परियोजनाओं से हमें कुल मिलाकर 3211.10 मैगावाट बिजली मिलती है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे माननीय साथी ने यह जानना चाहा है कि हमने हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम के थर्मल पावर स्टेशनों की कार्य

कुशलता में क्या सुधार किए हैं तो मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि प्लांट लोड फैक्टर 49.24 प्रतिशत से बढ़कर 59.91 प्रतिशत हो गया है, औसत दैनिक विद्युत उत्पादन 96 लाख यूनिट से बढ़कर 135 लाख यूनिट हो गया है जोकि 40 प्रतिशत की वृद्धि है, प्रति यूनिट कोयला उपभोग 838 ग्राम से घटकर 792 ग्राम हो गया है जिसके फलस्वरूप 69.20 करोड़ रुपए की संचित बचत हुई है, तेल उपभोग में 74 प्रतिशत की कमी आई है अर्थात प्रति यूनिट तेल उपभोग 12.70 मिली लीटर से घटकर 3.33 मिली लीटर हो गया है जिसके फलस्वरूप 79.87 करोड़ रुपये की संचित बचत हुई है, इसी प्रकार ऑक्जलरी खपत 12.04 प्रतिशत से घटकर 11.17 प्रतिशत हो गई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी को मैं यह बताना चाहूंगा कि ये आंकड़े अपने आप में बोल रहे हैं कि बिजली की पोजीशन में यह सुधार आया है, इन्होंने पूछना चाहा था कि ये सुधार लाने के लिए क्या-क्या पग उठाए गए थे जिसकी वजह से बिजली की पोजीशन में यह सुधार हुआ है। विभिन्न इकाईयों की मुरम्मत का काम नियमित समय पर किया गया है। शैडयूल्ड टाईम पर किया गया है और सुचारू रूप से किया गया है जिसकी वजह से क्षमता बढ़ी है। पुरानी ईकाईयों की त्रुटियों को दूर कर दिया गया है। पानीपत शुगर मिल में आधुनिक ई0एस0पी0 लगाया गया है जिससे मशीनों की उपलब्धता तथा क्षमता बढ़ गई है। इसी तरह से स्पीकर सर, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्तर के कोर्स कराये गये हैं और उनको ट्रेनिंग दी गई है जिसकी वजह से कर्मचारियों को नई मॉडर्न टैक्नोलौजी के माध्यम से काम करने की क्षमता और उनके ज्ञान में वर्धन हुआ है। इसी तरह से तेल, कोयले व ऑक्जलरी की खपत पर निरंतर निगरानी रखकर उसमें कमी लाई गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों को आकर्षक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रेरित किया गया है, जो अधिकारी अच्छे काम करते हैं उनको ईनाम के तौर पर प्रोत्साहन दिया जाता है जिसकी वजह से कर्मचारी अधिक कुशलता से काम कर सकें। इस योजना के लिए सरकार ने अच्छे वित्तीय प्रबन्धन किये हैं। सरकार ने इस प्रकार के जो कदम उठाये हैं उनकी पूरे देश में प्रशंसा की गई है। हमारी बिजली विभाग की चेयरपर्सन को केरला सरकार ने इस बात के लिए अपने यहां आमंत्रित किया है कि हमें बतायें कि आपने बिजली की क्षमता को बढ़ाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया है। इस प्रकार हरियाणा सरकार ने बिजली के उत्पादन में जिस प्रकार के कदम उठाये हैं उससे सारे देश में हरियाणा सरकार की सराहना हुई है।

श्री कृष्णलाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, पानीपत थर्मल पावर प्लांट के दो यूनिटों की 110 मैगावाट से 118 मैगावाट क्षमता बढ़ाने के लिए और इनके सुधारीकरण के लिए चौधरी बंसीलाल जी की सरकार के समय प्राईवेट ठेकेदारों को 300 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था। केवल मात्र 8 मैगावाट क्षमता को बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था और उन बातों को कई साल हो गये हैं प्रदेश सरकार को इससे काफी नुकसान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी महोदय से जानना चाहता हूं कि उन यूनिटस को चालू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और इनको कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में इस बारे में मैंने एक डिटेलड वक्तव्य दिया था। फिर भी मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि चौधरी बंसीलाल जी की सरकार के समय में एक जर्मनी की कम्पनी ए0बी0बी0 के साथ इन यूनिटों की 8 मैगावाट क्षमता को बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपये का एम0ओ0यू0 साईन किया गया था लेकिन वह किसी कारण से बीच में ही टूट गया और यह काम अधूरा रह गया। अब वर्तमान सरकार ने केवल

[श्री रामपाल माजरा]

20 करोड़ रुपये में यह काम फिर से शुरू कर दिया है और सरकार का काफी पैसा बचाया है और यह कार्य जल्दी ही पूरा हो जायेगा। इससे सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी महोदय से जानना चाहता हूँ कि फरीदाबाद में जो गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट 432 मैगावाट का दूसरा फेज है वह कितने दिन में उत्पादन देना शुरू कर देगा और क्या यह हरियाणा प्रदेश को ही अपना उत्पादन दे पायेगा या दूसरे राज्यों को भी बेचेगा ? दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माजरा साहब से यह जानना चाहूंगा कि 1998-99 में बिजली के लाईन लोसिज कितने प्रतिशत थे उसके मुकाबले आज के दिन कितने प्रतिशत हैं ? तीसरा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन की तरफ से जो बिजली संयत्र पानीपत रिफाइनरी में लगना है वह कब तक उत्पादन करना शुरू कर देगा ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, फरीदाबाद गैस बेस्ड पावर प्रोजैक्ट 432 मैगावाट का लगाना है। इस मामले को 10वीं योजना के प्लान में शामिल करना है और भारत सरकार से इस बारे में बात हो रही है। इस पर कार्य कब शुरू होगा यह तो मैं नहीं बता सकता लेकिन 2006-2007 तक इस प्रोजैक्ट को पूरा कर लिया जायेगा। स्पीकर सर, इसके लिए एन0टी0पी0सी0 को यूनियन पावर मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी है कि इस प्रोजैक्ट को जल्दी से जल्दी टेकअप किया जाये।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सी0पी0एस0 जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि फरीदाबाद गैस बेस्ड पावर प्रोजैक्ट मेरे क्षेत्र के गांव मुंझेड़ी में पड़ता है। मुझे आज भी याद है कि जिस समय सरकार ने वहां के किसानों की जमीन एक्वायर करनी शुरू की थी उस समय मुंझेड़ी और आसपास के गांवों के किसानों ने इस बात पर रीजैंटमैंट शो किया था कि जब सरकार उनकी जमीन ऐक्वायर कर रही है तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर उनको बिजली और दूसरी सुविधाएं मुहैया करवायेगी ? उस समय प्रशासन ने मुंझेड़ी और उसके समीप के गांवों को आश्वासन दिया था कि प्राथमिकता के आधार पर उन गांवों में विकास कार्य किए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस प्लांट के लगने से वहां इतनी ज्यादा लाईट है जिसके कुप्रभाव से वहां के पशुओं के दूध की क्षमता कम हो रही है। अध्यक्ष महोदय, वहां के किसानों का मुख्य पेशा पशु पालन ही है।

श्री अध्यक्ष : बिसला जी, यह पशुओं से संबंधित प्रश्न नहीं है आप बिजली से संबंधित प्रश्न पूछें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं वहीं आ रहा हूं। मैं माजरा साहब को बताना चाहूंगा कि उन लोगों की बात कोई सुनता ही नहीं है। वहां के अधिकारी उन लोगों को अपने दफ्तर में नहीं बड़ने देते। अध्यक्ष महोदय, क्या माजरा साहब वहां के अधिकारियों को यह आदेश देंगे कि उन किसानों की जो समस्या है उसका समाधान उस आश्वासन के आधार पर किया जायेगा जो जमीन एक्वायर करते समय दिया गया था। इस बारे में एग्रीमैंट भी किया हुआ है कि वहां पर प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य किए जायेंगे।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को और पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि वैसे तो आज के दिन पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास की झड़ी लगी हुई है और अब हरियाणा में कोई भी गांव विकास कार्यों से अछूता नहीं रहा है। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत सभी जगह विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। फिर भी बिसला जी ने एक अहम मुद्दा उठाया है इस बारे में मैं बिसला जी को बताना चाहूंगा कि एम0ओ0यू0 में यह मामला दर्ज है और एम0ओ0यू0 में जो बातें दर्ज हैं उनको हमारी सरकार निभायेगी। हमारी सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी और जहां तक दूध की क्षमता कम होने वाली बात है, मुझे नहीं लगता कि इस प्लांट के लगने से कोई एडवर्स इफैक्ट पड़ता हो।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, इस स्टेशन की लाईट इतनी ज्यादा है कि वहां पर 10 कि0मी0 तक रोशनी रहती है और किताब भी पढ़ी जा सकती है। इस स्टेशन की लाईट के कारण वहां बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। अध्यक्ष महोदय, इस स्टेशन से वहां के कई हजार लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है इसलिए प्रशासन को कहा जाये कि उन किसानों की समस्या का समाधान किया जाये।

श्री अध्यक्ष : बिसला जी, पशुओं को भी तो गर्मी की आवश्यकता होती है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात कही कि प्रशासन को आदेश दिए जाएं कि उन लोगों की शिकायतों पर गौर किया जाये ताकि उनको कुछ सुविधाएं मिल सकें। इस बारे में मेरा इनको कहना है कि ये उनकी समस्याएं लिख करके वहां के अधिकारियों को दे दें, हम इस बारे में वहां के अधिकारियों को आदेश दे देंगे कि उन पर गौर कर लिया जाये। फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में कई सोशल वॉलेन्टरी संस्थाओं द्वारा और सरकार द्वारा कहीं पर पौधे लगाये जा रहे हैं, कहीं पर स्कूल्ज बनाये जा रहे हैं और कहीं पर डिस्पेंसरीज आदि बनाई जा रही हैं।

श्री बलबंत सिंह मायना : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये सारे हरियाणा प्रदेश में 24 घण्टे बिजली मुहैया करवाएंगे क्योंकि पहले की जितनी भी सरकारें रहीं, चाहे वे कांग्रेस की सरकार थीं या बंसीलाल जी की सरकार थी कोई भी सरकार प्रदेश के लोगों को पूरी बिजली नहीं दे पाई। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी बिजली देंगे वह किन-किन माध्यमों से देंगे और पूरी बिजली पूरे प्रदेश को कब तक मिल जायेगी ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, मैंने डिटेल में अतिरिक्त बिजली की जनरेशन के बारे में बताया है। जो सवाल मायना जी ने किया है, इस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पिछले अधिवेशन के दौरान एक सवाल के जवाब में मैंने पूरी तफसील से बताया था कि बिजली के सुधारीकरण के लिए हम इतने स्टेशन या सब स्टेशन लगाने जा रहे हैं या लगा दिए गए हैं। मैं वहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी तो उस वक्त हरियाणा प्रदेश के लोगों को 24 घण्टे बिजली लगातार बिना किसी बाधा के प्राप्त होती थी। चौधरी देवी लाल जी के युग को आज भी हरियाणा प्रदेश के लोग याद करते हैं। इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में भी प्रदेश के लोगों को लगातार 24 घण्टे बिजली मिल रही है। कहीं से बिजली की मोटर या बल्ब सड़ने की शिकायत नहीं आई है और पूरी फ्रीक्वेंसी के साथ बिजली लगातार मिल रही है।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, ये कैसे कह रहे हैं कि 24 घण्टे बिजली मिल रही है और लोगों की मोटरें नहीं सड़ी।

श्री अध्यक्ष : राम किशन जी, आप बैठ जाएं।

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर साहब, लोगों को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, इनके राज में तो 12 किसानों को गोली से उड़ा दिया गया था फिर 24 घण्टे बिजली कहां से मिलती ?

श्री अध्यक्ष : इस बात का इनको कहां पता होगा, क्योंकि उस वक्त तो ये फौज में होंगे।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। जो ये कह रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाये।

Job-Oriented Courses in Private Colleges

***913. Shri Bhag Singh :** Will the Minister of State for Education be pleased to State whether any permission has been granted to Govt. Aided Private Colleges in the State to run job-oriented courses; if so, the details there of ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) : हां, श्रीमान जी। विवरण सदन के पटल पर रखे जाते हैं।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान संस्वीकृत रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के विवरण :

उच्चतर शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने तथा सहस्राब्दी की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से सत्र 2001-2002 में राज्य के निम्नलिखित सरकारी सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों को रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई है :—

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	संस्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम
1	2	3
1.	अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बल्लबगढ़	सूचना विज्ञान में स्नातक, सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक
2.	डी0ए0वी0 सेंटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	सूचना विज्ञान में स्नातक
3.	सी0आर0ए0 महाविद्यालय, सोनीपत	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
4.	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत	कम्प्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर) में एम0ए0स0सी0
5.	गीता विद्या मन्दिर केन्द्रीय महाविद्यालय, सोनीपत	सूचना विज्ञान में स्नातक

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

1	2	3
6.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक
7.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	सूचना प्रौद्योगिकी में बी0एस0सी0, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक, कम्प्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर) में एम0एस0सी0
8.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	कम्प्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर) में एम0एस0सी0, सूचना प्रौद्योगिकी में बी0एस0सी0
9.	के0वी0ए0 डी0ए0वी0 महिला महाविद्यालय, करनाल	जैव प्रौद्योगिकी, बी0एस0सी0 भाग-1 स्तर पर अणुजैविकी, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
10.	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	सूचना प्रौद्योगिकी में बी0एस0सी0
11.	एस0डी0 महाविद्यालय, पानीपत	सूचना प्रौद्योगिकी में बी0एस0सी0
12.	एम0एन0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाहाबाद	कम्प्यूटर विज्ञान सहित बी0एस0सी0
13.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद मारकंडा	एम0एस0सी0 सॉफ्टवेयर
14.	आई0बी0 महाविद्यालय, पानीपत	सूचना प्रौद्योगिकी में बी0एस0सी0
15.	आर्य कन्या महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक, सूचना प्रौद्योगिकी में बी0एस0सी0
16.	डी0ए0वी0 महाविद्यालय, अम्बाला शहर	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, कम्प्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर) में एम0एस0सी0
17.	एस0ए0 जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर	सूचना प्रौद्योगिकी में बी0एस0सी0 सूचना प्रौद्योगिकी में एम0एस0सी0 कम्प्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर) में एम0एस0सी0 कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मध्याह्न तथा सायंकालीन सत्र)
18.	एस0डी0 महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक
19.	जी0एम0एन0 महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक

1	2	3
20.	जी0बी0 डिग्री महाविद्यालय, रोहतक	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक
21.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक, सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक
22.	श्री एल0एन0 हिन्दू महाविद्यालय, रोहतक	कम्प्यूटर विज्ञान में एम0एस0सी0, सूचना विज्ञान में स्नातक, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक
23.	ए0आई0जाट महाविद्यालय, रोहतक	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, कम्प्यूटर विज्ञान में एम0एस0सी0
24.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	कम्प्यूटर विज्ञान में एम0एस0सी0, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
25.	सी0आर0एम0 जाट स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिसार	कम्प्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर) में एम0एस0सी0, सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर
26.	डी0एन0 महाविद्यालय, हिसार	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक, सूचना प्रौद्योगिकी में बी0एस0सी0, कम्प्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर) में एम0एस0सी0
27.	डी0ए0वी0 कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	सूचना प्रौद्योगिकी में बी0एस0सी0, कम्प्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर) में एम0एस0सी0, सूचना विज्ञान में बी0एस0सी0 (ऑनर्स)
28.	गुरु नानक कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक, सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर
29.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी	सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, एम0एस0सी0 कम्प्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर) में एम0एस0सी0
30.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	कम्प्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर) में एम0एस0सी0

31.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर	सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक
32.	डी0ए0वी0 महाविद्यालय, सढ़ौरा (यमुनानगर)	सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक

10.00 बजे अध्यक्ष महोदय, ये 32 कोर्सिज़ हमने चालू किए हैं ताकि सब को फायदा हो सके। बाकी जिसकी भी कोई डिमाण्ड आती है उसको नॉर्म्ज के अनुसार इन्सपैक्शन करवा कर चालू करने की कोशिश करते हैं।

श्री भाग सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वर्ष 2002-2003 में भी ऐसे प्रावधान हैं जिनसे प्राईवेट कॉलेजिज़ में कोर्सिज़ शुरू किए जाएं ?

चौ0 बहादुर सिंह : जो कॉलेज वाले एप्लाई करेंगे उनमे हम यह देखेंगे कि उनकी मांग क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, अगर डिमाण्ड और स्ट्रक्चर ठीक है तो उसके बाद उसे कन्सीडर कर लिया जाएगा।

श्री नफे सिंह राठी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत सरकारी कॉलेजों में भी इस किस्म के कोर्सिज शुरू करवाए जा सकेंगे ?

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि सरकारी कॉलेजों में भी ऐसे कोर्सिज शुरू करवाए जा सकते हैं और कई जगह पर हमने ऐसे कोर्सिज चालू भी कर रखे हैं।

प्रो0 राम भगत : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े फख्र की बात है कि हरियाणा सरकार ने प्राईवेट संस्थाओं में जॉब ओरिऐन्टिड आई०टी० डिप्लोमाज़ और डिग्रीयां दी हैं लेकिन आए दिन यह शिकायतें मिलती हैं कि प्राईवेट इन्स्टीच्यूट्स में जो कोर्सिज चल रहे हैं उनमें डोनेशन के नाम पर गरीब मां-बाप से बहुत ज्यादा राशि ली जाती है। उन संस्थाओं ने अच्छा-खासा धन्धा चला रखा है। क्या सरकार उन गरीब युवकों के बारे में कुछ सोच रही है जो गरीबी के कारण उन संस्थाओं में ऐडमीशन नहीं ले सकते हैं ? अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि संस्थाओं में कोर्सिज शुरू कर दिए। (विघ्न) इन संस्थाओं में जहां हमने आई ०टी० से रिलेटिड डिप्लोमाज़ और डिग्रीज़, टैक्नोलोजी से रिलेटिड कोर्सिज शुरू किए हैं क्या वहां पर यह सुनिश्चित किया है कि वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं तथा पूरा क्वालीफाईड स्टाफ है या नहीं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम भगत जी, आप सिर्फ प्रश्न पूछें।

प्रो0 राम भगत : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो दो बातें पूछी है मंत्री जी उन्हीं का जवाब दे दें।

चौ0 बहादुर सिंह : स्पीकर सर, हम इन्सपैक्शन करवाते हैं और पहले सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर देखकर ही कोर्सिज शुरू करते हैं। यू०जी०सी० की टीम भी आती है वह भी इन्सपैक्शन करती है और हमें रिपोर्ट देती है उसके बाद कॉलेज में कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी जाती है। बाकी जो माननीय साथी कह रहे हैं कि डोनेशन ली जाती है तो उस बारे में हमारे पास कोई कम्प्लेंट नहीं आई है अगर कोई कम्प्लेंट आएगी तो उस पर भी इन्क्वायरी करवाकर गौर किया जाएगा।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो इन्होंने परमिशन से जॉब ओरिएंटिड कोर्सिज की ग्रांट दी है यह किस आधार पर दी है ? इस बारे में कितने कोलेजिज ने परमिशन मांगी थी और कितनों को परमिशन दे दी गई थी तथा जिनको परमिशन दी गई थी वह किस आधार पर दी गई थी ?

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने परमिशन मांगी थी उनके बारे में इन्सपैक्शन करवाई जाती है। उसके बाद यू० जी० सी० की टीम भी आती है और उस बारे में इन्सपैक्शन करके अपनी रिपोर्ट हमें देती है। जिनके पास पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है, स्टुडैंटस की संख्या ठीक होती है, जो भी कालेजिज डिजर्व करते हैं उन सबको हम कंसीडर करते हैं और परमिशन देते हैं।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म कॉलेज, पलवल की तरफ से भी ऐसा कोई प्रार्थना पत्र आया है और अगर आया है तो उस पर क्या अपेक्षित कार्यवाही की गई है ? अगर कोई कार्यवाही नहीं की है तो उसके क्या कारण हैं?

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में रिकार्ड में देखकर इनको बता दिया जाएगा कि सनातन धर्म कॉलेज, पलवल की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र आया है या नहीं आया है अगर कोई प्रार्थना पत्र आया है तो ये चैम्बर में आकर मेरे से पता कर लें। मैं वहां पर इनको सारी बात बता दूंगा।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी कॉलेजिज हैं ये सब ग्रान्टिड हैं, सबको सरकार की तरफ से एड मिलती है। क्या इन सभी कॉलेजिज में उनकी मर्जी से फीस लगती है या इसमें कोई प्रतिशतता तय कर रखी है कि इतने प्रतिशत साधारण कैटेगरी का कोटा है और इतने प्रतिशत रिजर्व कैटेगरी का कोटा है ? अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आज की सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दे रही है तो क्या उनके लिए फीस में कोई कमी है या नहीं है अथवा उनके लिए कोई और रियायत दी जा रही है? अध्यक्ष महोदय, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के बच्चों के लिए कोई खास किस्म की रियायत है कि नहीं है इस बारे में भी मंत्री जी बताने का कष्ट करें।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 50 प्रतिशत सीटें साधारण फीस वाले बच्चों की हैं। लड़कियों के लिए फ्री कोर्स है और गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चों के लिए फीस में 50 प्रतिशत की छूट है।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने कॉलेजों और स्कूलों में कम्प्यूटर लगाए हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हरिजन और बैकवर्ड लोग बहुत गरीब होते हैं और वे लोग मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसा इक्ट्ठा करते हैं। हमारी सरकार ने उन गरीब बच्चों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया है। उनके बच्चे उन कोर्सिज की फीस नहीं भर पाए जिसके कारण उनके नाम कटने जा रहे हैं। इसने इसके लिए वहां पर धरने भी दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी उन गरीबों के बच्चों के लिए कोई आरक्षण और फीस में छूट देने का कष्ट करेंगे?

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल कंसर्न्ड प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन मैं इनको फिर भी इसका जवाब दे देता हूं कि हरियाणा में हरिजन बच्चों को कम्प्यूटर कोर्सिज के लिए पचास फीसदी की छूट फीस में दे रखी है।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि फीस कितनी है, फीस का 50 फीसदी कितना बनता है। वह गरीब आदमी 50 फीसदी फीस भी भर सकता है कि नहीं भर सकता है। इस बारे में भी आप देखें। अगर 10,000 रुपए फीस है तो उसका 50 फीसदी 5000 रुपए होगा। तो आप ही बताएं कि क्या यह गरीब आदमी 5000 रुपए दे सकेगा?

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने हरिजन का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं आया जो यह कहता हो कि मेरी फीस ज्यादा है मैं फीस नहीं दे सकता हूं। आज हरियाणा में हरिजनों की स्थिति ऐसी नहीं है जो चालीस रुपए की फीस भी न भर सकें । हमारे यहां पर 80 रुपए की फीस है और उसका 50 फीसदी 40 रुपए बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, स्कूलों के अन्दर हमारे पास हरिजनों के बच्चों की संख्या काफी है जोकि कम्पयूटर सीखना चाहते हैं।

श्री राम किशन फौजी : * * * * *

श्री अध्यक्ष : राम किशन जी जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि कम्पयूटर एजुकेशन स्कूलों और कॉलेजों में दी जा रही है। यह शिक्षा शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री महोदय ने सभी स्टेट्स से रिकार्ड मंगवाए कि कहां कहां कम्पयूटर एजुकेशन की क्या पॉलिसी है। साऊथ से और पंजाब से भी कम्पयूटर एजुकेशन की पॉलिसी मंगवाई गई थी। उन पॉलिसीज को देखने के बाद यह पाया गया कि किसी भी कैंडिडेट को कोई कन्सैशन नहीं था। हमने हमारे साथ के स्टेट पंजाब की पॉलिसी भी मंगवाई थी और वहां पर कम्पयूटर की फीस 80/-रुपए थी और किसी भी कैटेगरी को किसी भी किस्म का कन्सैशन नहीं था और जो कोर्स था वह साल में 50 घंटे ही करवाया जाता था। हमने भी अपने यहां पर फीस 80/- रुपए रखी है और कम्पयूटर कोर्स के साल में 50 घंटे को अपग्रेड करके 90 घंटे किया है। हमने डबल समय उसी फीस में दिया है और 50 प्रतिशत फीस में छूट रिजर्व कैटेगरी को दी है। मंत्री जी ने 40/- रुपए वाली जो बात कही है वह बिल्कुल उचित बात कही है कि हमारे सामने फीस के बारे में दिक्कत लेकर कोई नहीं आया है और कोई आ भी नहीं सकता है। स्पीकर सर, पिछली सरकार के वक्त योजना निर्माण निगम के पास पैसे जमा करवा कर फिक्स डिपोजिट करवा दिया जाता था और उसके ब्याज को तनख्वाह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने चार मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी और मुझे उस कमेटी की अध्यक्षता करने का मौका मिला था। उस कमेटी के तहत 7 करोड़ रुपये हरिजनों को पढ़ाने के लिए, उनको स्कॉलरशिप देने के लिए और उनको होस्टल फैसिलिटी देने के लिए, उनको डाईट देने के लिए और उनको जॉब्स के लिए अपोरचुनिटी क्रिएट करने के लिए दिया है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा रिकार्ड आपको हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा जैसा कि आज की हरियाणा सरकार ने किया है।

Strengthening of Distance Education

***861 Sh. Bhagi Ram** : Will the Minister of State for Education be pleased to state: whether any policy has been formulated by the Government for strengthening of Distance Education in the State; if so, the details thereof ?

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) : हां, श्री मान् जी। सम्बद्ध विवरण सदन के पटल पर रखे जाते हैं।

विवरण

राज्य में दूरस्थ शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के विवरण

राज्य शिक्षा नीति-2000 में उपबन्ध किया गया है कि :—

"शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने तथा नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में असमर्थ लोगों को घर द्वार पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मुक्त शिक्षा/दूरस्थ शिक्षा को सुदृढ़ किया जायेगा।"

इसको ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तथा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा दूरस्थ शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु कई कदम उठाये गये हैं तथा कई नये पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा उठाये गये कदम

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने दूरस्थ शिक्षा को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार किये हैं।

पिछले दो वर्षों में पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय में आरम्भ किये गये पाठ्यक्रम निम्न अनुसार हैं :—

1. सत्र 2000-2001 के दौरान आरम्भ किये गये पाठ्यक्रम :

1.	एम0एस0सी0 सॉफ्टवेयर (ऑन लाईन)	— दो वर्षीय
2.	सॉफ्टवेयर (ऑन लाईन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	— एक वर्षीय
3.	सूचना प्रणाली में बी0एस0सी0	— तीन वर्षीय
4.	अन्तरताने विज्ञान में बी0एस0सी0	— तीन वर्षीय
5.	सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	— एक वर्षीय
6.	ई — कामर्स में डिप्लोमा	— एक वर्षीय
7.	मानव संसाधन प्रबन्धन में स्नातकोत्तर	— दो वर्षीय
8.	मानव संसाधन प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	— एक वर्षीय
9.	कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं नेटवर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	— एक वर्षीय

2. सत्र 2001-2002 के दौरान आरम्भ किये गये पाठ्यक्रम :

1.	जनसंचार में स्नातकोत्तर	— एक वर्षीय
2.	एम0ए0/एम0एस0सी0 भूगोल	— दो वर्षीय
3.	एम0एस0सी0 कम्प्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर)	— दो वर्षीय

4. कम्प्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा — एक वर्षीय
5. कम्प्यूटर शिक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा — एक वर्षीय
6. स्वत्वाधिकार, पेटेंट एवं साईबर कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा — एक वर्षीय
7. व्यापार कानून एवं अभ्यास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा — एक वर्षीय

आगामी सत्र 2002-2003 से निम्नलिखित पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है :—

1. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर — तीन वर्षीय
2. व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर — तीन वर्षीय
3. बीमा व्यापार प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा — एक वर्षीय

इस समय 82 कक्षाओं में 54 एक वर्षीय/दो वर्षीय/तीन वर्षीय पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें प्रबन्धन, वित्त, विपणन, पर्यटन, होटल, पत्रकारिता, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान आदि क्षेत्र के व्यावसायिक पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं।

सभी छात्रों को सम्बद्ध अध्ययन सामग्री सप्लाई की जाती है। अध्ययन सामग्री के माध्यम से शिक्षा को वरिष्ठ अनुभवी पाठ्यक्रम समन्वयकों द्वारा अनिवार्य व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम से अनुपूरित किया जाता है।

इसके परिणामस्वरूप, पत्राचार पाठ्यक्रम के छात्रों के अच्छे परिणाम रहे हैं तथा उन्होंने विश्वविद्यालय परीक्षाओं में ऊंची मैरिट स्थिति प्राप्त करके श्रेष्ठता प्राप्त की है।

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा उठाये गये कदम

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक स्नातक स्तर तक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के दूरस्थ शिक्षुओं को शिक्षा प्रदान कर रहा है।

शैक्षणिक सत्र 2001-2002 के दौरान महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम आरम्भ किये गए हैं :—

1. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
2. सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
3. एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अर्द्धवार्षिक पाठ्यक्रम-I
4. एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अर्द्धवार्षिक पाठ्यक्रम-III
5. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक

दूरस्थ शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न अध्यापनक / अध्ययन रणनीतियां तैयार की गई

[चौ० बहादुर सिंह]

हैं। सम्पर्क कार्यक्रमों तथा निर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त स्वयं शिक्षा सामग्री शिक्षा स्नातक तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रमों के दूरस्थ शिक्षुओं के शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। स्नातक स्तर तक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मामले में अधिकांश सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में अध्ययन केन्द्र खोले गए हैं। कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय नॉर्म के अनुसार पूरे भारत में सुसज्जित पुस्तकालय एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से अतिरिक्त अध्ययन सामग्री वेबसाइट www. mduonline. org के माध्यम से भी प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दूरस्थ शिक्षुओं को निदेशालय के अपने शिक्षकों द्वारा भी परामर्श दिया जाता है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या राज्य में दूरस्थ शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है, यदि बनाई गई है तो उसका क्या ब्यौरा है ? मंत्री जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में अलग से बताएं और 2001-2002 के दौरान कौन-कौन से पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं और 2002-2003 के दौरान कौन-कौन से पाठ्यक्रम शुरू करेंगे ? इसके अलावा रोहतक कालेज में भी क्या कदम उठाए गए हैं उनके बारे में अलग से बताएं।

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि राज्य शिक्षा नीति-2000 में उपबन्ध किया गया है कि :—

"शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने तथा नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में असमर्थ लोगों को घर द्वार पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मुक्त शिक्षा/दूरस्थ शिक्षा को सुदृढ़ किया जायेगा।"

इसको ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तथा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा दूरस्थ शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु कई कदम उठाये गये हैं तथा कई नये पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा उठाये गये कदम

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने दूरस्थ शिक्षा को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार किये हैं।

पिछले दो वर्षों में पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय में आरम्भ किये गये पाठ्यक्रम निम्न अनुसार हैं :—

1. सत्र 2000-2001 के दौरान आरम्भ किये गये पाठ्यक्रम

1. एम0एस0सी0 सॉफ्टवेयर (ऑन लाईन) — दो वर्षीय
2. सॉफ्टवेयर (ऑन लाईन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा — एक वर्षीय
3. सूचना प्रणाली में बी0एस0सी0 — तीन वर्षीय
4. अन्तरताने विज्ञान में बी0एस0सी0 — तीन वर्षीय

5. सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा — एक वर्षीय
6. ई — कामर्स में डिप्लोमा — एक वर्षीय
7. मानव संसाधन प्रबन्धन में स्नातकोत्तर — दो वर्षीय
8. मानव संसाधन प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा — एक वर्षीय
9. कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं नेटवर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा — एक वर्षीय

2. सत्र 2001-2002 के दौरान आरम्भ किये गये पाठ्यक्रम

1. जनसंचार में स्नातकोत्तर — एक वर्षीय
2. एम0ए0/एम0एस0सी0 भूगोल — दो वर्षीय
3. एम0एस0सी0 कम्प्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर) — दो वर्षीय
4. कम्प्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा — एक वर्षीय
5. कम्प्यूटर शिक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा — एक वर्षीय
6. स्वत्वाधिकार, पेटेंट एवं साईबर कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा — एक वर्षीय
7. व्यापार कानून एवं अभ्यास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा — एक वर्षीय

आगामी सत्र 2002-2003 से निम्नलिखित पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है :—

1. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर — तीन वर्षीय
2. व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर — तीन वर्षीय
3. बीमा व्यापार प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा — एक वर्षीय

इस समय 82 कक्षाओं में 54 एक वर्षीय/दो वर्षीय/तीन वर्षीय पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें प्रबन्धन, वित्त, विपणन, पर्यटन, होटल, पत्रकारिता, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान आदि क्षेत्र के व्यावसायिक पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं।

सभी छात्रों को सम्बद्ध अध्ययन सामग्री सप्लाई की जाती है। अध्ययन सामग्री के माध्यम से शिक्षा को वरिष्ठ अनुभवी पाठ्यक्रम समन्वयकों द्वारा अनिवार्य व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम से अनुपूरित किया जाता है।

इसके परिणामस्वरूप, पत्राचार पाठ्यक्रम के छात्रों के अच्छे परिणाम रहे हैं तथा उन्होंने विश्वविद्यालय परीक्षाओं में ऊंची मैरिट स्थिति प्राप्त करके श्रेष्ठता प्राप्त की है।

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा उठाये गये कदम

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक स्नातक स्तर तक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के दूरस्थ शिक्षुओं को शिक्षा प्रदान कर रहा है।

[चौ0 बहादुर सिंह]

शैक्षणिक सत्र 2001-2002 के दौरान महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम आरम्भ किये गए हैं :—

1. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
2. सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
3. एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अर्द्धवार्षिक पाठ्यक्रम-I
4. एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अर्द्धवार्षिक पाठ्यक्रम-III
5. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक

दूरस्थ शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न अध्यापनक / अध्ययन रणनीतियां तैयार की गई हैं। सम्पर्क कार्यक्रमों तथा निर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त स्वयं शिक्षा सामग्री शिक्षा स्नातक तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रमों के दूरस्थ शिक्षुओं के शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। स्नातक स्तर तक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मामले में अधिकांश सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में अध्ययन केन्द्र खोले गए हैं। कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय नॉर्म के अनुसार पूरे भारत में सुसज्जित पुस्तकालय एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से अतिरिक्त अध्ययन सामग्री वेबसाइट www. mduonline. org के माध्यम से भी प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दूरस्थ शिक्षुओं को निदेशालय के अपने शिक्षकों द्वारा भी परामर्श दिया जाता है।

Recognition of Private Aided Schools

***880 Sh. Jasbir Mallour** : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether the Government Aided Private Schools which fulfill the norms have been given permanently or temporarily recognition in the State. If so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) : जी हां, सभी सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय स्थाई तौर पर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं।

इस समय राज्य में 236 निजी स्कूल दसवीं कक्षा तक तथा 171 प्राथमिक निजी स्कूल सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

श्री जसबीर मलौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला अम्बाला में ऐसे कितने निजी विद्यालय हैं जो सरकारी सहायता व अनुदान प्राप्त हैं और नॉर्म्स पूरे करते हैं और जिनको स्थाई या अस्थाई आधार पर मान्यता प्राप्त है उनकी संख्या कितनी है ?

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को संख्या तो जनरली बता दी जाएगी कि कितने स्कूल हैं जो नॉर्म्स पूरा करते हैं। जितने गवर्नमैंट ऐडिड स्कूल हैं सबको मान्यता प्राप्त है ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो गवर्नमैंट ऐडिड हो और मान्यता प्राप्त न हो।

श्री जसबीर मलौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गवर्नमैंट ऐडिड स्कूल हैं उनके लिए मान्यता प्राप्त करने के क्या नॉर्म्ज रखे गए हैं ?

चौ0 बहादुर सिंह : नॉर्म्ज ऐसे हैं जिनके तहत इतने कमरे होने चाहिए, इतनी जमीन होनी चाहिए। जो गवर्नमैंट ऐडिड स्कूल सारे नॉर्म्ज पूरे करते थे उनको ही मान्यता दी गई है गवर्नमैंट एडिड स्कूल जब मान्यता प्राप्त करने के लिए एप्लाई करेंगे उसके बाद यह देखा जाएगा कि कौन सा ऐसा स्कूल है जो मान्यता के काबिल है या काबिल नहीं है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गवर्नमैंट ऐडिड प्राइवेट स्कूल हैं सरकार उनको ग्रान्ट देती है क्या सरकार ऐसी कोई जांच भी करवाती है कि इन स्कूलों द्वारा जो ग्रान्ट ली जाती है उससे वहां के अध्यापकों को समय पर तनख्वाह दे दी जाती है ? जैसे अभी पहले प्रश्न में भी बात उठी थी कि लड़कियों के लिए 8/- रुपये या 20/- रुपये फीस तय है लेकिन किसी भी स्कूल में इतनी फीस नहीं ली जाती है उससे कई गुणा ज्यादा फीस ली जाती है क्या सरकार की तरफ से ऐसे तमाम स्कूलों की कोई जांच कराई जाएगी जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं ?

चौ0 बहादुर सिंह : जो सरकार के नियमों की पालना नहीं करते हैं उनके खिलाफ जांच भी करायेंगे और कार्रवाई भी करेंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जितने भी गवर्नमैंट ऐडिड स्कूल हैं क्या शिक्षा मंत्री जी उन सब स्कूलों के बारे में जांच करवायेंगे कि वहां पर सरकारी स्कूलों से कहीं ज्यादा फीस ली जाती है जबकि सरकार उन स्कूलों को 80 से 100 प्रतिशत तक की ऐड देती है। उन प्राईवेट स्कूलों की मैनेजमैंट अपनी मनमानी करती है और बच्चों को कोई फैसेलिटी नहीं देती हैं।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप कोई स्पैसिफिक स्कूल के बारे में शिक्षा मंत्री जी को लिखकर दे दें उसके बाद वे जांच करा सकते हैं और उनके खिलाफ ऐक्शन भी ले सकते हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे सभी प्राईवेट स्कूलों की जांच करायेंगे क्योंकि प्राईवेट स्कूल समय पर अपने अध्यापकों को तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं ? जबकि सरकार उन स्कूलों को ऐड देती है इसलिए सरकार की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हम समय समय पर डी0ई0ओ0 के माध्यम से इन स्कूलों की जांच भी कराते हैं, इंस्पैक्शन भी कराते हैं और हर साल इन स्कूलों का आडिट भी होता है। अगर माननीय साथी को कोई ऐसा इंस्टांस मालूम है तो वे लिखकर दे दें हम उस पर्टीकुलर स्कूल की बाकायदा जांच भी करायेंगे और अगर कोई त्रुटि पाई गई तो उसके खिलाफ ऐक्शन भी लेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, जितने भी गवर्नमैंट ऐडिड प्राईवेट स्कूल हरियाणा में चल रहे हैं वे अधिकतर शहरों में चल रहे हैं और जब देहात का कोई मैरीटोरियस बच्चा इन स्कूलों में दाखिला लेना चाहता है तो उसको इसलिए दाखिला नहीं मिल पाता क्योंकि वह महंगी ड्रैस नहीं पहन सकता और महंगा जूता नहीं पहन सकता। वहां पर पैसे वाले परिवारों

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

के बच्चों को दाखिला दिया जाता है। इसलिए इन स्कूलों में देहात के और गरीब परिवार के बच्चों के साथ बड़ा भारी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और रिजेंटमेंट हो रहा है। गांवों के किसान के बच्चे, गरीब मजदूरों के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं परन्तु उनको दाखिला न देकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन स्कूलों में ऐसी डिस्क्रिमिनेशन चल रही है क्या वे इन स्कूलों की रिकोग्निशन को रद्द करेंगे ?

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी स्कूल के बारे में हमें कोई इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उस के बारे में हम जांच भी करायेंगे और एक्शन भी लेंगे।

श्रीमती वीना छिब्बर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि प्राईवेट स्कूलों में मैनेजमैंट अपने मन माने ढंग से दाखिला करती है और एक विधायक की वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती जबकि इन स्कूलों को सरकार की तरफ से 90 प्रतिशत के लगभग ऐड मिलती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहती हूं कि वे कोई इस प्रकार का प्रोविजन करें कि एक स्थानीय विधायक की सुनवाई इन स्कूलों में हो सके (हंसी) इस बात को हंसी में टालने की बात नहीं है यह एक सीरियस मामला है जिसका कोई न कोई हल होना चाहिये।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम इंस्ट्रक्शंज जारी कर देंगे उसके बाद इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं रह जायेगी अगर उसके बाद भी कोई स्कूल सरकार के निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

Investment made by Harco Bank

*972 **Sh. Nafe Singh Rathi** : Will the Minister for Co-operation be pleased to state whether the Haryana State Co-operative Bank (HARCO BANK) has made any investment in Trust Bond Series-C of Housing Development Finance Corporation in the month of May-June-1991; if so, the amount thereof ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भडाना) : हां, श्रीमान जी, हरको बैंक ने मई और जून, 1991 में प्रत्येक बार एक करोड़ रुपये गृह विकास वित्त निगम की ट्रस्ट बॉन्ड सीरीज़-सी में निवेश किये थे।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि किसी प्राईवेट एजैंसी के पास हरियाणा सरकार के दो करोड़ रुपये जमा हुये और हरियाणा सरकार को उसका आर्थिक नुकसान हुआ ? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उस एजैंसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई और क्या सरकार इस राशि को ब्याज समेत वसूल करेगी ?

श्री करतार सिंह भडाना : स्पीकर सर, यह ठीक है कि यह राशि मई, जून, 1991 में दो करोड़ की दी गई थी और आवासीय विकास वित्त निगम ने इसका निवेश किया था। यह राशि बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत जमा की गई थी क्योंकि इस एक्ट के तहत बैंक डिपोजिट राशि का 25 प्रतिशत किसी मान्यता प्राप्त ट्रस्ट द्वारा प्रतिभूति जमा करवाना अनिवार्य होता है। इस राशि को वसूल करने के बारे में हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। इस मामले में दीवानी मुकदमा चलाया

जा रहा है। और इस पैसे को वसूल कर लिया जायेगा। क्योंकि पैसा डिपोजिट करवाने से सम्बंधित अधिकारी की डैथ हो चुकी है अब दलाल फर्मों के विरुद्ध दीवानी मुकदमा चल रहा है उसका जो भी निर्णय होगा वह सामने आएगा।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, एक वरिष्ठ आई0ए0एस0 अधिकारी के परिवार की एक कम्पनी थी जिसका नाम शरण एण्ड कम्पनी था। उसके माध्यम से वह पैसा जमा हुआ यदि हरको बैंक के माध्यम से पैसा जमा होता तो कई लाख रुपये का हरको बैंक को लाभ होता। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई क्रिमिनल केस दर्ज करवाया गया है ?

श्री करतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इसके कंसर्ड के खिलाफ क्रिमिनल केस जे0एम0 प्रथम श्रेणी यू0टी0, चण्डीगढ़ की अदालत में दर्ज करवा दिया गया है।

Storage Capacity

*935 **Sh. Nafe Singh Jundla** : Will the Minister for Co-operation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government (HAFED) to increase storage capacity; if so, the details thereof ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) : हां, श्रीमान जी। हैफेड ने राज्य में भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया हुआ है। वर्ष 2001-2002 (फरवरी, 2002 तक), हैफेड ने अपने गोदामों और प्लिंथों का निर्माण करके 2,53,500 टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता बढ़ा दी है। आगामी दो महीनों में भंडारण क्षमता 3,24,200 टन और बढ़ा दी जाएगी।

श्री नफे सिंह जुंडला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के किसान को मौजूदा सरकार ने मुख्यमंत्री जी के अनथक प्रयासों से जिस तरह से बिजली मुहैया करवाई है और नहरों का पानी टेल तक पहुंचाया है उसकी वजह से गेहूं और जीरी का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। रिकार्ड उत्पादन होने की वजह से हमें अनाज के रख-रखाव और उसके भण्डारण करने में समस्या आई है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस समस्या का समाधान करने के बारे में कहां-कहां गोदाम बनाए गए हैं और जिस तरह से दर्शाया गया है कि 2 लाख 53 हजार 500 टन भण्डारण क्षमता बढ़ाई तो गई है इस क्षमता को बढ़ाने पर क्या लागत आई है तथा 3 लाख 24 हजार 200 टन भण्डारण क्षमता जो आगे बढ़ाने जा रहे हैं उसमें क्या लागत आएगी ?

श्री करतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि 2 लाख 53 हजार 500 टन भण्डारण क्षमता बढ़ा दी गई है और 3 लाख 24 हजार 200 टन भण्डारण क्षमता बढ़ा दी जाएगी। हैफेड प्राइवेट पार्टियों से भी 7 साल की गारंटी योजना के तहत गोदामों का निर्माण करा रहा है। वर्ष 2001-2002 में बनाए जा रहे इन गोदामों की क्षमता 2 लाख 65 हजार टन होगी। प्राइवेट पार्टियों से भी गोदाम बनवाए गए हैं इस प्रकार हैफेड के पास कुल मिलाकर 9 लाख 80 हजार 952 टन की भण्डारण क्षमता के गोदाम होंगे। वर्ष 2001-2002 में एक लाख 15 हजार 500 टन भण्डारण क्षमता के प्लिंथों का निर्माण किया गया था। आगामी वर्ष में एक लाख 18 हजार टन भण्डारण क्षमता के प्लिंथों का निर्माण किया जाएगा। 31 मार्च, 2000 तक पहले ही 4 लाख 36 हजार 665 टन भण्डारण क्षमता के गोदामों का निर्माण किया गया है। इस प्रकार हैफेड के प्लिंथों की अपनी भण्डारण क्षमता बढ़कर 6 लाख 70 हजार

[श्री करतार सिंह भडाना]

865 टन हो जाएगी। जो 2.53 लाख टन की भण्डारण क्षमता बढ़ाई जा चुकी है उस पर 27.23 करोड़ रुपये लागत आई और 3,24,200 टन की भण्डारण क्षमता जो निकट भविष्य में बढ़ाने जा रहे हैं उस पर 26.32 करोड़ रुपये का खर्चा अनुमानित है। अब तक झांसी, सक्लाखेड़ा, रोहतक, रिवाड़ी, पिपली, पेहवा, कैथल, नीलोखेड़ी, नावेल, सफीदों, जाखल, कालांवाली और जीन्द में गोदाम बन कर तैयार हो चुके हैं।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हिसार जिले की रिपोर्ट आनी थी कि बरसात के अंदर कितना अनाज डैमेज हुआ और उस डैमेज्ड स्टॉक का क्या किया गया तथा आगे से इस तरह अनाज डैमेज न हो उसके लिए क्या प्रबंध किए गये हैं ?

श्री करतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि अब हमने अनाज के रख रखाव के लिए जितने भी गोदाम चाहिए थे उनका प्रबंध कर लिया है। पहले हम गेहूं को बाहर रख देते थे और गोदामों में चावल रख देते थे जिसके कारण गेहूं खराब हो जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : आदरणीय सदस्यगण, अब क्वैश्चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Number of Beneficiaries under Old Age Pension

*991 **Sh. Ram Kuwar** : Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state the total number of beneficiaries under 'Old Age Pension Scheme' in the State as at present; togetherwith the details of the amount spent annually for the disbursement of the said pension ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री रिसाल सिंह) : वृद्धावस्था पैंशन योजना के अन्तर्गत लाभपात्रों की संख्या बारे उत्तर अनुबन्ध "क" पर है।

अनुबन्ध "क"

वर्ष	लाभपात्रों की संख्या	खर्च राशि (रु0 करोड़ों में)
1	2	3
1991-92	7,40,000	60.18
1992-93	7,37,000	71.33
1993-94	6,79,255	54.36
1994-95	6,30,000	114.22
1995-96	7,41,290	80.14
1996-97	6,96,000	83.88

1	2	3
1997-98	7,29,600	81.82
1998-99	6,80,263	82.88
1999-2000	9,93,000	124.16
2000-2001	9,67,000	221.35
2001-2002 (31-1-2002 तक)	9,24,741	187.62

Construction of Roads

***921 Sh. Dan Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the roads from village Bawania to Jhangroli Via Bachini and from Mahendergarh to Kanina, District Mahendergarh; and

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be constructed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं श्रीमान् जी, ये सड़कें पहले से ही निर्मित हैं।

(ख) उपरोक्त "क" पर उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

Kisan Credit Card

***943 Shri Hamid Hussain** :

Shri Ranbir Singh : Will the Minister for Co-operation be pleased to state the number of farmers to whom Kisan Credit Cards have been issued by the Co-operative Bank in the State ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) : हरियाणा राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने 31-1-2002 तक 6,34,811 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये हैं।

Upgradation of Sub-Yard, Hathin

***933 Shri Bhagwan Sahai Rawat** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Sub-Mandi/Sub-Yard, Hathin to the status of Grain Market ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : हां, श्रीमान् जी।

Setting up of Rice Mill at Fatehabad

*995 **Smt. Vidya Baniwal** : Will the Minister for Co-operation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Rice Mill by HAFED at Fatehabad; and

(b) if so, the time by "which the above said Mill is likely to be set up ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) फतेहाबाद में चावल मिल स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के पश्चात नौ महीनों के भीतर यह चावल मिल स्थापित कर दी जाएगी।

Improvemnet of Road Safety

*981 **Shri Suraj Mal** : Will the Minister for Transport be pleased to state the steps taken so far, or proposed to be taken to improve the road safety on National Highways in the State ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : विधान सभा सदन के पटल पर एक तालिका रखी गई है।

तालिका

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(क) राज्य से गुजरने वाले मुख्य चार राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व परिवहन के सुचारू पर्यवेक्षण एवं प्रबन्धन के उद्देश्य से परिवहन विभाग, हरियाणा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में हरियाणा हाईवे पैट्रोल एवं सड़क सुरक्षा के नाम से एक संगठन की स्थापना की गई है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 8 व 10 पर लगभग हर तीस किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। यह यातायात सहायता केन्द्र यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहनों की चैकिंग के अतिरिक्त दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को कम से कम समय में सहायता पहुंचाते हैं तथा सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए मार्ग को साफ करने में सहायता करते हैं। प्रत्येक यातायात सहायता केन्द्र पर आवश्यक ढांचागत सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं जैसा कि जिप्सी, मोटर साईकिल, रिकवरी क्रेन, संचार यन्त्र, पैरा मैडिकल स्टॉफ सहित एम्बुलैंस तथा स्पीड राडार व एलको मीटर इत्यादि।

(ख) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक "हरियाणा सड़क सुरक्षा कमेटी" का गठन किया गया है जो सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में तालमेल स्थापित करने का काम कर रही है। कमेटी द्वारा अभी तक लगभग 50 मुद्दों की पहचान की गई है जिनमें चरणबद्ध तरीके से सुधार लाया जा रहा है।

(ग) मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत कई अधिसूचनायें/निर्देश जारी किये गये हैं जिनमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न वाहनों की गति सीमा को निर्धारित करना, दो पहिया वाहनों के चालक व पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हैल्मेट पहनना अनिवार्य करना, मोटर वाहन के चालक व सामने की सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बैल्ट लगाना अनिवार्य करना आदि शामिल हैं। सभी इनफोर्समैंट इकाइयां जैसे कि एस0एस0पी0 (हरियाणा हाईवे पैट्रोल व सड़क सुरक्षा), जिला पुलिस व जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यातायात सम्बन्धी प्रावधानों तथा कानून के अन्य प्रावधानों को सख्ती से लागू करें। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि केवल बन्द बॉडी मैक्सी कैबस को परिचालन की अनुमति दी जावेगी।

(घ) एस0एस0पी0 (हरियाणा हाईवे पैट्रोल व सड़क सुरक्षा), व जिला परिवहन अधिकारियों के अतिरिक्त सड़क सुरक्षा नियमों तथा अन्य कानूनों को लागू करने हेतु राज्य में सभी उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों, उपमण्डल अधिकारियों (ना) तथा नगराधीशों को भी कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं।

Setting up of Mustard Oil Mill at Narnaul

***980 Shri Moola Ram** : Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up Mustard Oil Mill at Narnaul; if so, the time by which the above said Mill is likely to be set up ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भडाना) : हां, श्रीमान् जी। हैफेड द्वारा नारनौल में सरसों के तेल की मिल की स्थापना प्रस्तावित है। यह तेल मिल सितम्बर, 2002 से पहले पूरी हो जाने की सम्भावना है।

Indira Awaas Yojana

***944 Shri Ram Phal Kundu,** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the detail of amount allocated under Indira Awaas Yojana during the current financial year 2001-2002 together-with the amount spent so far for the construction/repair of houses therefrom separately ; and

(b) the district-wise number of houses constructed/repaired under the scheme referred to in part (a) above during the said period ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत नव निर्माण के लिए 1222.550 लाख रुपये तथा मकानों के सुधारीकरण के लिए 305.640 लाख रुपये

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

की राशि आबंटित की गई थी। इसके विरुद्ध जनवरी, 2002 के अन्त तक नव निर्माण के लिए 812.20 लाख रुपये तथा सुधारीकरण के लिए 191.40 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ख) एक विवरणी सदन की मेज पर रखी जाती है।

विवरणी

क्रम संख्या	जिले का नाम	निर्मित किये गये मकानों की संख्या	मरम्मत किये गये मकानों की संख्या
1	अम्बाला	290	144
2	भिवानी	303	116
3	फरीदाबाद	361	196
4	फतेहाबाद	62	31
5	गुड़गांव	326	143
6	हिसार	255	104
7	झज्जर	49	26
8	जीन्द	180	110
9	कैथल	163	74
10	करनाल	228	139
11	कुरुक्षेत्र	171	137
12	महेन्द्रगढ़	102	39
13	पंचकूला	30	11
14	पानीपत	156	85
15	रिवाड़ी	171	50
16	रोहतक	174	91
17	सिरसा	323	88
18	सोनीपत	153	76
19	यमुनानगर	343	170
	कुल	**3840**	**1830**

Construction of Grain and Vegetable Market at Helimandi

***960. Shri Ram Bir Singh :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to costruct a new Grain and Vegetable Market in Helimandi; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : हेलीमण्डी में नई अनाज मण्डी बनाने बारे प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच चल रही है। अत : इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

Auction of Shops of Grain Market, Jhajjar

***998. Shri Daryo Singh, :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the time by which the Shops of Grain Market, Jhajjar are likely to be auctioned ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : इस समय कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि संशोधित योजना के अनुसार झज्जर में अनाज मण्डी बनाने के लिए हुड्डा द्वारा मार्किट कमेटी, झज्जर को भूमि अभी स्थानान्तरित की जानी है।

Construction of Additional Water Tank

***947. Shri Shadi Lal Batra :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the present capacity of water works of Rohtak City is not sufficient ; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct additional water tank in the aforesaid water works ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : क तथा ख. रोहतक शहर के जल घर में एक अतिरिक्त पानी के टैंक के निर्माण के लिए सरकार द्वारा पहले ही प्रयोजना स्वीकृत की जा चुकी है।

Completion of SYL

***934. Shri Bhupinder Singh Hooda, :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) Whether the State Government has taken any steps for the implemention of the verdict given by Apex Court in regard to the Construction/ Completion of the SYL Canal in the territory of Haryana and Punjab State ; and

(b) If so, details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : (क) एंव (ख) श्रीमान् जी, एक विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणी

सतलुज-यमुना सम्पर्क को पूरा करना।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15 जनवरी, 2002 के निर्णय के अनुरूप सरकार ने सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के पहले से ही निर्मित हरियाणा प्रभाग की टूट-फूट की मरम्मत हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। हरियाणा में निर्मित सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के प्रभाग की मरम्मत एंव क्षमता बहाली का कार्य पंजाब प्रभाग के पूरा होने से पूर्व ही करवा दिया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार पंजाब सरकार को निर्देश दिये गये हैं कि पंजाब प्रभाग में सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर की खुदाई का कार्य जहां पूरा नहीं हुआ, को जारी रखें और नहर को 15-1-2002 से एक वर्ष की अवधि में चालू करें। माननीय न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह भी निर्देश दिये हैं कि यदि उक्त अवधि के दौरान पंजाब सरकार यह कार्य पूरा नहीं करती तब केन्द्र सरकार उसे अपनी संस्था द्वारा यथासम्भव शीघ्रतापूर्वक पूरा करवायेगी।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Total Literacy Campaign

74. Shri Anil Vij : Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that total literacy campaign (TLC) launched in the State during the year 1991 has miserably failed to achieve the required targets; if so, the reasons thereof ; togetherwith the action, if any, taken against the officials held responsible for its failure ; and

(b) the number of women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes benefited under the said scheme ?

श्री अध्यक्ष : इस सवाल के बारे में उत्तर देने के लिए कन्सर्न्ड मिनिस्टर ने 3 महीने का समय मांगा है जो दे दिया गया है। उनका पत्र इस प्रकार से है :-

"BAHADUR SINGH

D.O. No. 2112-2002-LC(1)
Minister of State Education,
(Independent Charge)
Haryana, Chandigarh.
Dated 4-3-2002.

Subject : Unstarred 'Question No. 74 (Total Literacy Campaign) asked by Shri Anil Vij, MLA.

Respected,

Kindly refer to the subject cited above

Unstarred Question No. 74 (Total Literacy Campaign) asked by Sh. Anil Vij, M.L.A. has been fixed for 6-3-2002. Some information is still to be

collected from various Districts which is likely to take some time. It is not possible to collect the information by 6-3-2002. I, therefore, request you to allow three months extension for submitting reply.

The question is fixed for 6-3-2002.

Yours sincerely,
sd/-
(Bahadur Singh)

Shri Satbir Singh Kadian,
Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh."

Failure of Tubewells

75. **Shri Anil Vij** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the tubewells installed for providing of drinking water have been failed in large scale in the state; if so, the reasons thereof; and

(b) the number of tubewells installed/failed during the last five years togetherwith the amount spent on the installation of said tubewells ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं श्रीमान् जी।

(ख) पिछले पांच वर्षों में 1300 नए नलकूप लगाए गए जिन पर लगभग 36.63 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। इस दौरान 97 नलकूप असफल हुए जिनमें 75 नलकूप ऐसे हैं जो कि दस वर्ष से भी पहले लगाए गए थे।

Payment of salary by private colleges

76. Shri Anil Vij : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether it is a fact that a large number of employees of the Govt. Aided Schools in the State are not getting their salaries in time; if so, the names of such schools ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (चौ0 बहादुर सिंह) : निजी प्रबन्धन वाले सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी सरकार के कर्मचारी नहीं हैं अपितु प्रबन्धक समिति के कर्मचारी हैं। नियमों के अनुसार प्रबन्धक समिति पहले अपने कर्मचारियों को वेतन की अदायगी करती है तथा बाद में उसकी प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत करती है। प्रतिपूर्ति दावे अनुमन्यता तथा अधिक्य की कटौती/समंजन, यदि कोई हो, की शर्त पर सरकार द्वारा इन विद्यालयों को राशि जारी करने हेतु देय बनते हैं। इस प्रकार इन विद्यालयों को सहायता अनुदान जारी करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। आज की स्थिति के अनुसार सरकार के हिस्से का कोई बकाया लम्बित नहीं है। निधियां जारी करने हेतु वर्ष 2001-02 के दौरान प्राप्त दावे प्रक्रियाधीन हैं।

Drawing of Old Age Pension illegally

77. Shri Anil Vij : Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the old age pension is being drawn illegally by their relatives or the staff even after the death or permanent transfer of the pensioners from the State; and

(b) if so, whether any enquiry is to be conducted to find out the erring persons together with the steps to be taken to recover the said amount therefrom?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री रिसाल सिंह) : (क) तथा (ख) वृद्धावस्था पैंशन की अदायगी पैंशन नियमों के प्रावधानों अनुसार ही की जा रही है। फिर भी, यदि कोई मामला जहां पर लाभपात्र के रिश्तेदार या अमले द्वारा उसकी मृत्यु या राज्य से स्थाई स्थानान्तरण के बाद अनाधिकृत तौर पर प्राप्त की गई हो, ध्यान में आता है तो उसकी वसूली उचित जांच के बाद की जाती है तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

Setting up of Power House, Jatauli

79. Shri Ram Bir Singh, : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Power House at village Jatauli in Pataudi constituency ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : (क) एवं (ख) पटौदी निर्वाचन क्षेत्र में गांव जाटौली में एक उपकेन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्राम भोंड़ाकलां में एक नया 66 के0वी0 उपकेन्द्र निर्माणधीन है। इस उपकेन्द्र के निर्मित होने के बाद 66 के0वी0 उपकेन्द्र पटौदी का कुछ लोड इस नए उपकेन्द्र पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे ग्राम जाटौली तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों को जो पटौदी उपकेन्द्र से बिजली प्राप्त कर रहे हैं, की स्थिति में सुधार आएगा।

Construction of a New Building of C.H.C. Pataudi

***80. Shri Ram Bir Singh, :** Will the Minister of State for Health be pelased to state : whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building of Community Health Centre, Pataudi?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ0 एम0 एल0 रंगा) : जी, नहीं।

M.A. Classes

81. Sh. Ram Bir Singh. : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start the M.A. classes in Government College Heli Mandi Jatauli ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी ।

सदन में मर्यादा कायम रखना

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर सर, कल जैसे विपक्ष के लोगों का जो व्यवहार रहा आपने उनको बहुत झेला और आपने बड़ा धैर्य दिखाया। अध्यक्ष महोदय, कल की बात तो कल पर गई और जो एक्शन आपने लिया वह हाउस की सैंस से तथा हाउस की सहमति से लिया लेकिन आज भी विपक्ष के जो सदस्य आये, हमें यह कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि प्रजातंत्र का यह दुर्भाग्य है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा विपक्ष है जिसको कानूनों और नियमों का कोई ज्ञान नहीं है और न कुछ और मालूम है। ये लोग अपने आपको इतना सीनियर कहते हैं, चौधरी बंसी लाल जी यहां बैठे हैं ये मेरी बात की ताईद करेंगे। विपक्ष में एक तरफ तो पार्टी के अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैं तथा उनमें कई सदस्य ऐसे भी हैं जो कई बार विधायक बन चुके हैं और कई बार पार्लियामैंट के सदस्य भी रह चुके हैं उनको पार्लियामैंट के अंदर एम०पी० को कैसा व्यवहार करना चाहिए और असैम्बली में विधायक को कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी नहीं है लेकिन वे अपने आपको बहुत सीनियर नेता कहते हैं। स्पीकर सर, आपको मालूम ही है कि इस बारे में सैट रूल्ज हैं, अपनी असैम्बली की बुक के अंदर भी नियम हैं और पार्लियामैंट की भी प्रोसीजर बुक और रूल्ज भी हैं। स्पीकर सर, अभी कुछ समय पहले स्वर्गीय बालयोगी जी ने पार्लियामैंट के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सभी स्टेट्स के स्पीकर्ज को सभी पार्टियों के नेतागणों को, सभी चिपस को, प्रधान मंत्री जी को , लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, सभी को बुलाया गया था। वहां भी उन्होंने यूनानीमसली कोड ऑफ कंडक्ट पास करवाये थे वह बात अलग है । लेकिन मैं तो जो already established Parliament Procedure or Rules हैं उनकी बात करना चाहता हूं। स्पीकर सर, आज जो सदस्य काली पट्टी लगाकर विधान सभा में आये इस तरह का प्रदर्शन करना, डैमोंस्ट्रेशन करना विधान सभा सदस्यों को शोभा नहीं देता । खासतौर से सीनियर मैम्बर्स को तो पट्टियां या फ्लैग लगाना बिल्कुल शोभा नहीं देता और न ही इस तरह का डैमोंस्ट्रेशन हाउस में अलाऊड है। स्पीकर सर, इस तरह की कार्यवाही की अनुमति उन लोगों को नहीं देनी चाहिए। कोई मैम्बर काली पट्टी लगाकर सदन में प्रदर्शन करे, धरना दे इस तरह की कार्यवाही असैम्बली में या पार्लियामैंट में परमिसिबल नहीं है। यह किसी मैम्बर विशेष के अधिकार की बात नहीं है, यह सारे हाउस के अधिकार और सम्मान की बात है। Speaker Sir, I want to read out the Sub-head 'Rules to be observed by Members while present in the House' of Chapter-12 "Conduct of Members" from the Book Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakdher at Page 278 in which it is written that :-

"A Member is not to resort to hunger-strike, dharna or any demonstration or perform any religious function in the precincts of the Parliament House and the Parliament House Estate." विपक्ष के भाई इस प्रकार की जो हरकतें कर रहे हैं these things are not permissible in the House. स्पीकर सर, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर

[प्रो०सम्पत सिंह]

वे काली पट्टी बांधकर हाउस में आते हैं तो हाउस में परमिट करने से पहले उनकी काली पट्टी उतरवाई जाये। वे सम्मानित मैम्बर के रूप में आयें, उनको पूरा सम्मान आप दे रहे हैं, हाउस भी उनको पूरा सम्मान दे रहा है। लेकिन वे इस तरह का प्रदर्शन या डैमोंस्ट्रेशन केवल मात्र मीडिया में रहने के लिए करते हैं। स्पीकर सर, हाउस की कार्यवाही में विपक्ष का कोई योगदान नहीं हैं। आज प्रश्नकाल था और प्रश्नकाल तो विपक्ष का ही हुआ करता है,जीरो आवर भी विपक्ष का ही हुआ करता है, विपक्ष प्रश्नकाल और जीरो आवर के लिए तरसा करता है और विपक्ष की हमेशा कोशिश रहती है कि उनके जीरो आवर का समय कम न हो जाये, उन्हें जीरो आवर का पूरा समय मिले लेकिन स्पीकर सर, इन दोनों आवर्ज को ही विपक्ष ने गवां दिया। इस से फिर यही बात साबित होती है कि विपक्ष के लोग हाउस की कार्यवाही के प्रति सीरियस नहीं हैं। उन्हें जो बातें सरकार के बारे में कहनी थी, चाहे सरकार की आलोचना करनी थीं या सुझाव देने थे, उस तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया जो कि उनका फर्ज बनता था। उन्होंने जो प्रश्न दिए हुए थे लोक हित के प्रश्न थे। उन प्रश्नों पर सरकार से पूछते और सरकार उनका जवाब देती। जो ये सुजैशंज देते शायद उनको सरकार मान भी लेती। पब्लिक को भी शायद उनसे फायदा होता। वे एक एक लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। वे केवल अपने सैल्फ इन्ट्रैस्ट के लिए कोई कन्ट्रीब्यूशन न करें और केवल अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए आपनी बातें कहें और शोशेबाजी करते रहें और नारे लगाते रहे, काली पट्टियां लगाते रहें, मुंह पर पट्टियां लगाते रहें, क्या यह कोई शोभा देता है ? अगर इन्होंने ऐसा ही करना था तो फिर ये अपना शरीर ही काला पोत कर आ जाते। इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। ये लोग काले तो वैसे ही हो रहे हैं, काली पट्टी बांधने से इनका कालापन तो जायेगा नहीं। इनको तो बल्कि सफेद पट्टी बांध कर आना चाहिए था। ताकि इनका कालापन कुछ दूर होता। यह मैं आपसे अपील करना चाहता था। इस प्रकार की चीजें हाउस के अन्दर नहीं होनी चाहिए। चौधरी बंसी लाल जी भी मेरी इस बात की ताईद करेंगे। चौधरी साहब, क्या काली पट्टियां बांधना, डैमोस्ट्रेशन करना या धरना देना हाउस के अन्दर एलाउड है या नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो।

चौ० बंसी लाल : मुझे तो पता नहीं।

प्रो० सम्पत सिंह : आपको पता नहीं चौधरी साहब, आप इतने सीनियर हो।

चौ० बंसी लाल : यह बात तो ठीक है कि वैल में नहीं जाना चाहिए, बिना बात शोर नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई कपड़े कैसे पहन कर आये इस बारे में मुझे नहीं मालूम।

प्रो० सम्पत सिंह : बंसी लाल जी, मैं कपड़ों की नहीं, डैमोंस्ट्रेशन की बात कह रहा हूं कि जैसे ये डैमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं क्या यह सही है ?

चौ० बंसी लाल : यदि कोई काली पट्टी बांध कर हाउस में आ जाये और आ करके बैठ जाये तो मेरा ख्याल है कि आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आपके रुल्ज में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप उनको रोक सकें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : वे डैमोंस्ट्रेशन नहीं कर सकते।

चौ० बंसी लाल : वे काली पट्टी बांधते हैं तो आपको क्या तकलीफ है बांधने दो।

Shri Sampat Singh : Kali Patti, that is a demonstration..

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब को किताब दो ताकि ये पढ़ कर देख लें । (विघ्न)

चौ० बंसी लाल : कल को तो वे काली जैकेट पहन करके आ जाएंगे ।

प्रो० सम्पत सिंह : काली जैकेट पहन करके आएं, वह अलग है। काली पट्टी बांध करके प्रोटैस्ट करना is a demonstration? मेरा मतलब डैमोस्ट्रेशन से है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह डैमोस्ट्रेशन है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रोफैसर साहब, चौधरी बंसी लाल जी का ध्यान नहीं था इसलिए इनको यह किताब दुबारा पढ़ने के लिए दे दो।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं जो बता रहा था कि अभी जो कान्फ्रेंस हुई थी (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये ।

श्री भागी राम : ये तो फ्रस्टेटिड हैं । (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : भागी राम जी, फ्रस्टेटिड आदमियों को और फ्रस्टेट न करो ये तो आलरेडी फ्रस्टेटिड हैं इसलिए इनको ज्यादा फ्रस्टेट न करो (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता था कि All India conference of Presiding Officers, Chief Ministers, Ministers of Parliamentary Affairs, Leaders and Whips of parties on Discipline and Decorum in Parliament and Legislature of the States and Union Territories was held on 25th November, 2001 at New Delhi. यह मीटिंग स्वर्गीय बालयोगी जी पूर्व लोक सभा अध्यक्ष ने बुलाई थी और उसमें जो तय हुआ था उस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इस प्रोसिडिंग के पेज न0 20 पर साफ लिखा है, जो परमिसिबल चीजें नहीं हैं उनमें यह है कि shouting of slogans in the House परमिसिबल नहीं हैं । Wearing or display of badges of any kind in the House are also not permissible. स्पीकर साहब हाउस में डैकोरम बनाने के लिए मैम्बर्ज को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए बकायदा कोड ऑफ कन्डक्ट है। उस कोड ऑफ कन्डक्ट के बारे में हमें प्रयास करना चाहिए कि वह लागू हो ताकि यह हाउस पब्लिक इन्ट्रैस्ट के लिए अच्छी प्रकार से चल सके। यह कोड ऑफ कन्डक्ट हरियाणा की 2 करोड़ 10 लाख जनता के लिए है न कि केवल किसी पार्टी विशेष के लिए है इसलिए उनकी तरफ नजर रखते हुए हमें इस कोड ऑफ कन्डक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसको मानना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्लेग फैलने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No.1 from Shri Anil Vij, M.L.A. regarding spreading of Plague. I admit it. Shri Anil Vij may please read his notice.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह स्पष्ट हैं कि अभी गत् दिनों के दौरान हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में कुछ लोग प्लेग से बीमार हुए थे तथा उन्हें पी0जी0आई0, चंडीगढ़ में इलाज के लिए भी लाया गया था जहां कुछ लोग मर भी गये थे। पी0जी0आई0, चंडीगढ़ में अधिकारियों की लापरवाही तथा प्लेग के अति संक्रामक रोग होने के कारण, कुछ अन्य रोगी जो वहां उपचाराधीन थे भी प्लेग से प्रभावित हुए जिसके कारण प्लेग पंजाब तथा हरियाणा के कुछ स्थानों में भी फैल गया है। इसके कारण, लोगों में भय व्याप्त है तथा शायद हिसार में कोई मौत भी हुई है। यहां यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह बीमारी गंदगी से बहुत शीघ्र फैलती है तथा आज हमारे कस्बे तथा गांव गंदगी से भरे पड़े हैं जो लोगों के बीच चिन्ता का मुख्य कारण बन चुका है। इससे पहले कि यह एक अति गम्भीर बीमारी का रूप धारण करे तथा सूरत जैसे हालात पैदा करे, युद्ध स्तर पर पग उठाये जाने आवश्यक हैं।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह हरियाणा में उन स्थानों के नाम बताएं जहां प्लेग ध्यान में आया है तथा इसे फैलने से रोकने के लिए तथा गंदगी के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं ? सरकार सदन के पटल पर इस संबंध में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

वक्तव्य

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ0 एम0 एल0 रंगा) : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने जैसे पूछा है, आज हरियाणा प्रान्त में प्लेग फैलने का कोई प्रचार नहीं है और न ही कोई प्लेग का मरीज या सम्भावित लक्षणों का मरीज हमारे सामने आया है। एक व्यक्ति जिसका नाम श्री कृष्ण सिंह रियोंद खुर्द गांव का था जो मानसा में बुढलाडा तहसील पंजाब का रहने वाला था, वह अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ में आया था और उस दौरान उसकी तीमारदारी करते हुए वह प्लेग के किसी सम्भावित रोगी के सम्पर्क मे आया जिससे उसको सम्भावित प्लेग हो गया जिस कारण पी0जी0आई0, चण्डीगढ़ में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके शव को दाह संस्कार के लिए रियोंद खुर्द में ले जाया गया वहां पर ले जा कर के उसकी पत्नी ने उसको नहलाया और उसका दाह संस्कार कर दिया गया, उसके पश्चात् उसकी पत्नी श्रीमती करमजीत कौर में जिस समय अगले दिन सम्भावित प्लेग के लक्षण पाए गए और उसे उल्टियाँ वगैरा की शिकायत हुई तो उसे रतिया में डा0 आर0के0 सिंह के प्राईवेट होस्पीटल में ले जाया गया। वहां पर उसके लक्षणों को देखते हुए उसका केस राजकीय होस्पीटल, हिसार में रैफर कर दिया गया। इस प्रकार 21 फरवरी को शाम 7.00 बजे रैफर केस वहां पर आया और उसके सम्भावित प्लेग के लक्षणों को देख कर टीम गठित करके हरियाणा स्वास्थ्य निदेशालय, चण्डीगढ़ को सूचित किया गया। निदेशालय की टीम के परामर्श के बाद जब उसमें प्लेग के सम्भावित लक्षण पाए गए तो 22 तारीख को श्रीमती करमजीत कौर रोगी को पी0जी0आई0, चण्डीगढ़ के लिए रैफर कर दिया गया और उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य निदेशालय से निदेशक महोदय की टीम वहां पर पहुंची जिसने पूरे अस्पताल का मुआयना किया और उनकी पूरी देख-रेख में आवश्यक कदम उठाए गए। आज के दिन हरियाणा प्रान्त में प्लेग का कोई भी रोगी नहीं है और न ही सम्भावित लक्षण हैं फिर भी हरियाणा सरकार आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देखरेख में यह चाहती है कि हरियाणा में जनसाधारण को प्रत्येक नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं।

हिमाचल प्रदेश की खबरें जिन दिनों अखबारों मे आई उसका ऐहतियात बरतने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीमें गठित कर दीं। सभी सिविल सर्जन्ज़ को निर्देश दिए गए। पहला निर्देश यह दिया गया कि सभी सिविल सर्जन्ज़ अपने अपने जिलों में कड़ी निगरानी रखें दूसरे निदेशालय स्तर पर कण्ट्रोल रूम बनाया गया जिसका टैलीफोन नं0 585503 था यदि जिले में कोई भी इस तरह का लक्षण मिलता है तो वे इस दूरभाष पर तुरन्त सूचित करें। तीसरे सभी जिला के अस्पतालों के अन्दर एक आईसोलेशन वार्ड बना दिया गया है जिससे कि सम्भावित मरीजों को इलाज के लिए वहां रखा जाए। इसके साथ ही साथ रोग निरोधक दवाईयां हर जिला स्तर पर हमने भेज दीं ताकि आने वाले रोगी की बीमारी की सूचना मिलते ही उसका उपचार किया जा सके। सभी डी0एस0ओज़ को हमने निर्देश जारी किए हैं कि अस्पतालों के आस-पास जो उसका कार्य क्षेत्र है, उसमें सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें।

इतना ही नहीं श्रीमति करमजीत कौर को पंजाब से हिसार लाया गया उस समय हिसार के अस्पताल के अन्दर 36 डॉक्टर्ज, पैरा मैडिकल स्टाफ और दूसरे कर्मचारी जो उसके सम्पर्क में आये उन सभी को रोग निरोधक दवाइयां दे चुके हैं। इसके अलावा भी जिस एमरजैंसी वार्ड में उसको रखा गया तथा जहां पर एक्स-रे किया गया, जिस आईसोलेशन वार्ड में उसको भेजा गया था उन सभी को फयूमिकेट कर दिया गया है और जिस समय उस मरीज को चण्डीगढ़ ले जाया गया उस समय जो पैरा मैडिकल स्टाफ और जो अन्य स्टाफ साथ था उन सभी को रोग निरोधक दवाईयां दी गई हैं। यहां तक कि जिस एम्बुलैंस में उसे ले जाया गया था उसके चालक और परिचालक को भी रोग निरोधक दवाइयां दी गई हैं। इसी के साथ एक और बात ध्यान में आई कि जिस समय मरीज को चण्डीगढ़ लाया जा रहा था उस वक्त उसको रास्ते में अम्बाला के पास एक ढाबे में चाय पिलाई गई थी हमने उस ढाबे वाले के पास जाकर उसको और उसके कर्मचारियों को भी दवाई दी थी। यह कार्यवाही उस मरीज को पी0जी0आई0 अस्पताल में भर्ती करवाने तक ही सीमित नहीं हो जाती है। हमने फतेहाबाद के सीविल सर्जन को हिदायतें दी हैं कि यदि पंजाब में इस तरह की बीमारी आई तो वहां सीमा पर लगते हरियाणा के गांवों में जाकर भी दवाईयां बांट देना। उसके अलावा फतेहाबाद के साथ लगते हुए जो 14 गांव हमारे थे, वहां पर जाकर हमने सर्वे किया था। सर, एक कामना गांव है जिस गांव के 14 व्यक्ति कृष्ण सिंह के अन्तिम संस्कार में गए थे हमने उन व्यक्तियों को भी खुद रोग निरोधक दवाई खिलवाई थी ताकि प्लेग की बीमारी आगे न फैले। आज के दिन में मैं यह कह सकता हूं कि इस प्लेग बीमारी के प्रति हरियाणा सरकार पूरी तरह से जागरुक है। आज हरियाणा में कोई भी व्यक्ति प्लेग से पीड़ित नहीं है। सर, PGI चण्डीगढ़ में 18 फरवरी से 20 फरवरी के दौरान जितने भी केस प्लेग के दाखिल थे या वहां पर हरियाणा के लोग चाहे वे एक्सीडैंट की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से इलाज करवा रहे थे, की सूची भिजवा दी थी ताकि इन सबको रोग निरोधक दवाईयां दे दें। हमने वहां जाकर के सबको रोग निरोधक दवाईयां दीं और यह एन्श्योर किया कि वे बिल्कुल ठीक हैं। किसी भी व्यक्ति में प्लेग के सम्भावित लक्षण नहीं पाए गए। यहां तक कि आज के प्रश्न के उत्तर में मैं यह कह सकता हूं कि आज के दिन हरियाणा सरकार इस बीमारी के प्रति पूरी तरह से जागरूक है और स्वास्थ्य विभाग भी हर तरह से जागरूक है और रहेगा। इसके अलावा सम्मानित सदस्य ने यह भी प्रश्न उठाया है कि शहरों और गांवों में गन्दगी फैल रही है। उस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने शहरों में नगरपालिकाएं बनाई हुई हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश

[डॉ0 एम0 एल0 रंगा]

में हर नगरपालिका को स्वाधीनता दी हुई है, काफी मात्रा में उनको आर्थिक अनुदान दिया हुआ है, उनके पास सफ़ाई कर्मचारी मौजूद हैं। आज वहां पर गलियां और नालियां सीमेन्टिड हैं और शहरों के अन्दर हमने करोड़ों रुपए की लागत से इन्सुलेटर लगाने का प्रस्ताव भी सरकार के पास भेजा हुआ है। जिसे सरकार ने स्वीकृत किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहरों में उससे और ज्यादा स्वच्छता और सफाई आ जाएगी। उसके साथ मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर शहरों से डेयरियों को बाहर लाने का काम किया है ताकि शहरों में स्वच्छता प्रदान की जा सके। जहां तक गांवों का प्रश्न है, मैं आज से दो-अढ़ाई साल पहले की बात नहीं कह सकता लेकिन आज हरियाणा का हर गांव स्वर्ग बन चुका है। गांवों के अन्दर जितनी भी सड़कें और गलियां हैं उनके लिए 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत हर गांव में प्रचुर मात्रा में आर्थिक अनुदान दिया गया है। सफाई व्यवस्था की तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा के गांवों में सफाई की पूरी व्यवस्था है और प्लेग तो क्या कोई भी बीमारी वहां पर आने की हिम्मत नहीं कर सकती है। सर, शायद यही कारण है कि यमुनानगर के उपचुनाव में जिसके बारे में माना जाता था कि वह कांग्रेस का या किसी दूसरी पार्टी का गढ़ था, हमने वहां अभूत पूर्व विकास कार्य करवाये और आज सारे शहर के लोग हमारे साथ आए हैं और उनके द्वारा जिताया हुआ मैम्बर आज हमारे बीच में बैठा हुआ है। यह सब हमारी कार्यप्रणाली का परिणाम है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी का सवाल का जवाब बहुत ही बढ़िया था। अपने जवाब में इन्होंने बताया कि इन्होंने सबको दवाईयां दीं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सवाल पूछने वाले को भी दवाई दी है ? (हंसी)

डॉ0 एम0एल0 रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछने वाले के लिए भी दवाई लेकर आया हूं।

चौ0 बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, रंगा साहब ने जवाब तो ठीक कर के दिया है लेकिन सफाई के जो अधिकार नीचे दे रखे हैं उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। (हंसी)

श्री अनिल विज : सर, मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है और बहुत तेजी से कार्यवाही की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। आज भी एक समाचार पत्र में खबर छपी है कि रतिया में प्लेग से एक महिला की मृत्यु हो गई है और पी0जी0आई0, चंडीगढ़ में आज की तारीख में भी कुछ रोगी उपचाराधीन हैं। पी0जी0आई0, चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से कई रोगी अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। यहां पर जिस तरह से इस मामले को लाइटली लिया जा रहा है वह ठीक नहीं है। हमें इस मामले को लाइटली नहीं लेना चाहिए बल्कि हमें इस बारे में बहुत ही अच्छी तरह से काम करना चाहिए। जहां तक सफाई की बात मंत्री महोदय ने कही है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि सूरत में जब प्लेग फैला था तो वहां देखते ही देखते मृत्यु की दर बहुत तेजी से बढ़ती चली गयी थी। उस समय इस के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बाद में वहां पर प्लेग के फैलने का कारण गंदगी माना गया था। अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने अम्बाला शहर में फैली हुई गंदगी के बारे में करीब सौ ऐसी तस्वीरें खींची हैं जहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यह ठीक है कि सरकार इस बारे में अच्छा

काम कर रही है सरकार ने इसको रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जितने विस्तार से मंत्री जी ने इन कदमों के बारे में बताया वह अच्छी बात है लेकिन हमें इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए शहरों से और गांवों से गंदगी को हटाने के लिए एक कम्पेन चलाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि प्लेग फैलने के बाद ही नहीं बल्कि इसके फैलने से पहले ही अगर हम सफाई की ओर ज्यादा ध्यान दें तो यह और अच्छी बात होगी। स्वास्थ्य और लोकल बॉडी दोनों मंत्री यहां पर बैठे हैं मैं इनसे कहना चाहूंगा कि सफाई को चुस्त दुरूस्त करने के लिए और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। यह ठीक है कि सफाई की जिम्मेदारी नगरपालिकाओं की है लेकिन हम सबकी भी यह जिम्मेदारी है कि हम इस ओर ज्यादा ध्यान दें। जिम्मेदारी के मामले में हममें से कोई भी नहीं बच सकता। अध्यक्ष महोदय, आज यह बीमारी एक चिन्ता का विषय बनी हुई है। सरकार ने अनेक काम इस बारे में किए हैं लेकिन अभी बहुत और काम इस बारे में किए जाने बाकी हैं। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इस मामले को हंसी में उड़ाते हुए एक दूसरे को इंजैक्शन लगाने की बात नहीं कही जानी चाहिए। अब भी इस बारे में काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण काम किए जाने बाकी हैं। सफाई करने की जिम्मेदारी केवल नगरपालिकाओं की नहीं है बल्कि सभी विभागों को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इस बारे में आश्वासन चाहूंगा।

डॉ0 एम0एल0 रंगा : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने जिस प्रकार से रतिया में प्लेग के किसी केस का जिक्र किया है मैं उसके बारे में उनको स्पष्ट करना चाहूंगा कि रतिया की तो बात ही छोड़िए पूरे हरियाणा में कहीं भी आज के दिन कोई भी व्यक्ति प्लेग से पीड़ित नहीं है और न ही कोई ऐसी संभावना है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आज के पंजाब केसरी में फ्रंट पेज पर ही इस बारे में छपा हुआ है।

डॉ0 एम0एल0 रंगा : अध्यक्ष महोदय, प्लेग की तो बात छोड़िये अगर हमें कहीं पर बुखार का भी पता लगता है तो तुरन्त हमारी टीम वहां पर जाती है और उसका इलाज करती है। मैंने पहले ही इस बारे में जो प्रिकॉशनरी मैयर्ज लिए हैं, उनके बारे में सदन को अवगत कर दिया है। हमारी टीमें हर जिले में इन टच हैं कि कोई इस तरह की बीमारी प्रदेश में न फैले। सफाई की व्यवस्था वैसे तो सरकार करती ही है लेकिन हम सबकी भी इस बारे में ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसका ध्यान रखें। हमने वैसे तो इस बारे में काफी प्रावधान किए हैं और अन्य बातें भी हम करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि नगरपालिकाओं और गांवो में हर तरह से सफाई की व्यवस्था रखी जाए।

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, रंगा साहब ने विस्तार से इस बारे में अपना पक्ष रखा। मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूं और रंगा साहब को बधाई भी देना चाहता हूं कि जैसे ही अखबार या अन्य किसी मीडिया ने इस बात को प्रकाशित किया वैसे ही स्वास्थ्य विभाग ने, तथा सम्मानित मंत्री जी ने तुरन्त उस पर कार्यवाही की। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे सामने जो साथी बैठते हैं इन सभी की सफाई तो यमुनानगर के लोगों ने कर दी। कृष्णपाल जी भी उनके साथ वहां अपनी पार्टी की सफाई करवा लाए।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री धीरपाल सिंह : इनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पांच साल तक लगातार शासन किया लेकिन फिर भी लोगों ने जो दुर्दशा इनकी वहां पर की है मैं उस पर व्याख्या नहीं करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर और हरियाणा के लोगों ने डा0 साहब की बात पर और मुख्यमंत्री जी की बात पर विश्वास करके ही दोनों पार्टियों की सफाई की। इसी प्रकार मंत्री महोदय ने सफाई के लिए भी तुरन्त कार्यवाही कर इस बीमारी को रोकने का प्रबन्ध भी किया है। मैं हाउस की तरफ से डाक्टर रंगा साहब का आभार व्यक्त करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 30.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 7th March, 2002.

Mr. Speaker : Motion moved-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 7th March, 2002.

Mr. Speaker : Question is-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 7th March, 2002.

The Motion was carried

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion on the Governor's Address will be resumed. सभी सदस्य गवर्नर ऐड्रस पर ही बोलें। सभी को 6-7 मिनट का समय दिया जाएगा। पार्टीवाइज़ टाईम की डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है। 300 मिनट का समय इंडियन नेशनल लोकदल को मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 130 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 40 मिनट, हरियाणा विकास पार्टी को 15 मिनट, आर0पी0आई0 को 10 मिनट, एन0सी0पी0 को 10 मिनट, बी0एस0पी0 को 10 मिनट व इंडिपैंडैंट्स को 70 मिनट का समय दिया जाता है। अभिभाषण पर बोलते हुए सभी माननीय सदस्य इस समय का ध्यान रखें। अब श्री भगवान सहाय रावत बोलेंगे।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज के इस महान सदन में हरियाणा प्रदेश में बसने वाले और कृषि पर आधारित किसान के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एस0वाई0एल0 पूरा करने का जो दिशा निर्देश देकर जो

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

उपहार दिया गया है उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूँ कि एस0वाई0एल0 कैनाल हरियाणा की जीवन रेखा है **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई थी इस नहर के निर्माण के लिए पंजाब सरकार को राशि भी दी गई थी। चौधरी देवी लाल जी का वह स्वप्न आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से हरियाणा के लिए, हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा में बसने वाले उद्योगपति व मजदूर के लिए व सभी वर्गों के लिए यह एक बेहतरीन उपहार है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस जनतंत्र में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मैं आपके ही माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितना दायित्व सत्तापक्ष का होता है उतना ही विपक्ष का भी होता है। सही मायनों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होती है। जनता का हित करना हम सबका नैतिक कर्त्तव्य भी है। सही मायनों में एक विधायक, एक मंत्री, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जो भी लोग जनता द्वारा चुनकर यहां आते हैं। हम लोग जनता के कल्याण के लिए तथा जनता के द्वारा चुने जाते हैं इसलिए जनता का कल्याण करना हमारा परम कर्त्तव्य है। उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष जिस फ्राख दिली से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है कल के घटनाक्रम को दृष्टिगत रखकर मैं विपक्ष के बारे में कहना चाहूंगा कि विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन करने में गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामकिशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुने।

श्री उपाध्यक्ष : रामकिशन फौजी जी, आप अपनी सीट पर बैठिये।

श्री भगवान सहाय रावत : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मुझे याद है जब वे पर्याप्त मात्रा में संख्या उपलब्ध नहीं करा सके थे और कल भी जब उनके द्वारा लाया गया प्रस्ताव गिर गया तो उन्होंने किस प्रकार का मिसमैनेजमेंट का उदाहरण प्रस्तुत किया और सारा दोष सत्ता पक्ष पर मढ़ा। आज भी उनको पता था कि कार्य सूची में यह निश्चित था कि सदन समय सुबह साढ़े नौ बजे शुरू होगा। वे लोग स्वयं विलम्ब से आये और पर्याप्त संख्या में उपस्थित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, के खिलाफ उनका अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। उसके बाद उन्होंने यहां पर किस तरह का तांडव किया यह सबके सामने है। उनका व्यवहार सही मायने में आपत्तिजनक था। अगर इन नियमों की परिभाषा की व्याख्या की जाये तो बहुत समय लगेगा। इसके बारे में यहां नियमावली में दिया गया है कि कोई भी सदस्य अपनी सीट से उठकर अव्यवहार करता है तो यह नियमों के अनुसार नहीं कहा जाता है। विपक्ष के नेता और दूसरे सदस्य जो पार्लियामेंट में भी रहे और मंत्री के पद को भी जिन्होंने सुशोभित किया मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने प्रथम नियम का भी पालन न करते हुये सदीय मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और वे प्रजातांत्रिक व्यवस्था की दुहाई देते रहे। आज भी और कल भी, रोज उनका स्टैंड बदलता रहा। पहले वे कहते रहे कि सबसे पहले हमारा अविश्वास का प्रस्ताव टेक अप किया जाना चाहिये। जब वह टेक अप कर लिया तो कहते हैं कि सबसे पहले क्वैश्चन ऑवर होना चाहिये और आज जब प्रश्नकाल आया तो उसका भी बाई काट कर के चले गये और यह सिद्ध कर दिया कि वे अपनी भूमिका में गंभीर नहीं हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन को जो संदेश दिया जैसा अभिभाषण यहां आकर दिया उसको दृष्टिगत रखकर उस पर चर्चा के लिए मैं भी अपने कुछ निजि विचार और व्यक्त करना चाहूंगा। वर्तमान सरकार आदरणीय चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व में गतिशील है। मैं समझता हूं कि प्रजातांत्रिक इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं आई होगी जिसने 'सरकार आपके द्वार' जैसे कार्यक्रम का आयोजन करके जनता को प्राथमिकता दी हो।

[श्री भगवान सहाय रावत]

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है जनता सर्वोपरि है। माननीय अब्राहिम लिंकन की परिभाषा को अगर मैं पढ़ूं तो वह ऐसी है कि " Govt. for the people, by the people and of the people" यह परिभाषा सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मानी जाती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था और लोकतंत्र की उसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने इस तरह के अनेक प्रेरणा स्रोत हमे दिये जो आज हमारे लिए आदर्श बने हुए हैं। उनके कहे हुए यह वाक्य कि लोक राज लोक लाज से चलता है, उनके उसी मार्गदर्शन पर चलते हुए माननीय चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। उन्होंने हर गांव में हर विधान सभा क्षेत्र में जाकर जनता द्वारा चुने हुए पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर गांवों में डिवैल्पमेंट कमेटीज बनाई। यदि मैं तथ्यात्मक बात कहूं तो आजादी के बाद देश के किसी राज्य में इतने विकास के कार्य नहीं हुए होंगे जितने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत हरियाण प्रदेश में हुये हैं। एक-एक पंचायत के अन्तर्गत, एक-एक गांव में 80-80 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा अपने हल्के इथीन का जहां पर मेवात का गांव उटावड़ है। उस गांव में 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत 80 लाख रुपये खर्च किये गये। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकास का कार्य इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में हुआ है। सभी गांवों की चारदीवारी, स्कूलों की बाउण्डरी, स्कूलों के कमरे, गलियों को पक्का करना आदि उन कार्यों को करने से उनकी सूझबूझ का सबूत मिलता है। इसी प्रकार गांवों के जो शमशान घाट उपेक्षित रहते थे और उन पर नाजायज कब्जे किये हुये थे, हमारी मेव जाति के लोगों के कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जे किये हुए थे, जिनको उनके धर्म में अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, उन पर काम करवा कर एक पुण्य का कार्य किया गया है। उस इलाके के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े ही आभारी हैं। इसी प्रकार मैं माननीय चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी का आभारी हूं जिन्होंने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के पहले चरण में तकरीबन 852 करोड़ 79 लाख रुपये की लागत से 10089 विकास कार्य पूरे किए हैं और इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में 368 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से 9830 विकास कार्य अभी प्रगति पर हैं इस कार्यक्रम ने राज्य में विकास कार्यों को एक नई गति व दिशा दी है। इस प्रकार पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है और मैं समझता हूं कि चौधरी देवीलाल जी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती क्योंकि वे हमेशा ही जन्म से गरीबों के लिए जिये, जनता के लिए जिये और जीवन पर्यन्त उनके लिए संघर्षरत रहे। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी उनकी कई स्मृतियां मेरे मन पर अंकित हैं। मुझे उनके कार्यकाल में विधायक बनने का सौभाग्य मिला था। उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले की सरकारों ने किसानों की कभी इतनी मदद नहीं की होगी और अगर की भी होगी तो आधे अधूरे मन से की होगी। पूरी तरह से वे मदद कर नहीं पाए होंगे। पीछे जब ओलावृष्टि हुई थी तो माननीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने किसानों के खेत की डौल पर जाकर किसानों के दुःख दर्द में हिस्सेदारी की। उनको सांत्वना देने के लिए खेत की डौल पर बैठकर प्रशासन को आदेश दिया था कि इन किसानों के नुक्सान की क्षति पूर्ति की जाए तो उस वक्त के प्रशासन ने गिरदावरी करने के बारे में उनसे कहा गिरदावरी करवा कर इसके नुक्सान की पूर्ति की जाएगी। चौधरी देवीलाल जी की यह बात सुनकर आज कौन हर्षित नहीं होगा जब उन्होंने अधिकारियों को कहा था कि कब आप गिरदावरी करोगे और कब आपका रिकार्ड बनकर आएगा किसान को तो आज सहायता की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि किसान के खेत की डौल पर बैठकर किसान के

नुक्सान की भरपाई की जाए। ऐसा चौधरी देवीलाल जी का चरित्र था। यह इतिहास की बात है। पहले कभी भी ग्रामीण आँचल की भावनाओं को ऐसे समझा नहीं गया। मैं समझता हूं कि इसका उदाहरण कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से किसानों के उत्पादन तथा पानी की बात कहना चाहूंगा। नई शुगर मिल्स लगाकर गन्ने की पिराई में और वृद्धि की गई है। आज हरियाणा का किसान शायद सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है क्योंकि उसको भारतवर्ष में गन्ने का सबसे ज्यादा मूल्य मिल रहा है और उसकी पेमैंट में भी कभी विलम्ब नहीं हुआ। सहकारी क्षेत्र में नई मिल्स लगाकर, पुरानी मिलों की क्षमताएं बढ़ाकर और किसानों को टाइम पर पेमैंट करके हरियाणा में नये कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल, गोहाना एक वर्ष की रिकार्ड अवधि में लगाई गई है। मैं समझता हूं कि ऐसा भी उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कि इतनी तत्परता से किसी प्रोजैक्ट को पूरा किया गया हो। आज हरियाणा के किसान को 104/- रुपये, 106/- रुपये और 110/- रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य मिल रहा है जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहूंगा जोकि आजादी के बाद उपेक्षित रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद यहां पर लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई। सबसे पहले हरियाणा सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है जिसने शिक्षा नीति में परिवर्तन किए हैं। यह एक सराहनीय कार्य है। मुझे विधायक बनने से पहले अध्यापक होने का सौभाग्य मिला था। शिक्षा नीति में परिवर्तन करना आज देश और राज्य की अनिवार्यता है। इस सरकार ने पहली क्लास से ही अंग्रेजी विषय प्रारम्भ करके शिक्षा नीति में नये बदलाव किए हैं। इस सरकार ने गर्ल्स कॉलेज खोले हैं और इन्फर्मेशन टैक्नोलोजी तथा कम्प्यूटर एजूकेशन को बढ़ावा दिया है। छठी और दूसरी क्लासिज में नए पाठ्यक्रम को शुरू करके इस सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर हम मानवीयता के आधार पर देखें और शरीर संरचना के दृष्टिगत मनुष्य के सर्वांगीण विकास की बात करें तो खेलों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं खिलाड़ी रहे हैं, मुझे वह स्वर्णिम दिन याद है जब आप और मैं गुड़गाव के स्टेडियम में खेल में पार्टिसिपैंटस होते थे इसलिए मुझे आपकी उपस्थिति में यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए नई खेल नीति लागू करके राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। पहले कोई भी खिलाड़ी ओलम्पिक टूर्नामैंट में एक भी मैडल लेकर नहीं आया लेकिन अब हरियाणा ने उस चैलेंज को स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है। हमारे माननीय विधायक श्री अभय सिंह चौटाला, जो ओलिम्पिक एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष हैं, के नेतृत्व में खेल नीति को बढ़ावा मिल रहा है। गांव-गांव में स्टेडियम बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है और जैसा कि सदन के सभी सदस्य जानते हैं और हरियाणा की जनता भी जानती है कि ओलम्पिक टूर्नामैंट में घोषणा का प्रभाव हुआ है। हरियाणा सरकार ने स्वर्ण पदक जीतने वाले को एक करोड़ रुपये, चांदी का मैडल जीतने वाले को 50 लाख रुपये और कांस्य-मैडल लाने वाले को 25 लाख रु0 का पुरस्कार देना पहले से ही तय कर दिया है। आज के नौजवानों में खेलों के प्रति बहुत उत्साह है। मुझे इस बात को दोहराते हुए गर्व हो रहा है कि पिछली सरकारें नौजवानों को शराब की तस्करी और दूसरे गलत कार्यों में लगाकर अपना दायित्व भूल गई थीं और हमारे नौजवान भाई अपना रास्ता भटक गये थे, उनके सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था जिस कारण इस प्रदेश के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया था। जब हमारी सरकार आई उस समय प्रदेश की हालत से यह

[श्री भगवान सहाय रावत]

स्पष्ट मालूम होता था कि इस प्रदेश का भविष्य तब तक उज्जवल नहीं हो सकता जब तक नौजवानों का भविष्य उज्जवल नहीं होता। नौजवानों को सही रास्ते पर लाने के लिए हमारी सरकार ने अच्छी खेल नीति का माध्यम चुना जिसका प्रभाव भी नौजवानों पर जल्दी ही पड़ा और आज की स्थिति हम सबके सामने हैं। नौजवानों को सही रास्ते पर लाने के लिए भाई अभय सिंह चौटाला और हरियाणा की जनता बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय खेल राज्य मंत्री जी ने हिसार में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है जो कि हमारी सरकार की अच्छी नीतियों का परिणाम है। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 3 प्रतिशत का आरक्षण दिया है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने गांवों में स्टेडियम बनाने के लिए सबसिडी देने का भी प्रावधान किया है जिससे गांवों में रहने वालों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे हरियाणा प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि हिसार में 7वें युवा राष्ट्रीय खेल महोत्सव का सफल आयोजन हुआ और उसमें हरियाणा के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किया। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के विकास के लिए भी हमारी सरकार ने सराहनीय कार्य किए हैं। हमारी सरकार ने किसानों को बीज, खाद, पानी और कीटनाशक दवाईयां सुनिश्चित मात्रा में उपलब्ध करवाने के भरसक प्रयास किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने किसानों को गेहूं, जौ, धान के प्रमाणित बीजों पर 200/- रुपये प्रति क्विंटल दलहनों पर 800/- रुपये प्रति क्विंटल और कपास पर 1000/-रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने फॉसफेटिक व पौटाशिक उर्वरकों पर भी किसानों को लगभग 200 करोड़ रुपये का अनुदान देकर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी को मालूम है कि किसान इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं, हरियाणा में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं और उनका मुख्य धन्धा खेती है। मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने हिसार कृषि विश्वविद्यालय में 'निःशुल्क कृषि हैल्प लाईन' सेवा शुरू की है जिसके माध्यम से किसान कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से टैलीफोन पर ही अपनी समस्याओं का समाधान जल्दी से पा सकेगा और समय रहते अपनी फसल की बीमारी को रोक पायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से इन्फर्मेशन टैक्नॉलोजी और शिक्षा की तरह अब किसान भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे और किसान पूरी तरह से लाभान्वित होंगे तथा यह अपने आप में एक अनूठी मिसाल होगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र आता है जहां मेरा और आपका हल्का पड़ता है वहां पर भी किसानों को सिंचाई की उचित सुविधा देने के लिए हमारी सरकार ने 4 हजार अतिरिक्त फव्वारा सिंचाई संयत्र लगाने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त कल्लर भूमि के सुधारीकरण के लिए भी हमारी सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है और चालू वित्त वर्ष में 8 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना है। उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों के साथ-साथ मैं अपने हल्के से संबंधित एक और बात आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां बहीन पंचायत के पास 440 एकड़ जमीन है जो कि कल्लर भूमि है जिसके सुधारीकरण का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस जमीन का सुधारीकरण का कार्य शुरू तो कर दिया गया है लेकिन लोग उस कार्य के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं इसलिए मैं विभागीय प्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि वे इस सुधारीकरण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इस सुधारीकरण का यह कार्य जल्दी पूरा कराने का कष्ट करें। उपाध्यक्ष महोदय, आज

के दिन किसानों को हरियाणा में अपने कृषि उत्पादन को बेचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। हमारा प्रदेश देश के सामने एक अनोखी मिसाल बन गया है क्योंकि आज किसान 8 से 10 किलोमीटर के फांसले के भीतर अपने उत्पादन को बेच सकता है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 105 मुख्य मार्किट यार्ड, 179 सब-यार्ड तथा 158 खरीद केन्द्र हरियाणा में स्थापित किये गए हैं। इस सरकार के दौरान मार्किटिंग बोर्ड के द्वारा ग्रामीण सड़कों की विशेष मुरम्मत पर 137 करोड़ 54 लाख रुपये खर्च किए गए हैं तथा 363 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से 4464 किलोमीटर लम्बी नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण की योजना है इसमें से 2791 किलोमीटर लम्बी नई ग्रामीण सड़कों का कार्य पूर्ण भी हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से हथीन की समस्याएं रखना चाहता हूं। इस सरकार की उपलब्धियों के बारे में अपनी बात कहना भी मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं इसमें मैं स्वयं को और गौरवान्वित होना समझूंगा। हथीन की मण्डी, जिसको सब यार्ड घोषित किए हुए वर्षों हो गए थे, उसकी तरफ किसी भी पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। जहां तक मुझे याद है, यह सब यार्ड 1968, 1970 या 1972 के बीच में बना था यानि उसका निर्माण वहां पर करवाया गया था। आप देखिए कि 1970 से लेकर आज हम 2002 में बैठे हैं यानि 32 सालों के बाद तक उस सब यार्ड को अपग्रेड नहीं किया गया था। इन 32 सालों के शासनकाल में जहां अधिकांश शासन कांग्रेस का रहा और चौधरी बंसी लाल जी का भी रहा, उस सब यार्ड को पूरी मण्डी का दर्जा नहीं दिया जा सका। मैं 1972 में ब्लॉक समिति और जिला समिति का सदस्य था, उस वक्त वह सब यार्ड बना था उसके बाद से लेकर इस सरकार के आने तक उसको पूरी मण्डी का दर्जा नहीं दिया जा सका था। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी सरकार ने उसको मण्डी में अपग्रेड नहीं किया। मुझे आपके सामने यह सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि आज की वर्तमान सरकार के समय में हथीन की मण्डी को पूरी मण्डी का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरु हो गई है इसके लिए मैं कृषि मंत्री जी व आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि यह कार्य शुरु ही नहीं हुआ है बल्कि गजट नोटिफिकेशन भी होने जा रहा है। यानि चन्द दिनों में वहां पूरी मण्डी गठित हो जायेगी। पूरी मण्डी बन जाने पर वहां नई मार्किट कमेटी का भी गठन हो जायेगा। इसके लिए सरकार निश्चित रूप से बधाई की हकदार है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा कि यमुना नदी और भाखड़ा डैम के पानी का जल स्तर सामान्य मात्रा से कम होने के बावजूद भी सरकारी प्रयासों से किसानों को उचित पानी देने की व्यवस्था की गई। इस मंत्रालय द्वारा इस वर्ष 26 करोड़ रुपये की लागत से पथराला बांध तथा 34 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से चौधरी देवीलाल ओटू वीयर, सिरसा का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इसके अलावा आधुनिकीकरण के अन्तर्गत मुख्यतः बरवाला ब्रांच, सिरसा ब्रांच, मेलका माईनर व पाबड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी को लिया गया है। सिंचाई विभाग ने 394 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से पूर्ण होने वाले नौ प्रोजैक्ट स्वीकृत किए हैं इनमें से 299 सिंचाई सम्बन्धी स्कीमें तथा 212 स्कीमें जल निकासी से संबंधित हैं। इनके अन्तर्गत मुख्य योजनाएं, बरसोला फीडर, महम तथा लाखन माजरा ड्रेन हैं, जो पूर्ण हो चुकी हैं। रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, दड़बा-धग्गर ड्रेन, बचेर-नशोर लिंक चैनल व रामकली माईनर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार से बाढ़ नियंत्रण के लिए भी अनेक प्रभावी कदम उठाये गये हैं। अब मैं गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों के बारे में भी कुछ बातें कहना चाहूंगा। वहां पर केवल मात्र गुड़गांव कैनाल और आगरा कैनाल द्वारा ही सिंचाई की जाती है। वहां पर सिंचाई के केवल

[श्री भगवान सहाय रावत]

यही दो माध्यम हैं। आगरा कैनाल का कन्ट्रोल उत्तर प्रदेश के हाथों में है। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं पिछली बार 1987 में विधायक बना था तब भी हमने चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में इस नहर का कंट्रोल हरियाणा के हाथों में लेने का प्रयास किया था लेकिन वह योजना पूरी तरह सिरे नहीं चढ़ सकी थी। उस वक्त चौधरी देवीलाल जी के प्रयासों से इतना तो जरुर हो गया था कि हरियाणा के अन्दर से जहां जहां से यह नहर गुजरती है और जो मुख्य लिंक चैनल हरियाणा में हैं उनका कन्ट्रोल तो हरियाणा के हाथ आ गया था लेकिन पूरा कन्ट्रोल अभी तक हरियाणा के हाथों में नहीं आया है। आज भी इस आगरा कैनाल का मैनेजमैंट उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथों में ही है। यही कारण है कि यहां के किसानों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल रहीं जितनी मिलनी चाहिएं। आगरा कैनाल पर अपना कन्ट्रोल न होने के कारण इस नहर का पूरा पानी हमें नहीं मिल पाता क्योंकि मैनेजमेंट दूसरी सरकार का है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस नहर के साथ कोई समानान्तर नहर निकाल कर या मैनेजमैंट अपने हाथ में लेकर वहां के किसानों को पूरा पानी दिलवाया जाये। हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा पहले भी केन्द्रीय स्तर पर इसके समाधान के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं लेकिन आज भी इसका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हाथ में है। जब तक हम इस नहर के नियंत्रण में पार्टली भागीदार या जिम्मेदार नहीं होंगे तब तक हमें पूरा पानी नहीं मिल पायेगा। जहां तक गुड़गांव नहर का ताल्लुक है, वहां पर उटावड़ डिस्ट्रिब्यूटरी है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के समय में स्थानीय नहर के जो राज्यमंत्री थे उन्होंने उटावड़ डिस्ट्रिब्यूटरी पर करोड़ो रुपये खर्च करके गलत डिजाईनिंग करवाई। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहली सरकार के समय में उसकी गलत डिजाईनिंग की गई यानि उसको मोडीफाईड करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी उसका जो लास्ट सिरा है यानि टेल है वह ऊंचा है जिस कारण वर्तमान में उस नहर में पूरा पानी नहीं चलता। पानी का फ्लो ठीक न होने के कारण वह नहर कई बार टूट भी जाती है जिस कारण किसान पानी से वंचित होते हैं। मैं पूर्व मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी की मौजूदगी में इनके समय की जो बात है और रिकार्ड पर आधारित है, वह कहना चाहूंगा। वहां पर हसनपुर विधान सभा क्षेत्र में 2 करोड़ रुपये की लागत से एक डैम बनवाया गया था। इस डैम को सही योजना के मुताबिक नहीं बनाया गया और न ही सही स्थान पर बनाया गया जिस कारण वह बांध पानी आने की वजह से रेत के बांध की तरह बह गया था। जब यह बात वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाई गई तो इन्होंने तुरन्त आदेश देकर इसकी मुरम्मत करवाई है। निश्चित् रूप से ऐसे कार्यों की वर्तमान सरकार द्वारा जांच की जानी चाहिए जिसमें किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत और बिजली उत्पादन की आज के युग में एक महत्वपूर्ण भूमिका बन गई है। सुबह से ले कर रात्री तक, जब आज आदमी प्रात : काल उठता है तब से ले कर जब तक वह सोने के लिए जाता है, प्रत्येक दैनिक कार्य में, प्रत्येक घरेलू कार्य में, प्रत्येक औद्योगिक कार्य में, शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र मे, मैं कहना चाहूंगा कि सभी क्षेत्रों मे विद्युत अनिवार्य चीज है। हमारे यहां पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार उसके उत्पादन के प्रयास किए गए। उपाध्यक्ष महोदय, एक विधायक होने के नाते मैं आपके माध्यम से यहां पर सुझाव भी देना चाहूंगा। आज 55 साल की आजादी के बाद भी जो विद्युत उत्पादन है उस में इस वर्तमान सरकार से पहले उतने सघन प्रयास नहीं किए गए। आज की सरकार ने केन्द्र स्तर पर और अपने स्तर पर अलग-अलग क्षेत्रों मे जो अलग-अलग प्रकार से

बिजली का उत्पादन हो सकता है चाहे वह हाईडल प्रोजैक्ट्स लगा कर हो, चाहे गैस पर आधारित प्लांट लगा कर हो, उसके भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अकेले हिमाचल प्रदेश में हाईडल प्रोजैक्ट्स लगा कर केन्द्र की स्वीकृति से उनसे आग्रह करके इन्वैस्टमैंट करवा के पूरे उत्तरी भारत को ही नहीं समस्त भारत वर्ष को बिजली दी जा सकती है। इस तरह के सराहनीय प्रयास आज हमारी वर्तमान सरकार कर रही है और मैं चाहूंगा कि और शीघ्रता से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से सस्ती बिजली उपलब्ध करवा कर चौधरी देवी लाल जी 24 घण्टे बिजली देने के लिए प्रयासरत थे और उसमें उन्होंने काफी हद तक सफलता भी पाई थी। आज के हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने 32% उत्पादन बढ़ा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और आगे चल कर 24 घण्टे बिजली मिलेगी। कोई भी किसान, कोई भी उपभोक्ता, कोई भी कन्जयूमर और कोई भी इण्डस्ट्रियलिस्ट जब भी बटन दबाए मैं समझता हूं कि उसको बिजली उपलब्ध हो, यह आज देश की अनिवार्यता है और हमारी सरकार इसके लिए सतत प्रयासरत है।

श्री उपाध्यक्ष : रावत साहब, आप प्लीज़ पांच मिनट में वाईड अप करें।

श्री भगवान सहाय रावत : उपाध्यक्ष महोदय, जब आपका आदेश होगा मैं बैठ जाऊंगा मैं तो नियमों का पाबन्द हूं। इसके साथ ही दो-तीन प्वायंटस और हैं जो महामहिम राज्यपाल महोदय के एड्रैस में सम्मिलित हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। औद्योगिक दृष्टि से बहादुरगढ़, बादली, गुडगांव और सोनीपत की मांग को देखते हुए जो औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित की गई हैं उनकी भूमि ग्रहण की जा रही है, मैं समझता हूं औद्योगिक क्षेत्र में यह एक प्रशंसनीय काम है। मेरी सरकार, आज की वर्तमान सरकार द्वारा इटली सरकार की सहायता से हमारे जिले फरीदाबाद में 13 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से श्रमिक डिवैल्पमैंट सैंटर स्थापित किया जा रहा है जो कि निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य है। आज जन-स्वास्थ्य जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जल संकट से बचने के लिए मैं समझता हूं कि केन्द्र की एक सूझ-बूझ होनी चाहिए थी। इस बारे में हरियाणा सरकार ने एक प्रशंसनीय कदम उठाया है। पीने के पानी के संकट के बारे में जहां तक मेरी दृष्टि जाती है आने वाले समय में पीने के पानी की दिक्कत आ सकती है। इसको दृष्टिगत रख कर जहां हमारी सरकार ने 55-70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति तक बढ़ाया है, यह इस बात को इंगित करता है कि हमारी सरकार इस बारे में सचेत है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां पर अनेक बूस्टरज़ बनाए गए हैं और नई-नई वाटर वर्क्स और स्कीम्ज़ बनाई गई हैं। मेवात क्षेत्र में मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड के अन्तर्गत उनके वाटर सप्लाई स्कीम्ज़ और उनके बूस्टरज़ बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि औरंगाबाद, मितरौल और बहीन में जो बूस्टरस बन कर तैयार हो गए हैं उनको जितना जल्दी चालू किया जाए उतना ही जल्दी उनसे लोग लाभान्वित होंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बचारी और सौंध दो बहुत बड़े गांव हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वहां पर 6-6 हजार वोट्स हैं लेकिन उन गांवों में पिछले 55 सालों की सरकारें पीने के पानी की व्यवस्था करने में असफल रही हैं। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को यह श्रेय जाता है कि उन दोनों गांवों में बुस्टरस बन कर तैयार हैं और इंडिविजुअल पानी के कनैक्शन्ज़ भी दिये जा रहे हैं, इससे ज्यादा जनस्वास्थ्य विभाग की प्रगति का द्योतक नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार स्वच्छ जल उपलब्ध करवा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज़ और है जिसे अगर मैं नहीं

[श्री भगवान सहाय रावत]

कहूंगा तो मैं अपने फर्ज से कोताही करूंगा, वह है सड़कों की बात। माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि सन् 1987 में 50 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया था जिनका अगर मैं नाम लूंगा तो काफी समय लग जाएगा। 12 वर्ष के समय में उन पर कोई रिपेयर का काम नहीं हुआ है। आदरणीय बंसी लाल जी के समय में एक भी नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और एक भी सड़क की रिपेयर नहीं की गई है। वर्तमान सरकार ने उन 12 वर्षों के गन्दे को बाहर करके पूरे हरियाणा में सड़कों का जाल बिछा दिया है। नई सड़कों का निर्माण करवाया है और पुरानी सड़कों की रिपेयर करवाई है। मैं आपके माध्यम से कुछ कन्स्ट्रक्टिव सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं जब भी डिस्कशन करता हूं तो सरकार की प्रशंसा करता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी बहुत सजग हैं और वे हर विधायक से राय लेते हैं। उन्होंने हमारी बात सुनकर आदेश दिए कि जिन गांवों में सड़कें नहीं हैं वहां सड़कें बना दी जाएं और जहां जहां से सड़कें गुजरती हैं वहां-वहां पर नालियां भी बना दी जाएं ताकि सड़कें बार-बार न टूटें। मैं आपके माध्यम से विभागीय अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि सड़क बनाने से पहले सड़कों के किनारों पर नालियां बनाने के बारे में मुख्य मंत्री जी ने जो आदेश दिए थे उनकी पालना की जाए। मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि जहां पर पानी ठहरता है, वहां पर नालियां बनाई जाएं ताकि बार-बार सड़कें नहीं टूटें इससे जनता का तथा सरकार का पैसा बचेगा। इसी तरह से मैं परिवहन के बारे मे भी कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा स्टेट का परिवहन विभाग सबसे अच्छी व्यवस्था के लिए जाना जाता था। लेकिन बाद में ऐसा समय भी आया जब हरियाणा की बसें सड़कों पर दिखाई देनी बंद हो गईं, उसके सब्स्टीच्यूट में जो प्राइवेट बसें सड़कों पर चलाई गईं उनके भी ढांचे कहीं पर नहीं दिखाई दिए। वे बसें अच्छे रूटों को चुनकर चलने लगी जिनके कारण हमारी आम जनता दुखी होने लगी। वर्तमान सरकार ने जहां सड़कों का निर्माण किया है वहीं पर परिवहन व्यवस्था को नया जीवनदान दिया है। आज हरियाणा की ऑर्डिनरी बसिज़ के बारे मे गलतफहमी पैदा होती है क्योंकि कई बार यात्री यह समझ नहीं पाता कि यह डीलक्स बस है या ऑर्डिनरी बस है। मैं समझता हूं कि हमारी ऑर्डिनरी बसें दूसरे प्रदेशों की डीलक्स बसों से भी बेहतर ढंग से दौड़ती हैं। जिस वजह से हरियाणा का सीना चौड़ा हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने परिवहन मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। एक बार मैं, उदय भान जी और राजेन्द्र सिंह बिसला जी मंत्री जी के पास बैठे हुए थे और हमारे जरा से आग्रह करने पर उन्होंने डीलक्स बसें चलाने के लिए आदेश दिया था। उन्होंने तुरंत उस बात को मान कर के अपने विभाग को आदेश दिए और उनके विभाग ने उन आदेशों की पालना करके गुडगांव और फरीदाबाद के लिए डीलक्स बसों की व्यवस्था कर दी। निश्चित रूप से वे अपने आदेश की पालना करवाने में सक्षम हैं और उनका विभाग बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे बसें पलवल तक बढ़ाई जाएं ताकि जो लोग पलवल से आते हैं वे भी उन बसों में सफर कर सकें। इसके अलावा वे बसें आगरा तक भी चलाई जाएं जिससे टूरिस्ट भी उन बसों में सफर कर सकें और हरियाणा प्रदेश की बसों की आमदनी बढ़ सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने परिवहन व्यवस्था को पटरी पर लाकर हरियाणा प्रदेश का नाम प्रति किलो मीटर लागत के हिसाब से सबसे ज्यादा लाभ कमाकर देश में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। माननीय परिवहन मंत्री, अरोड़ा जी और

माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात का श्रेय जाता है कि उनके मार्गदर्शन में यह सारा विकास कार्य चल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। आज प्राइमरी एजूकेशन, मिडिल एजूकेशन, सीनियर सैकेंड्री एजूकेशन और उच्च विद्यालय की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आज हरियाणा में ग्यारह हजार तेरह प्राथमिक विद्यालय, एक हजार आठ सौ सतासी माध्यमिक विद्यालय, उन्तीस सौ उच्च विद्यालय और एक हजार दो सौ अठत्तीस सीनियर सैकेंड्री विद्यालय चलाए जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हमारी सरकार ने किया है। हमारे यहां पर कुरुक्षेत्र, गुरू जम्भेश्वर, रोहतक और हिसार की चार यूनिवर्सिटीज हैं। आज कुरुक्षेत्र और रोहतक की यूनिवर्सिटी के सिलेबस में समानता ला दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने पहले भी कहा कि मैं विधायक बनने से पहले एक शिक्षक रहा हूं। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज की तारीख में हमारे कुशाग्र बुद्धि के बच्चे आई0ए0एस0 और एच0सी0एस0 की परीक्षाओं में बैठते हैं। विशेषकर जब हमारे विद्यार्थी ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 की परीक्षा देने जाते हैं तो वहा के विद्यार्थियों के मुकाबले में अपने को बराबर नहीं पाते हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां पर उन्होंने यूनिवर्सल रूप में सिलेबस को कॉमन किया है वहीं मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में, किसी उच्च पदस्थ अधिकारी के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहर लाल यूनिवर्सिटी भेजी जाए। यह टीम दोनों यूनिवर्सिटीज के सिलेबस का अध्ययन करने के बाद हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को पुनः संशोधित करे। इन दोनों यूनिवर्सिटीज का सिलेबस लगभग वही होता है जो आई0ए0एस0 की परीक्षा के लिए होता है जबकि हमारे यहां की यूनिवर्सिटीज का सिलेबस दूसरा होता है। इससे होता यह है कि एक विद्यार्थी को डबल बर्डन पड़ता है क्योंकि पहले तो वह यहां की यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ता है और जब वह दूसरे इम्तहानों मे बैठता है तो उसे लगता है कि मैंने तो कोई पढ़ाई ही नहीं की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका सहयोग चाहते हुए आपके माध्यम से इस हाउस से भी एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने यह बात पिछले सैशन में भी कही थी। जब चौधरी देवीलाल जीवित थे तब भी मैंने श्री ओम प्रकाश चौटाला जी से, उनकी सरकार से, आपकी सरकार से अनुरोध किया था कि चौधरी देवीलाल जी केवल इस प्रदेश के या देश के ही नहीं रह गये हैं बल्कि अब तो उनका नाम महात्मा गांधी के बाद विश्व स्तर पर लिया जाने लगा है इसलिए उनके नाम से किसी सैंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जानी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि अरावली हिल्ज पर, जहां से आपका जिला और मेरा जिला लगता है वहां पर हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है जहां पर इस तरह की यूनिवर्सिटी बनायी जा सकती है। यह इलाका दिल्ली की सीमाओं से भी सटा हुआ है। वहां इस तरह की सैंट्रल यूनिवर्सिटी बनायी जाए जिस में दिल्ली की जवाहर लाल यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनियर्सिटी के समकक्ष हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा दिलायी जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : रावत साहब, आपको बोलते हुए 32 मिनट्स हो गये हैं इसलिए अब आप वाईंड अप करें।

श्री भगवान सहाय रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट का समय और लेना चाहूंगा। मैं एक दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे चंद मिनट्स और बोलने के लिए दिए जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह

[श्री भगवान सहाय रावत]

से समाज कल्याण का विषय आता है। जब हम समाज कल्याण के विषय पर बात करते हैं तो चौधरी देवीलाल जी का नाम अनायास ही हमारी जिह्वा पर आ जाता है। यह मैं किसी अतिश्योक्ति या अलंकार का उपयोग करते हुए नहीं कह रहा हूं। जब समाज कल्याण में विधवा पैंशन, अपंग पैंशन की बात आती है, तो उनका नाम स्वतः ही आ जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, पाश्चात्य जगत वाले अपने को हमसे कई साल एडवांस समझते हैं उनका प्रजातंत्र भी हमारे से कई साल पुराना है। इसी तरह से हमारे यहां की पश्चिमी बंगाल की सरकार भी अपने आप को बहुत प्रगतिशील सरकार मानती है लेकिन भारतवर्ष के किसी राजनीतिज्ञ के, किसी विचारक के दिमाग में यह बात नहीं आयी कि जैसे सरकारी मुलाजिमों को रिटायरमैंट के बाद पैंशन मिलती है उसी तरह से वृद्धों को भी अपने व्यवसाय में कार्य करते हुए पैंशन मिलनी चाहिए। इस तरह के वृद्ध बुढ़ापे में आश्रित तो रहते हैं लेकिन उनकी भी कुछ आकांक्षाएं होती है। जब वे अपने बच्चों, बेटियों या पोतियों के साथ मधुर संबंधों के कारण अपनी जेब से कुछ देना चाहते हैं तो वे अपने आपको असहाय महसूस करते हैं। उनकी इस पीड़ा को चौधरी देवीलाल जी ने समझा और उसको दृष्टिगत रखकर वृद्धों को पैंशन दी। यह पैंशन उनको गुजारे भत्ते के रूप में नहीं बल्कि एक सम्मान के रूप में दी गयी। इस तरह का उदाहरण दुनिया की धरती पर कहीं भी आपको नहीं मिल सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज भी वह क्षण याद है। जब चौधरी देवीलाल जी के अंतिम दिनों में उनका जन्म दिन मनाया जाना था। जब उनको लोग कहने लगे कि आप चलिए आपका जन्म दिन मनाया जा रहा है तो उन्होंने वहां पर जाने से मना कर दिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जब तक वृद्धों की पैंशन और नहीं बढ़ेगी तब तक आप मेरे जन्म दिन को क्या मनाओगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि सरकार ने वृद्धों की पैंशन दुगनी करने का काम किया था। यह अंतिम समय में उस महान नेता की वृद्धों के प्रति श्रद्धांजलि थी, उनके प्रति सम्मान की दृष्टि थी। उन्होंने मरते दम तक अपनी प्रिय जनता के सुख दुख को नहीं छोड़ा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वर्तमान सरकार के द्वारा उन वृद्धों के सम्मान में ताऊ जी के मार्ग दर्शन को ध्यान में रखते हुए गांव-गांव में वृद्ध गृह खोले जा रहे हैं। आज सरकार इन गृहों की देखभाल को उचित प्राथमिकता भी दे रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 265 नये 'ताऊ देवीलाल गृहों' का निर्माण किया गया है और 248 इस तरह के और वृद्ध गृहों का निर्माण करने का प्रावधान है।

श्री उपाध्यक्ष : रावत साहब, अब आप वाईड अप करें।

श्री भगवान सहाय रावत : सर, एक और बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ग्रामीण विकास और पंचायत की बात मैं और कहना चाहूंगा। जहां पर लोकल बॉडीज या पंचायती राज इंस्टीच्यूशंज को अनेक वित्तीय अधिकार देकर सरकार ने नयी शुरूआत की है उसके लिए भी वर्तमान सरकार बधाई की पात्र है। पिछली सरकारें देश में बात तो जनतंत्र की करती रहीं लेकिन जो जनता गांवों में बसती है छोटे छोटे कस्बों में बसती है वह सही मायने में भारत वर्ष की जनता है उनको वह अधिकार नहीं दे सकी थी जो वर्तमान सरकार ने दिये हैं। ग्राम पंचायतों को और स्थानीय संस्थाओं को अधिकार दिये गये हैं और उनकी नयी डिवेलपमैंट कमेटी बनाकर जनतंत्र में उनकी सही भागीदारी की है। इलैक्टिड आदमियों के साथ सहयोग करने के लिए गांव के कुछ अन्य लोगों को भी सम्मिलित किया गया है विपक्ष ने इस बात को दूसरे तरीके से लिया है और कहा है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ यह गलत है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उसी

निर्वाचित सरपंच की अध्यक्षता में वह कमेटी गठित की गई है उसमें से एक हरिजन को लिया, एक बैकवर्ड को लिया, एक महिला को लिया और एक भूतपूर्व सैनिक को लिया इससे ज्यादा समन्वित और अच्छी कोई कमेटी गठित नहीं हो सकती थी। यह इसमें मील का पत्थर साबित किया है अगर मैं सारे आंकड़ों को यहां देने लग जाऊं तो विपक्ष के साथियों के लिए यहां जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इनके लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज कानून अवस्था के मामले में हरियाणा प्रदेश अग्रणी है औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी हरियाणा प्रदेश अग्रणी है, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है हरियाणा प्रदेश सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में काम करने जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब चौधरी बंसी लाल जी बोलेंगे।

चौ0 बंसी लाल (भिवानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करूंगा। इसमें जो सबसे पहला आइटम है उसमें राज्यपाल महोदय ने एस0वाई0एल0 का जिक्र किया है। एस0वाई0एल0 के बारे में इस मौजूदा सरकार ने क्रेडिट लेने की कोशिश की जबकि इनका इसमें कोई योगदान नहीं है। यह केस सुप्रीम कोर्ट में मेरी सरकार ने दायर किया और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। हरियाणा प्रदेश को पानी देने का जो फैसला किया गया वह 24 मार्च, 1976 को किया गया जब मैं रक्षा मंत्री था। हरियाणा प्रदेश को मैंने पानी दिलवाया उससे पहले इसका जिक्र ही नहीं था। मुख्यमंत्री जी आज यहां नहीं हैं कल आ जाएंगे वे हमेशा इस देश में एक बात कहते रहे कि चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा प्रदेश के हिस्से वाली एस0वाई0एल0 को बनाया अगर वह एस0वाई0एल0 मैं न बनाता तो हमको आज पानी नहीं मिलता। आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम उसकी मरम्मत का प्रोग्राम बना रहे हैं और उसके लिए 10 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि पंजाब वाले जब अपना काम शुरू कर दें तब ये मरम्मत का काम शुरू करें उससे पहले काम शुरू करने से कोई फायदा नहीं होगा।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी अब उलट बात कह रहे हैं पहले ये कहते थे कि पहले बनाते अब कहते हैं कि मरम्मत बाद में कराएं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अभी चौधरी बंसी लाल ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहते रहे हैं कि पहले इनको हरियाणा पोर्शन की बजाय पंजाब पोर्शन बनाना चाहिए था। यह कहा है यह नहीं कहा है कि हरियाणा पोर्शन नहीं बनाना। आपको पता है कि उस टाइम इस इशू का कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ था। यह इशू मेरिट पर लिया जा रहा था उस वक्त माहौल बढ़िया था उस वक्त पंजाब पोर्शन में बन जाती। उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा यह सिद्धांत है कि अगर कोई नहर बनानी हो, कोई खाला बनाना हो या कोई डिस्ट्रीब्यूटरी बनानी हो तो उसको हैड साइड से बनाना शुरू किया जाता है। जब हालात पोलीटिकल हो जाते हैं। मैरिट पर उसे बनाना मुश्किल होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उस समय पंजाब का पोर्शन बनाया जाता तो आज यह झगड़ा नहीं होता। पंजाब का पोर्शन पहले बनना चाहिये था। पंजाब का पोर्शन न बनाने से चौधरी बंसीलाल जी इसके लिए कुछ भी कहें इतिहास इनको हमेशा इस बात का दोषी मानता रहेगा। पंजाब पोर्शन पहले बनना चाहिये था। आज आप कह रहे हैं कि जो हरियाणा का पोर्शन है उसकी मरम्मत नहीं होनी चाहिये। मरम्मत के लिए एस्टिमेट बनाया जा चुका है सर्वे कराया गया है और यह अनुमान लगाया गया है कि प्रदेश को इससे कितना नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से चौ0

[प्रो0 सम्पत सिंह]

बंसी लाल जी ने बनाया था वह लगभग दोबारा से बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा का पोर्शन बनाने के लिए हरियाणा सरकार पर उत्तरदायित्व डाला है और पंजाब का पोर्शन बनाने के लिए पंजाब सरकार पर उत्तरदायित्व डाला है। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया भी इसके लिए पैसे देती है, कंट्रीब्यूट करती है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आ चुके हैं। चौधरी बंसीलाल जी, आपकी सरकार ने बकायदा इस केस की पैरवी की है। स्टेट के इंट्रस्ट में जिस हालात में कामयाबी मिली है उसके लिए वर्तमान सरकार को सारा श्रेय जाता है। जो केस कोर्ट में डाला जाता है सारे तथ्य सामने रख कर डाला जाता है और सारे फैक्ट्स को सामने रखा जाता है। जो वकील किया जाता है उसका भी ध्यान रखा जाता है कि वह किस तरह से केस को कोर्ट में पुट करेगा। यह स्वाभाविक है कि जिस सरकार के समय में फैसला आयेगा श्रेय उसी सरकार को मिलेगा। चौधरी बंसीलाल जी, आप जो भी कहें आपसे पहले भी चौधरी देवीलाल जी यह केस कोर्ट में डाल चुके थे। चौधरी भजनलाल जी ने इस मामले को अच्छी तरह से टेक अप नहीं किया नहीं तो यह फैसला तो आज से दस साल पहले ही हमारे हक में हो सकता था और हरियाणा का हक दस साल पहले मिल जाता।

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये माननीय सदस्य बीच में तकरीर करना चाहते हैं तो पहले एक घण्टा इन्हीं को बोल लेने दें। उपाध्यक्ष महोदय, अब इस अभिभाषण में एक चीज आई है। यह कहते हैं कि हमने दो शूगर मिल लगाई हैं। ठीक है इन्होंने दो शूगर मिल लगाई हैं। लेकिन मैंने सुना है कि सिरसा जिला में पन्नीवालामोटा में जो शूगर मिल लगाई है वह बन्द होने वाली है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को कहें कि अगर इन्होंने बीच में तकरीर करनी है तो मैं बैठ जाता हूं। मैंने तो इनके बोलते समय कोई तकरीर नहीं की। इसके अलावा एक चीज यह आ गई कि कालेजों और स्कूलों में शिक्षकों के पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं। इसमें यह लिखा है कि हमने कम्प्यूटर शिक्षा चालू कर दी है। इसके लिए मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि प्रदेश में कितने कालेजों और कितने स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा चालू की गई है। क्या उन स्कूलों और कालेजों में बिजली उपलब्ध है, क्या बिजली रोजाना मिलती है ? इसके अलावा मैं हाउस टैक्स के बारे में चर्चा करूंगा। हाउस टैक्स जो लगाए गये हैं मैं समझता हूं कि बहुत से लोग हाउस टैक्स नहीं दे सकेंगे। सोनीपत में एक दुकान का किराया तो आता है 700/- रुपये और उसका हाउस टैक्स है 2200-2300/-रुपये। इसलिए उस दुकानदार को तो दुकान को ही छोड़ना पड़ेगा इसके अलावा वह क्या करेगा ? उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार ने लिखा है कि पानीपत रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। अभी दो-तीन महीने पहले मैंने अखबार में पैट्रोलियम मंत्री का ब्यान पढ़ा था उस ब्यान में यह आया था कि हम पानीपत रिफाइनरी की एक्सपैंशन नहीं करेंगे क्योंकि हरियाणा सरकार से हमारा झगड़ा है। मैं जानना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार से 4 प्रतिशत ऐण्ट्री टैक्स का झगड़ा चल रहा है क्या वह झगड़ा खत्म हो गया है ? क्या सरकार ने भारत सरकार से कोई एम0ओ0यू0 साईन किया है ? अगर एम0ओ0यू0 साईन किया है तो वह क्या साईन किया है ? उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह भी लिखा है कि सड़कों की मरम्मत और सड़कों को बनाने के लिए मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 137.64 लाख रुपये खर्च किये और 363.42 लाख रुपये से 4464 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण की योजना है। तो इसमें ये क्या क्रैडिट ले रहे हैं ? 300 रुपए तो मेरी सरकार छोड़ कर गई थी, इन्होंने क्या किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : बंसी लाल जी, आप 300 करोड़ रुपये की जगह 300 रुपये कह रहे हैं, शायद आपसे भूल हो गई है।

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 300 करोड़ रुपये ही कहना चाहता हूं। यहां सिंचाई की बात आई है, सिंचाई के बारे में इन्होंने क्या दिया है ? सिंचाई विभाग ने 394 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से पूर्ण होने वाले 9 प्रोजैक्ट स्वीकृत किए हैं। इनमें से 299 स्कीमें सिंचाई विभाग से सम्बन्धित हैं और 212 स्कीमें जल निकासी से सम्बन्धित हैं। इनके अन्तर्गत मुख्य योजनाएं बरसोला फीडर, महम तथा लाखन माजरा ड्रेनें हैं जो पूर्ण हो चुकी हैं। रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, दड़बा घग्घर ड्रेन, बसेर नथौर लिंक ड्रेन ये सब मेरे ही किए हुए हैं फिर ये किस चीज का क्रैडिट ले रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। चौधरी बंसीलाल जी जो यह कह रहे हैं कि ये सारे काम मेरे किए हुए हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के लिए लैण्ड एक्वीजिशन नवम्बर, 1962 में हुई थी उसके बाद 11 साल तक माननीय सदस्य चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन उन फाइलों का पता ही नहीं चला कि वे कहां गई ?

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये सब स्कीमें मेरे वक्त की तैयार हुई हुई हैं। बड़सौला माइनर तैयार हो गई थी, महम की दोनों ड्रेनें तैयार हो गई थीं सिर्फ बहुअकबरपुर के लोगों ने वह ड्रेन निकालने नहीं दी, कुछ काम उसका बाकी था, वैसे मैंने दोनों ड्रेनों का काम पूरा करवा दिया था। रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन की फांउडेशन मैंने ही रखी थी, नाबार्ड से कर्जा मैं लाया और इसका काम मैंने चालू कर दिया था। इसी तरह दड़बा घग्घर ड्रेन, हिसार से घग्घर ड्रेन प्रोजैक्ट मेरे ही तैयार किए हुए हैं फिर ये किस चीज का क्रैडिट ले रहे हैं (शोर) । उपाध्यक्ष महोदय, रामकली माइनर का काम मैंने शुरु कर दिया था, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ये कहकर क्रैडिट ले रही है कि हमने 621 मेगावाट बिजली की वृद्धि कर दी, कहां कर दी, इसका कोई पता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी जानते हैं और दूसरे लोग भी जानते हैं कि 432 मेगावाट का काम मैंने ही शुरु किया था। इसके 2 प्लांट आ गए थे और तीसरा इनकी सरकार में कमीशन हुआ है लेकिन उसका काम मेरे ही वक्त में चालू हो गया था। उपाध्यक्ष महोदय, 210 मेगावाट का पानीपत का छठा थर्मल प्लांट मैने ही शुरु किया था, आधे से ज्यादा बन कर तैयार हो गया था, खाली कूलिंग प्लांट का काम बाकी बचता था। गुड़गांव में 25 मेगावाट का मैगनम का यूनिट भी मेरे वक्त में लगा था। इन्होंने कहा है कि 250-250 मेगावाट के दो अतिरिक्त सैन्टर लगाने का काम पानीपत में शुरु हो चुका है तो मैं इस सरकार से पूछना चाहूंगा कि मौके पर क्या काम शुरु किया गया है, क्या कोई ईंट, पत्थर, रोड़ा लगाया गया है जिससे माना जाए कि काम चालू हो गया है, यह मैं चौधरी सम्पत सिंह जी से और मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो 50 फीडर के बारे में कह रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसके मैटीरियल का आर्डर मेरी सरकार के वक्त में हो गया था कि ये 50 फीडर स्ट्रैंथन करने हैं। ये किस चीज का क्रैडिट ले रहे हैं मुझे यह पता नहीं लग रहा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माइन्स एण्ड जियोलिजी विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे जिले भिवानी में एक पहाड़ नीलाम हुआ, अच्छी बात है कि नीलाम हुआ। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन जो पर्ची वहां कट रही है, पहली पर्ची काटता है क्रशर का मालिक। क्रशर वाला जो पर्ची काटता है वह पूरे पैसे ले जाता है और सेल्स टैक्स भी ले लेता है। उसके बाद थोड़े फासले पर जाकर 7 जगह और नाके लगा दिए गए हैं और नाकों

[चौधरी बंसी लाल]

के ऊपर ट्रकों से 1000/-रुपए, ट्रेलर से 2000/- रुपए, टाटा-407 से 500/- रुपए और ट्रैक्टर्ज से 250/-रुपए वसूल किए जाते हैं, ये पैसे उनसे किस चीज के लिए जाते हैं यह बात मैं सरकार से जानना चाहता हूं। गवर्नमैंट ऑफ हरियाणा डिपार्टमैंट ऑफ माईन्स एण्ड जियोलिजी की तरफ से ये पर्चियां काटी जा रही हैं और इसमें एक चीज और लिख रहे हैं, किसी पर्ची में कुछ नहीं लिखते, किसी में लिख देते हैं रॉ मैटीरियल। यह रॉ मैटीरियल की पर्ची कटती है ट्रेलर की 2000/-रुपये की 30 टन वजन के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, क्या ट्रेलर क्रेशर के रैंप के ऊपर 30 टन वजन लेकर चढ़ सकता है, बैक में जा सकता है। क्या कोई ट्रक जो 6 व्हील का होता है वह 16 टन वजन लेकर क्रेशर की रैंप के ऊपर जा सकता है। क्रेशर वाला उसी ट्रक की 250 फिट की पर्ची काट रहा है, उसी ट्रक की उसी टाईम की टैक्स वाले और दूसरे लोग पर्ची काट रहे हैं किस नाम की पर्ची काट रहे हैं इस का पता नहीं वे टोल टैक्स ले रहे हैं या और ले रहे हैं कुछ लोग तो उसको गुंडा टैक्स के रूप में बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह टैक्स किस बात का है? जब एक जगह टैक्स ले लिया क्रेशर वाले ने फिर दूसरी जगह टैक्स क्यों लिया जा रहा है? क्रेशर वाले ने माल की कीमत, ड्राईवर का नाम, क्वांटिटी और सेल्जटैक्स 12 प्रतिशत लिखकर पर्ची काट दी और आगे जब सरकार वाले पहुंचे इन्होंने माल का पैसा फिर से लिख दिया, सेल्जटैक्स का पैसा फिर से लिख दिया। वे दो पर्ची देते हैं एक पर्ची देते हैं मालिक के पास रहने के लिए और दूसरी पर्ची देते हैं सेल्जटैक्स विभाग को देने के लेकिन सेल्जटैक्स विभाग वाले यह कहते हैं कि हम यह पर्ची लेने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इनके पास सेल्जटैक्स लाईसैंस का नम्बर नहीं है। सरकार की पर्ची कट रही है और सेल्जटैक्स नम्बर की जगह लिखते हैं अप्लाईड फॉर, कितने दिन तक अप्लाईड फॉर रहेगा। वहां पर हर रोज कम से कम 15 लाख रुपये टोल टैक्स का वसूल किया जा रहा है यह किस कानून के तहत किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ? जब लोगों ने अपने हकों की लड़ाई लड़ी तो वहां पर पुलिस की छावनी बना दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि किस कानून के तहत कैसे वहां बैठे हैं किस कानून के तहत टैक्स वसूल करते हैं ? वहां तीन पहाड़ी ऐसी हैं जिनका ठेका मजदूरों के पास है और एक डेढ़ साल का समय बाकी बचता है फिर भी उनका काम बंद कर दिया और उनका काम बंद करने से पहले उनके पहाड़ से जो माल निकलता था तो ये 1000/-रुपये की पर्ची उनकी भी काटते थे। भिंगाणा में भी 1000/-रुपये की पर्ची काट रहे हैं, नीलामी हुई नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी सिविल नाफरमानी क्यों हो रही है ? कानून के खिलाफ खुल्लम-खुल्ला यानि साहूकारी जैसा टैक्स सरकार क्यों ले रही है ? इस तरह से नाजायज ढंग से लोगों से टैक्स वसूल किया जा रहा है और वहां की पंचायत को उसका करीब एक करोड़ रुपया मिलना चाहिए था लेकिन पंचायत को अभी तक कुछ मिला नहीं ! मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बोली किस तारीख को हुई, किस तारीख को बोली ऐक्सैप्ट हुई और ऐक्सैप्ट होने के बाद गवर्नमैंट के साथ एग्रीमैंट किस तारीख को हुआ और 1000/- रुपये टैक्स का कब से लेना शुरू किया, शुरू से अब तक की पर्ची मेरे पास है सरकार जब जवाब देगी तब मैं सरकार को ये पर्ची दिखाऊंगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं यह कैसे लिया जा रहा हैं, क्यों लिया जा रहा है क्या लोगों से धक्के से वसूल किया जा रहा है ? उपाध्यक्ष महोदय, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के बारे में लिखा है कि इन्होंने इतने गांवों को पानी की इतनी सप्लाई कर दी मेरी इन्फर्मेशन यह है कि हरियाणा सरकार ने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए 1000 से 1500 के करीब शैलो ट्यूबवैल लगाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, शैलो

ट्यूबवैल का पानी पीने के लिए उचित नहीं होता। इससे लोग बीमार होंगे, इनका पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शैलो ट्यूबवैल की जगह डीप ट्यूबवैल बोर कराये जाने चाहिएं इनका पानी पीने के लिए अच्छा होता है। इन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा है कि इनकी सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए पैंशन स्कीम शुरू की है जबकि यह स्कीम हमने 11-5-1998 से ही शुरू कर दी थी, उसका क्रेडिट ये कैसे ले रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, इन्फर्मेशन एण्ड टैक्नोलाजी के बारे जब आप मुझे बजट पर बोलने का समय देंगे उस वक्त बात करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आज भी आपको बोलने के लिए पूरा समय है।

चौ0 बंसी लाल : नहीं, मैं तो उसी वक्त बोलूंगा जब रैलेवैन्ट होगा। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने लिखा है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एम0 पीज0 लोकल डिवैल्पमैंट फण्ड के तहत इतने करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। मेरा कहना यह है कि इसमें हरियाणा सरकार का क्या लेना देना है। यह तो भारत सरकार से सीधा आया है और सीधा एम0 पी अलॉट करता है, खर्च होता है, इसमें सरकार का क्या कन्ट्रीब्यूशन है। (विघ्न) यह कृष्णपाल जी आपको बता देंगे।

श्री चन्द्र भाटिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ बताना चाहता हूं।

चौ0 बंसी लाल : इसको तो आप मेरे लिए रिजर्व रखते हो। (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपका पुराना चहेता भतीजा है। (हंसी)

चौ0 बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक लॉ एण्ड ऑर्डर का सवाल है, आज हरियाणा प्रदेश में लॉ एण्ड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। आज आप मुझे दिन छिपने के बाद बाया गोहाना रोहतक जा कर के दिखा दें, साधारण गाड़ी में जा कर दिखा दें, आराम से चले जाएं, मुझे सही सलामत जा करके दिखा दें मैं मान लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब आप मेरे को कह रहे हो। कल दोनों चलेंगे। कल शाम को छुट्टी हो जायेगी।

चौ0 बंसी लाल : मैं तो ऐसी जगह फंसता नहीं हूं, यह काम आप कर लेना। अब मैं आपके जिले की बात बता दूं। आज आपके जिले में गुड़गांव से नजफगढ़ होकर जो सड़क झज्जर जाती है उस पर भी वारदातों का कोई ठिकाना नहीं है।

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : चौधरी साहब, यह रोड जिसका आप जिक्र करना चाहते हैं वह बाया नजफगढ़ नहीं बल्कि बाया फरुखनगर है।

चौ0 बंसी लाल : हां, फरुखनगर है लेकिन नजफगढ़ में भी ऐसा ही होता है। नजफगढ़ में तो इतने कत्ल हो चुके हैं कि कोई ठिकाना नहीं है। लोग बाहर निकलने से डरते हैं। (विघ्न) आप अपनी बात कह लेना, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, गुड़गांव का तो ऐसा कोई रोड नहीं है, नजफगढ़ तो दिल्ली में से होकर जाता है।

चौ0 बंसी लाल : मैं आपके फरुखनगर की ही बात कह रहा हूं। आपके फरुखनगर से ही होकर यह रोड जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, मैं ऐसी सीट से आया हूं जहां लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति आपके समय में क्या थी और आज क्या है यह मैं अच्छी तरह से आपको बता सकता हूं।

चौ0 बंसी लाल : ये तो आंकड़े ही बता देंगे।

श्री धीर पाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी साहब का राज था जिस सड़क की बात ये कर रहे हैं इनके दामाद के साथ वहां पर घटना हुई थी। इसलिए इनको वह घटना आज तक याद है।

चौ0 बंसी लाल : मेरे दामाद के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

श्री धीर पाल सिंह : चौधरी साहब, आपके दामाद और बेटी उसी रोड से गुजर रहे थे जब वह घटना घटी थी।

चौ0 बंसी लाल : कब की बात है ?

श्री धीर पाल सिंह : आपके नोटिस में होगा ।

चौ0 बंसी लाल : मेरे नोटिस में कोई बात नहीं आई । (विघ्न)

श्री रामकिशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : रामकिशन जी आप बैठिये। बंसी लाल जी आप बोलिये।

चौ0 बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय,आज प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर को सुधारने की जरूरत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पैट्रोलिंग की गाड़ियां लगाई हैं वे नेशनल हाईवे पर लगाई गई हैं। मेरा कहना यह है कि यह पैट्रोलिंग हर सैंसिटिव रोड पर लगाई जायें ताकि लोग आराम से जा सकें इतनी बात कह करके मैं अपना स्थान लेता हूं।

प्रो0 सम्पत सिंह : चौधरी साहब, आप और बोल लीजिए।

चौ0 बंसी लाल : मैं इररेलैवंट तो बोलता नहीं। मैं तो जायज बोलता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप बैठिए। चौधरी साहब को बोलने का पूरा मौका दिया गया है और अब ये अपनी मर्जी से बैठे हैं।

श्री उदय भान (हसनपुर, अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा था उसका धन्यवाद प्रस्ताव श्री निशान सिंह जी ने पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और धन्यवाद करूंगा क्यों कि इसमें एस0 वाई0 एल0 नहर के बारे में बात कही गई है। यह नहर हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा है जिसकी वजह से तमाम दक्षिणी हरियाणा और दूसरे जो हरियाणा के हिस्से हैं उनको पानी मिलना है। इस नहर के बनने से हरियाणा प्रदेश में खुशहाली का नया अध्याय शुरू होगा। इसके सम्बन्ध में सरकार ने बहुत गम्भीरता के साथ कार्य किया है। यह ठीक है कि पहले चौधरी देवी लाल जी इस मामले को अदालत में ले गए थे। इस मामले को कांग्रेस सरकार ने वापिस ले लिया और बाद में चौधरी बंसी लाल जी इसको अदालत में ले तो गए थे लेकिन सही ढंग से यह उसको अदालत में नहीं रख पाए । इस सरकार ने इस में बहुत गम्भीरता से कार्य किया। इस मामले में सरकार के द्वारा जो वकील निर्धारित किए गए थे उन्होंने इस मसले को गम्भीरता के साथ उठाया और इस बात का परिणाम है कि 15 जनवरी को सुप्रीमकोर्ट का फैसला इस बारे में आया। इस फैसले में सुप्रीमकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश

दिए हैं कि वह एक साल के अन्दर-अन्दर सतलुज यमुना नहर को पूरा करवाए और अगर पंजाब सरकार किसी कारण से इसे पूरा करवाने में असमर्थ रहती है तो सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिए हैं कि केन्द्र सरकार इस नहर का काम पूर्ण करवाए। इस सम्बन्ध में मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारिकबाद दूंगा कि उन्होंने इस मामले को बड़ी गम्भीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, जैसे यह फैसला हुआ उन्होंने त्वरित गति से यह फैसला लिया कि हरियाणा के हिस्से में चौधरी बंसी लाल जी के समय में जो नहर बनी थी उसकी शीघ्र ही सफाई की जाए ताकि जब नहर में पानी आए तो वह पानी हमारे किसानों को मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिणी हरियाणा में फरीदाबाद का एरिया आता है। (विघ्न)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : उपाध्यक्ष महोदय, उदय भान जी ने कहा है कि चौधरी देवी लाल जी इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए जब कि इन्होंने केस को वापिस ले लिया। चौधरी देवी लाल जी ने केवल कोर्ट में ही लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि एस0 वाई0 एल 0 को बनाने में उनका बहुत अहम् रोल भी था। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : माजरा जी, इस मामले को चौधरी बंसी लाल जी बड़ी गम्भीरता से ले रहे हैं इसलिए वे हाउस से बाहर जाते हुए इस ईशू पर वापिस आ गए हैं।

श्री रामपाल माजरा : चौधरी बंसी लाल जी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए इस सदन में 13 जुलाई को जो भाषण दिया था उसकी दो-चार लाईनें मैं पढ़ देता हूँ। इन्होंने अपनी सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में कहा था जब चौधरी भजन लाल को वे कह रहे थे नहर को मैंने बनवाया। चौधरी बंसी लाल जी ने इस बात को क्लीयर करते हुए कहा था कि सब कहते हैं मैंने बनवाई मेरे पास चौधरी बंसी लाल जी की स्पीच है इसमें इन्होंने कहा 31 मार्च, 1979 तक की सी0ए0जी0 की रिपोर्ट नं0 3 है। इस रिपोर्ट के पेज नं0 91 पर एस0वाई0एल0 के बारे में लिखा है कि मार्च, 1995 तक अर्थ वर्क हुआ 116.86 क्यूसिक मीटर और मार्च, 1986 तक हुआ 191.74 मिलियन एकड़ फीट । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 191.74 मिलियन एकड़ फीट वर्क है, यह काम 42% बैठता है। इसके साथ जो लाईनिंग है वह मार्च 1986 तक 109 क्यूसिक फिट हुई जो सिर्फ 2% बैठती है। उसके बाद चौधरी भजन लाल की छुट्टी हो गई और उसके बाद मैं आया। अर्थ वर्क 42% मैंने करवाया । 1987 तक यह काम 376.32 यानि 74% हो गया। इसका मतलब यह है कि 123 मिलियन क्यूसिक फिट के करीब एक साल में काम हुआ। फिर रही बात लाईनिंग की इनके वक्त में एक लाख नौ हजार एक सौ स्कवेयर मीटर फीट कार्य हुआ यानि 2% मेरे वक्त में एक साल में बढ़ कर 75.575 मिलियन एकड़ फुट कार्य हुआ जो 29% है। उसके बाद चौधरी देवी लाल जी आए उनकी सरकार के टाईम में लाईनिंग का काम 91% तक चला गया और अर्थ वर्क 92 तक चला गया जो रिकार्ड की बात है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, "यह बात माननी पड़ेगी कि ज्यादा काम 1987 के बाद की सरकार ने किया। ऐसा नहीं है कि मुझे चौधरी देवी लाल जी की सरकार से मोहब्बत हो गई है। असलियत यह है कि चौधरी देवी लाल, की सरकार के वक्त में ज्यादा काम हुआ है।" उपाध्यक्ष महोदय, यह बात चौधरी बंसी लाल जी ने कही थी।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री बंसी लाल एम0एल0ए0 द्वारा

चौ0 बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पर्सनल एक्सपलनेशन है। उपाध्यक्ष महोदय, यह

[चौ0 बंसीलाल]

बात ठीक है कि मैंने सदन में यह बात कही थी। लेकिन जब मैंने यह बात सदन में कही थी तो उस वक्त मुझे बताया गया कि मैंने यह जो आंकड़े पढ़े हैं वे सही नहीं हैं। चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी साहब ने जो आंकड़े पढ़े हैं ये 1991 के पढ़े हैं। मैंने अपनी तसल्ली के लिए विद्या चरण शुक्ला जी, जो कि उस वक्त की भारत सरकार में सिंचाई मंत्री थे, को चिट्ठी लिखी और उनका जवाब मेरे पास आया। उनका वह जवाब अप्रैल, 1992 का लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा कि प्रिय बंसी लाल जी, सतलुज यमुना लिंक नहर, पंजाब राज्य क्षेत्र के विषय पर अपने पत्र दिनांक 25 फरवरी, 1992 का अवलोकन करें। उपलब्ध सूचना के आधार पर इस नहर पर मिट्टी और लाईनिंग के कार्य पर जो प्रगति हुई है वह संलग्न विवरणों पर दर्शाई गई है। मासिक खर्चों के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण वार्षिक आंकड़े भेजे जा रहे हैं। मासिक खर्चों के आंकड़े उपलब्ध होने पर आपको भेज दिए जाएंगे। देरी के लिए खेद है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह चार्ट है इसमें उन्होंने प्रोगैस आफ अर्थ वर्क इन लाख क्यूबिक मीटर और प्रोगैस ऑफ लाईनिंग इन लाख स्क्वेअर मीटर लिखा है। उपाध्यक्ष महोदय, अप्रैल से जून तक 40 करोड़ 27 लाख रुपये मेरे से पहले 2 महीने में खर्च हो गए थे। मैं जून में आया था और एक महीने में मैंने 13 करोड़ रुपये लगाए हैं। जुलाई से सितम्बर में 30.49 लाख क्यूबिक मीटर, अक्तूबर से दिसम्बर में 43.39 लाख क्यूबिक मीटर, जनवरी से मार्च, 1987 में 30.53 लाख क्यूबिक मीटर, अप्रैल से जून, 1987 में 19.88 लाख क्यूबिक मीटर पर काम करवाया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह टोटल 137.29 लाख क्यूबिक मीटर कार्य बनता है। चौधरी देवी लाल जी के वक्त में जुलाई से सितम्बर तक 15.01, अक्तूबर से दिसम्बर तक 17.27, जनवरी से मार्च, 1988 में 13.23, अप्रैल से जून, 1988 तक .49, जुलाई से सितम्बर, 1988 तक 1.01, अक्तूबर से दिसम्बर, 1988 तक 88.25, जनवरी से मार्च, 1989 तक 3.58, अप्रैल से जून, 1989 तक 6.69, अक्तूबर से दिसम्बर, 1989 तक .63, जनवरी से मार्च, 1990 तक 2.01, अप्रैल से जून, 1990 तक 2.84 क्यूबिक मीटर पर काम करवाया गया था। यह टोटल 67.01 क्यूबिक मीटर बनते हैं। मेरे राज में जो काम हुआ है वह 137.29 लाख क्यूबिक मीटर बनते हैं। ये फिगर्ज उस समय के भारत सरकार के सिंचाई मंत्री द्वारा भेजे हुए फिगर्ज हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि जो बात पहले आपने हाउस में कही है और आपने बताया कि वह सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में है क्या वह आपने नहीं कही थी ?

चौ0 बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, वह बात भी मैंने हाउस में ही कही थी और जो बात आज कह रहा हूं वह भी हाउस में ही कह रहा हूं और भारत सरकार के हवाले से कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, उस वक्त जो बात आपने कही थी क्या आपने बाद में उसको विदड्रा किया था ?

चौ0 बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, विदड्रा करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। सी0ए0जी0 की अलग रिपोर्ट है और जो रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ी है, वह भारत सरकार में उस वक्त के सिंचाई मंत्री जी की है जोकि ऑफिशियल डाकुमैंट है। अगर ये चाहते हैं तो ये उसको फाईल पर पढ़ सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है चौधरी साहब, आप बैठ जाएं।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, ये लाइनिंग के बारे में बताएं।

चौ० बंसी लाल : लाईनिंग के बारे में मैंने हिसाब लगा लिया है। यह टोटल 50.15 लाख स्क्वेअर मीटर हैं। यह फिगर चौधरी देवी लाल, चौधरी भजन लाल और मेरे वक्त के हैं। अलग अलग का हिसाब मैंने नहीं लगाया है।

प्रो० सम्पत सिंह : आप अलग अलग करके बता दें।

चौ० बंसी लाल : इस बारे में अगर मैं अलग अलग बताऊंगा तो भी लाइनिंग पर हुआ काम भी मेरे वक्त में ज्यादा हुआ निकलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब आप स्थान लें। सम्पत सिंह जी जब आप रिप्लाई देंगे तो आप इस बारे में बता देना।

चौ० बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अप्रैल, 1986 से जून, 1986 तक लाइनिंग का काम 2.149 क्यूबिक मीटर हुआ, जुलाई 1986 से सितम्बर, 1986 तक 1.149 क्यूबिक मीटर हुआ, अक्तूबर, 1986 से दिसम्बर, 1986 तक 4.301 और जनवरी, 1987 से मार्च, 1987 तक 6.843, अप्रैल, 1987 से लेकर जून, 1987 तक 7.118 क्यूबिक मीटर काम हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यह काम मैंने तेजी से शुरू करवाया था और मैं हरियाणा के पंचों और सरपंचों को वह काम दिखलाकर लाया था। इनके वक्त में फिर जुलाई, 1987 से लेकर दिसम्बर, 1987 तक 6.542 क्यूबिक मीटर लाइनिंग का काम हुआ। अक्तूबर, 1987 से दिसम्बर, 1987 तक 17.27 और जनवरी, 1988 से मार्च, 1988 तक .20845 एवं जुलाई, 1988 से अक्तूबर, 1988 तक .540 और जनवरी, 1989 से मार्च, 1989 तक .864 एवं अप्रैल, 1989 से जून 1989 तक .744, जुलाई, 1989 से लेकर सितम्बर, 1989 तक .264 और अक्तूबर, 1989 से दिसम्बर, 1989 तक .474 क्यूबिक मीटर का काम हुआ। इसी तरह से जनवरी, 1992 से मार्च, 1992 तक .386 और अप्रैल, 1992 से जून, 1992 तक .378 क्यूबिक मीटर काम हुआ। यानी जो काम करवाने की स्पीड मेरी थी वह दो तीन महीने तक तो चली लेकिन उसके बाद वह प्वायंट पर आ गयी।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, अब आप अपना स्थान लें।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, अभी चौधरी बंसी लाल जी ने जो अपना स्पष्टीकरण दिया, उसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ वर्क के बारे में पढ़ने के बाद जब ये लाइनिंग के बारे में बता रहे थे तो ये हिचकिचा रहे थे। इनकी हिचकिचाहट का कारण यही है मैं इनको बताना चाहता हूं कि जहां तक लाइनिंग वर्क का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि यह काम तीनों सरकारों के वक्त में बराबर का रहा है। लेकिन जहां तक अर्थ वर्क के बाद लाइनिंग का काम है, जो इन्होंने आंकड़े पढ़े हैं उसके हिसाब से भी नियरली 60 परसैंट यह काम चौधरी देवीलाल जी के समय में ही हुआ है। इन्हीं के आकड़ों के मुताबिक जो चिट्ठी सैंट्रल गवर्नमेंट से आयी है उसमें 60 परसैंट लाइनिंग का काम चौधरी देवीलाल जी के वक्त में बताया गया है। सी०ए०जी० की रिपोर्ट का कोई कम महत्व नहीं है और उसको कम नहीं आंका जा सकता। इनके पास जो सैंट्रल गवर्नमैंट के एक मिनिस्टर की चिटठी है इसका मतलब वह चिट्ठी सी०ए०जी० की रिपोर्ट के ऊपर है। ऐसा नहीं हो सकता। सी०ए०जी० की रिपोर्ट तो मंत्रियों के काम करने के बाद या विभागों के काम करने के बाद तैयार होती है। इसलिए ये उस रिपोर्ट को झुठला नहीं सकते। इनका कोई यार बेली दोस्त मंत्री होगा और उसी से ये वह चिट्ठी बनवाकर ले आए होंगे।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, ये फिर भी मार खा गए। इसके अंदर भी चौधरी देवीलाल के समय में ही लाइनिंग का रिकार्ड तोड़ काम हुआ है। इस बात को ये खुद भी मान रहे हैं कि 60 परसैंट काम चौधरी देवीलाल जी के वक्त में ही हुआ है। यह ठीक है कि बाद में वह स्लो इसलिए हो गया क्योंकि पंजाब में उग्रवादियों ने एक चीफ इंजीनियर को वहां पर मार दिया था। हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन लाइनिंग का 60 परसैंट से ज्यादा काम चौधरी देवीलाल जी के वक्त में ही हुआ है। यह बात इनको भी माननी चाहिए।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री उदयभान : उपाध्यक्ष महोदय, अब तो बंसीलाल जी की तसल्ली हो गयी होगी क्योंकि इनको मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया है। बंसीलाल जी को यही नहीं पता कि सी0ए0जी की रिपोर्ट किसी मंत्री की चिट्ठी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है या नहीं। इनको यही नहीं पता कि सी0ए0जी0 की रिपोर्ट ठीक है या मंत्री की चिट्ठी ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय मैं कह रहा था कि एस0वाई0एल0 का पानी आने से दक्षिणी हरियाणा को बहुत भारी लाभ होगा। हमारा फरीदाबाद जिला भी दक्षिणी हरियाणा में ही आता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिले के किसान की हालत भी सिंचाई के मामले में बहुत दयनीय है। वहां की सिंचाई व्यवस्था केवल मात्र आगरा कैनाल पर ही आधारित है और इस कैनाल का पानी पर्याप्त नहीं है तथा वहां पर अंडर ग्राउंड वाटर भी बहुत खारा है। वहां पर मेवात के इलाके में एस0वाई0एल0 कैनाल के माध्यम से जो पानी आएगा उसमें से कुछ पानी गुड़गांव कैनाल में भी आएगा। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिले को पानी का पूरा लाभ मिल सके इसके लिए सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए, इस तरह का कोई प्रोजैक्ट तैयार करना चाहिए क्योंकि वहां पर पानी की भारी बहुत कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से 'सरकार आपके द्वार' जो कार्यक्रम है, यह एक ऐसा जीता जागता सबूत है इसके लिए श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने विकास की गंगा बहाई है जोकि दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण है क्योंकि दूसरे प्रदेशों के लोग भी इस कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। 'सरकार आपके द्वार' में फस्ट फेज में 852 करोड़ 79 लाख और सैकेण्ड फेज में 368 करोड़ 67 लाख व टोटल 1221 करोड़ 46 लाख रुपये इस सरकार ने खर्च किए हैं। 19919 कार्य इस कार्यक्रम के द्वारा हुए हैं। एवरेज माना जाए तो एक कांस्टीच्यूएंसी पर 13 करोड़ 57 लाख रुपये के लगभग खर्च आता है। चौधरी बंसी लाल जी के समय में विकास कार्य पूरी तरह से ठप्प हो गए थे और आज ये कहते हैं कि यह काम भी मेरे समय में हुआ था वह काम भी मेरे समय में हुआ था। उनका साढ़े तीन साल का शासन रहा उसमें किसी भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई, कोई विकास का काम नहीं हुआ। जब बंसी लाल जी मुख्य मंत्री थे तो हर काम के लिए कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुख्यमंत्री बनते ही जिस गति से विकास के काम शुरु किए उससे सभी को पीड़ा होती है। चौटाला साहब ने हर गांव में सड़कें बनाई, स्कूलों में कमरे बनाए, अस्पताल बनाए, सीवर लाइन बनाई, हरिजन बैकवर्ड चौपालें बनाई, वृद्धाश्रम बनाए। (इस समय सभापतियों की सूची में एक सदस्य श्री भगवान सहाय रावत चेयर पर पदासीन हुए।) आज पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर इस कार्यक्रम के तहत विकास कार्य न कराए जा रहे हों। 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में लगभग साढ़े बाइस करोड़ रुपये के काम चल रहे हैं जो एक रिकार्ड है। यदि

तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो चौधरी बंसी लाल जी के शासनकाल से यह लगभग दस गुना ज्यादा है। हालांकि मुख्यमंत्री इस समय मौजूद नहीं हैं परन्तु फिर भी मैं इस अवसर पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इर कांस्टीच्ट्एंसी में लगभग साढ़े 13 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 1996 में एम0एल0ए0 की डिवैलपमैंट ग्रांट चौधरी बंसी लाल जी ने खत्म कर दी थी, इस संबंध में भी पुनर्विचार किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में विचार करें और इस ग्रान्ट को बहाल किया जाए। अगर 50 लाख रुपये एक विधायक के जरिए हल्के में खर्च होते हैं तो उससे विधायक का भी मान सम्मान बढ़ेगा और विधायकों के छोटे-छोटे काम भी हो सकेंगे। चेयरमैन सर, इस सरकार ने बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं तथा बिजली के क्षेत्र को जितनी गंभीरता से लिया गया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। पिछली सरकार ने कागजों में काम किया था लेकिन प्रैक्टिकली काम नहीं किया था। बिजली के मामले में 1998-99 की तुलना में इस सरकार ने इस समय एक प्रशंसनीय काम किया है और प्रतिदिन 111 लाख यूनिट बिजली की अधिक उपलब्धता प्राप्त की है जो अपने आप में एक रिकार्ड है और पहले की बजाये 38 प्रतिशत बिजली का उत्पादन बढ़ा है। उसके लिए बिजली विभाग के अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी सारी टीम की जितनी प्रशंसा की जाये वह कम है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र को बिजली का उत्पादन बढ़ने के कारण 35 प्रतिशत अधिक बिजली दी है। जहां तक ट्यूबवैल कनैक्शंज की बात है, पिछली सरकारों के समय 10-12 साल से लोगों ने अपने ट्यूबवैल्ज के लिए कनैक्शंज अप्लाई किये हुये थे लेकिन उनको नये कनैक्शंज नहीं मिल पाये थे। वर्तमान सरकार ने दो वर्षों में माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में 16000 नये ट्यूबवैल कनैक्शंज दिये हैं, इस काम के लिए सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाये वह कम है। किसानों को इसका काफी लाभ मिला है, इसके लिए यह सरकार प्रशंसा की पात्र है। चेयरमैन साहब, इस सरकार ने बिजली उत्पादन के बढ़ाने के काम को जितनी गम्भीरता से लिया है उसका नतीजा यह है कि फरीदाबाद, हिसार तथा यमुनानगर में 500-500 मैगावाट के नये थर्मल पावर प्लांट लगाये जा रहे हैं। पानीपत में 250-250 मैगावाट के दो संयंत्र लगाये जा रहे हैं। जैसा कि क्वैश्चन आवर में एक क्वैश्चन था, फरीदाबाद में 432 मैगावाट का दूसरा फेज एन0टी0पी0सी0 की सहायता से लगाया जा रहा है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन की सहायता से पानीपत में रिफाइनरी की क्षमता को ही दुगुना नहीं बढ़ाया जा रहा है बल्कि दूसरा पैट्रोलियम कैमिकल्ज का 360 मैगावाट का बिजली संयंत्र भी लगाया जा रहा है जिसके चालू होने से हरियाणा प्रदेश में सरप्लस बिजली हो जायेगी और यह दूसरे राज्यों को बिजली देने में सक्षम हो जायेगा। ऐसा मैं मानकर चलता हूं। सरकार ने बिजली उत्पादन के कार्य को काफी गम्भीरता से लिया है। हमारे फरीदाबाद में पल्ला में 220 के0वी0 का और सैक्टर 31, 45 और सैनिक कॉलोनी में 66 के0वी0 के सब स्टेशन लगाये गये हैं जो कि निर्धारित समय से दो-तीन महीने पहले ही रिकार्ड टाईम में तैयार कर दिये गये हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनका उद्घाटन भी कर दिया है। मेरे हल्के हसनपुर, मोहना और औरंगाबाद में 66 के0वी0 के सब स्टेशन लगाये जा रहे हैं जिनका काम जल्दी ही पूरा हो जायेगा। इस सरकार नें बिजली के कार्य को काफी महत्व दिया है। जहां तक ट्रांसफारमर्ज की बात है, पिछली सरकारों के समय में इनकी बुरी हालत थी। ओवर लोड की वजह से उनके ट्रांसफारमर्ज फुंक जाते थे लेकिन वर्तमान सरकार ने बिजली सुधारीकरण के लिए प्रशंसनीय कार्य किये हैं। 7700 नये ट्रांसफारमर्ज दिये गये हैं और साढ़े सात हजार किलोमीटर लम्बी पुरानी लोड टैंशन वायर को बदलने का काम किया है। इसी

[श्री उदयभान]

तरह से इस सरकार ने बिजली के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है इसके लिए वर्तमान सरकार की जितनी भी तारीफ की जाये वह कम है। मैं यह मानकर चलता हूं आज बिजली हरेक इंसान के लिए मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। बगैर बिजली के कोई भी काम नहीं हो सकता और न ही बिजली के बिना कहीं आ जा सकते हैं। हमारा प्रदेश जल्दी ही बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा। चेयरमैन साहब, मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा सड़कों के बनवाने का जो काम किया गया है और मण्डियों की सड़कों को बनाने का जो काम किया गया है, उससे किसानों को काफी लाभ हुआ है, उसके लिए भी मार्केटिंग बोर्ड की जितनी तारीफ की जाये वह कम है। मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सड़कों को बनवाने और इनकी मरम्मत पर 596 लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं उसके लिए वर्तमान मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी, कृषि मंत्री, चेयरमैन और माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं जिनके मार्गदर्शन में यह कार्य किया जा रहा है। इसी विकास का नतीजा है कि यमुनानगर से हमारे साथी मलिक चन्द गम्भीर आज हमारे साथ इस सदन में मौजूद हैं। विपक्ष के साथी चुनाव से पहले कहते थे कि यह जनमत संग्रह होगा क्योंकि उनकी यह सोच थी कि सीट उन्हीं की बपौती है। वे सोचते थे कि यह यमुनानगर की सीट या तो कांग्रेस पार्टी की है या भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन इंडियन नैशनल लोक दल ने यह कहा यह लोग कह रहे हैं कि यह जनमत संग्रह है, हम भी इस बात को मानते हैं कि यह जनमत संग्रह है। यह सरकार के विकास के कार्यों का ही नतीजा है कि मलिक चन्द्र गम्भीर जी यमुनानगर से भारी बहुमत से जीतकर आए हैं। विपक्ष के साथी कहते थे कि प्रदेश में हम पहले नम्बर पर आएंगे, उनकी तो यमुनानगर में जमानत ही जब्त हो गई है। सभापति जी, मुझे बहुत अफसोस है कि आज के अखबार में कुछ कांग्रेस के नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री के बारे में ब्यान दिए हैं कि वे किसी भी सीट से हमारे मुकाबले में चुनाव लड़ लें, इनको और कोई काम तो होता नहीं। इस तरह की बेहूदगियां ही ये लोग कर सकते हैं। अभी-अभी तो ये यमुनानगर में पिट कर आए हैं अब अगली कौन सी सीट से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता। सभापति जी, ये लोग स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, इनको रूल्ज और रैगुलेशन का ज्ञान तो है नहीं। ये लोग मौके पर तो उपस्थित होते नहीं, लॉबी में जाकर चाय पीते हैं या अखबार पढ़ते हैं या फिर बाथरूम में घुस जाते हैं। बाद में हंगामा करके अखबारों में फोटो छपवाना चाहते हैं इसके अलावा इन्हें कोई और काम नहीं है। विपक्ष को जो रचनात्मक काम करने चाहिए वह सब करने में ये असफल रहे हैं। यही वजह है कि यमुनानगर से डॉ0 मलिक चन्द गम्भीर जी भारी बहुमत से जीतकर आए हैं।

श्री सभापति : उदयभान जी आप जल्दी वाइंड अप करें।

श्री उदयभान : सभापति जी, सहकारी चीनी मिलों के बारे में सरकार किसानों के प्रति बहुत गम्भीर रही है। देश के अन्दर हरियाणा के किसानों को गन्ने का सर्वाधिक मूल्य मिला है और वह भी भकद मिला है। ऐसा भारत में कहीं भी नहीं हुआ है। हरियाणा की सरकार इस मामले में बधाई की पात्र है कि सरकार ने किसानों को गन्ने का सर्वाधिक मूल्य दिया है और वह भी भकद पेमेंट की है। सभापति जी, इस सरकार ने दो नई चीनी मिलें भी लगाई हैं। मैं सरकार से इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि पलवल में भी शूगर मिल माननीय चौधरी देवीलाल के समय लगी थी। मैं कहना चाहूंगा कि उस मिल की क्षमता से कम से कम तीन गुना ज्यादा गन्ना वहां पैदा होता है। इस कारण वहां के किसानों को बहुत भारी दिक्कत हो रही है कि उनका पूरा गन्ना नहीं लिया

जा रहा। बोल्डिंग भी पूरी नहीं हो पाती और गन्ना रह जाता है। दूसरे क्रैशर लगाए जा रहे हैं। सभापति जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार इस मिल का तुरन्त सर्वे करवाकर इसकी क्षमता को बढ़वाने पर विचार करे ताकि वहां के किसानों का पूरा गन्ना मिलों में लिया जा सके। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि दो चावल मिलें लगाई गई हैं, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हमारे फरीदाबाद जिले में खासकर होडल, पलवल का जो इलाका है, वहां भारी मात्रा में धान पैदा होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करे और होडल, पलवल के आसपास हैफेड द्वारा एक राइस मिल लगवाए ताकि वहां के किसानों को दिक्कत न हो। सभापति जी, सिंचाई विभाग के द्वारा भी प्रशंसनीय काम किया गया है। चौधरी देवीलाल के समय में नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया गया था और अब मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के समय में नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया गया है। ऐसा पहली बार ही हुआ है जब सिंचाई को महत्वपूर्ण मुद्दा मानकर किसान की समस्या को हल करने के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। सभापति महोदय, मेरे से पहले आपने भी जिक्र किया था कि हसनपुर हल्के के अंदर यू0डी0सी0 से 1.4 कि0मी0 पर खिरबी गांव में चौधरी बंसी लाल जी ने पक्का बांध बनवाया था। उस समय सरकार ने सीमेंट की तो चोरी कर ली और वह बांध मिट्टी में ही बनवा दिया। उस समय इस बांध पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये थे और वह पूरी तरह से पानी में बह गया क्योंकि उसमें मैटीरियल ठीक नहीं लगा था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। उस बांध का दोबारा से निर्माण किया जाये तथा यू0डी0सी0 से 0.4 कि0मी0 पर एक नया बांध बनाया जाये ताकि किसानों के खेतों की सिंचाई ठीक से हो सके। सभापति महोदय, बाढ़ नियन्त्रण के मामले में भी सरकार बहुत गंभीर रही है। इस बारे में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरा एरिया यमुना नदी के साथ लगता है। इस संबंध में मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया था वहां पहले दीवार के साथ स्टड्स लगाने का काम किया गया था। अब मैं फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि यमुना नदी के कटाव को रोकने के लिए और वहां के किसानों की खेती की जमीन यमुना नदी के कटाव में न बहे, उसको रोकने के लिए स्टड्स लगाने का काम टैक्नीकल कमेटी से एप्रूव करवाया जाये और वहां स्टड्स लगाये जायें ताकि मिट्टी का कटाव रूक सके। सभापति महोदय, मौजूदा सरकार की उद्योग नीति भी अच्छी रही है जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान सरकार के समय में 434 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हरियाणा में हुआ है। 60 प्रतिशत कारों, मोटरसाईकलों और ट्रैक्टरों का उत्पादन हरियाणा में होता है इससे पता लगता है कि मौजूदा सरकार की उद्योग नीति कितनी अच्छी है। सभापति महोदय, जिस समय 1966 में हरियाणा बना था, उस समय हरियाणा का निर्यात 4.50 करोड़ रुपये के लगभग होता था जबकि अब हरियाणा का निर्यात लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का हो गया है। यह सरकार की अच्छी नीतियों का ही परिणाम है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। सभापति महोदय, अब मैं जन-स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूंगा। मौजूदा सरकार ने पीने के पानी की तरफ और गंदे पानी की निकासी को विशेष प्राथमिकता दी है। पीने का पानी 40 से 56 लीटर और 55 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से देने का सरकार ने संकल्प लिया हुआ है तथा ज्यादातर गांवों में इतना पानी सरकार उपलब्ध भी करवा रही है। शहरों के अंदर पीने के पानी की जो बड़ी भारी किल्लत थी उसको दूर करने के लिए मौजूदा सरकार ने 1640 करोड़ रुपये का बजट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एप्रूवल के लिए केन्द्र सरकार को भेजा हुआ है। सभापति महोदय, पीने के पानी के लिए 4.50 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट होडल में चल रहा

[श्री उदयभान]

है उसके लिए सरकार को मैं बहुत बधाई देता हूं। मौजूदा सरकार ने गंदे पानी की निकासी को प्राथमिकता दी है और यमुना ऐक्शन प्लान के तहत पहले 12 शहरों में मल निकासी प्रणाली तथा मल परिशोधन संयन्त्रों का विस्तार किया जा रहा है और 18 शहरों में मल निकासी और मल परिशोधन संयन्त्र लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे होडल में घोषणा की हुई है कि वहां पर मल परिशोधन संयन्त्र लगाया जायेगा और 8.50 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट स्वीकृत हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह प्रोजैक्ट जल्दी ही सिरे चढ़ाया जाये। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि होडल की अनाज मण्डी हरियाणा में दूसरे नम्बर पर है। यहां की अनाज मण्डी में राजस्थान और यू0पी0 के किसान भी अपना अनाज बेचने आते हैं। इस मण्डी में अनाज बहुत आता है और यह मण्डी बहुत छोटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं महसूस किया था कि यह मण्डी बहुत छोटी है और यहां 125 एकड़ भूमि पर एक मॉडर्न मण्डी बनाने का ऐलान किया था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यह मॉडर्न मण्डी बनाने की दिशा में शीघ्र पहल की जाये ताकि वहां के किसानों को असुविधा का सामना न करना पड़े और बाहर से जो लोग आयें उन्हें मॉडर्न अनाज मण्डी देखने को मिले। यह मण्डी सब सूबों से बेहतर होगी ताकि बाहर के लोग अपने वहां जाकर कहें कि हरियाणा में माननीय चौटाला साहब ने बहुत अच्छी मॉडर्न अनाज मण्डी बनवाई है। सभापति महोदय, यह जो माडर्न अनाज मण्डी बनेगी यह एक अच्छे उदाहरण के रूप में जानी जायेगी और बाहर के लोग भी कहेंगे कि यह बहुत ही अच्छी अनाज मण्डी है। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को और परिवहन मंत्री जी को बधाई दिए बगैर नहीं रह सकता क्योंकि इन्होंने परिवहन के अन्दर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। परिवहन व्यवस्था जो पूरी तरह से ठप्प हो चुकी थी, बसों की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी बहुत कम समय में ही इसमें सुधार किया गया है। अपनी मौजूदा सरकार द्वारा 1200 नई बसें चलाई गई हैं और इसके अलावा 300 नई बसें चलाने का भी बहुत शीघ्र प्रस्ताव है इसके लिए परिवहन मंत्री जी को जितनी बधाई दी जाये वह कम है। चेयरमैन साहब, हरियाणा रोडवेज का खुद का जो इन्जीनियरिंग कारपोरेशन गुड़गांव में है उसके अन्दर ही इन बसों की बॉडी तैयार की गई है। हरियाणा रोडवेज की बसों को देखकर कोई भी यह कह सकता है कि हरियाणा रोडवेज में आज सारे देश में दूसरे राज्यों की रोडवेज की बसें चल रही हैं, उन सबसे बेहतर टाईप की बसें हैं। इसके लिए सरकार की जितनी भी तारीफ की जाये वह कम है। चेयरमैन साहब, अप्रैल से दिसम्बर के बीच लोगों को बेहतर सुविधा देने की वजह से ही रोडवेज द्वारा 87 करोड़ रुपये का कोष जुटाया गया है इसके लिए भी सरकार बहुत-बहुत बधाई की पात्र है।

श्री सभापति : उदयभान जी, आपको बोलते हुए 30-35 मिनट हो गये हैं। आप अपनी बात जल्दी खत्म करें।

श्री उदय भान : चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से यह अवश्य कहूंगा कि जो नैशनल हाईवे पर पैट्रोलिंग का काम माननीय मुख्य मंत्री द्वारा शुरु करवाया गया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये और लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए ही हरियाणा हाई वे पर पैट्रोलिंग की स्थापना की गई थी लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा

कि इस हाई वे पैट्रोलिंग पर चैक रखने की जरूरत है। इस बारे में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नेशनल हाई वे पैट्रोलिंग पर लगा स्टाफ अपना काम न करके दूसरा काम करते हैं और लोगों का दूसरी तरह से शोषण कर रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं इसलिए हरियाणा हाईवे पैट्रोलिंग पर चैक रखने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस मकसद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लगाया था उसी काम पर वे रहें और लोगों से लूट मचाने का काम न करें, इसलिए इस पर चैक रखने की सख्त आवश्यकता है।

चेयरमैन साहब, शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया है। शिक्षा के मद में सरकार द्वारा 3 गुणा बजट अधिक बढ़ाया गया है। चेयरमैन साहब, जिन स्कूलों में अध्यापकों की कमी थी या जिन स्कूलों में अध्यापक नहीं थे, वहां पर अध्यापकों की नई भर्ती करके अध्यापकों की कमी को दूर करने का भरसक प्रयास किया गया है। कम्प्यूटर शिक्षा व इन्फर्मेशन टैक्नालॉजी शिक्षा को भी सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया है इसलिए मैं इस कार्य के लिए भी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं। चेयरमैन साहब, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे हल्के हसनपुर के अन्दर एक भी वोकेशनल इन्स्टीच्यूट, आई0टी0आई0 या कोई पोलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। पहले होडल के अन्दर एक ऐसा इन्स्टीच्यूट खोलने की योजना थी लेकिन वह योजना भी ड्रॉप कर दी गई। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार करके वहां पर एक आई0टी0आई0 अवश्य खोली जाये।

चेयरमैन साहब, अब मैं समाज कल्याण विभाग से संबंधित कुछ बातों पर बोलना चाहूंगा। इस विभाग द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के बच्चों के वजीफे भी पहले से दो गुणा अधिक किए गए हैं। इसी प्रकार से वृद्धावस्था पैंशन और विकलांग पैंशन को भी डबल किया गया है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनके शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। माननीय वित्त मन्त्री प्रो0 सम्पत सिंह जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ और उसमें जो निर्धन और मेधावी छात्रों को जो इन्सैंटिव देने का निर्णय लिया गया है, उसकी भी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। 10 जमा 2 के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 700/- रुपये प्रति महीने का वजीफा उसमें किया गया है और 1500/- रुपये स्टेशनरी अथवा लेखन सामग्री के लिए और दो हजार रुपये प्रति वर्ष पुस्तकों के लिए ग्रान्ट के लिए किया है उसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। चेयरमैन सर, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री लीला राम (कैथल) : धन्यवाद चेयरमैन साहब। मैं 4 मार्च को महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में आदरणीय साथी सरदार निशान सिंह जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। चेयरमैन महोदय, मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। चेयरमैन महोदय, 4 मार्च को हरियाणा प्रदेश के विकास के बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने अभिभाषण पढ़ा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हरियाणा सरकार ने उससे भी ज्यादा विकास कार्य हरियाणा प्रदेश में किए हैं और कुछ कार्य तो इस प्रकार के हैं जो इस अभिभाषण में नहीं पढ़े गये। चेयरमैन महोदय,

[श्री लीला राम]

सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की पुरानी लम्बित मांग एस0वाई0एल0 मुद्दे का फैसला हरियाणा प्रदेश के हित में दिया है। चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आज इस सदन के अन्दर स्वर्गीय लोक नायक चौधरी देवी लाल जी का जिक्र न किया जाए तो शायद इस सदन की कार्यवाही अधूरी रहेगी। चेयरमैन महोदय, हरियाणा प्रदेश में एस0वाई0एल0 के मुद्दे पर चौधरी देवी लाल जी ने जो लड़ाई लड़ी उस लड़ाई को आगे चल कर आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के अथक प्रयासों से सारे प्रदेश की सूखी भूमि को पानी दिलवाने का जो का किया मैं उसके लिए भी हरियाणा सरकार की तारीफ करुंगा तथा हरियाणा सरकार को बधाई दूंगा। आदरणीय चेयरमैन महोदय, पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सरकार बनी उससे पहले हरियाणा प्रदेश का क्या हाल था, क्या माहौल था वह हरियाणा की जनता देख चुकी थी और उसे भुगत चुकी थी। हरियाणा प्रदेश की कमान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सम्भाली उससे पहले हरियाणा प्रदेश में कानून-व्यवस्था की क्या स्थिति थी वह हरियाणा की जनता के सामने थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठकर कानून-व्यवस्था की स्थिति को ठीक किया वहां पर हरियाणा प्रदेश में विकास कार्यों की भी झड़ी लगा दी। कुछ दिन बाद हरियाणा प्रदेश में हुए उप-चुनाव में हरियाणा की जनता ने आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में फतवा जारी किया और दूसरी ओर हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बनते ही उन्होंने चुनाव से पहले जो घोषणाएं की थीं, कुछ योजनाएं और स्कीमों का प्रारूप दिया था उन स्कीमों को ले कर लोगों के बीच आए और उसका नाम रखा 'सरकार आपके द्वार'। आदरणीय चेयरमैन महोदय, जब हरियाणा प्रदेश में मुख्य मंत्री 'सरकार आपके द्वार' के तहत किसी हल्के या किसी जिले के हैडक्वार्टर में जाते थे वहां पर हरियाणा प्रदेश के जिला हैडक्वार्टरों के सभी अधिकारी डी0सीज0, एस0 पीज0, एस0डी0ओज0, एक्सीयन और दूसरे अधिकारियों को भी वहीं पर बुला लेते थे और उस हल्के और जिले की पूरी की पूरी पंचायतों को वहां पर सरकार के सामने बुलाया जाता था और जब पंचायतों को यह कहा जाता था कि आप अपनी मांगे रखिए तब मुख्य मंत्री जी अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याओं को सुन कर वहीं पर उनका समाधान करने और समस्याओं का निदान करने का काम करते थे। इस बारे में मैं यह कहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश में किसानों की, व्यापारियों की, कर्मचारियों की और जनता की सरकार है। चेयरमैन महोदय, जिस प्रकार विभागों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश ने प्रगति की है, उन्नति की है वह अपने आप में एक मिसाल है।

चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले सिंचाई विभाग के बारे में बोलना चाहूंगा तथा कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के साथ धक्का हो रहा था। पहले मुख्यमंत्रियों के राज में नहरों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय, ने कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले भाखड़ा नहर की सफाई का काम किया है जिस वजह से आज हरियाणा की जनता को पूरा पानी मिल रहा है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हरियाणा की इर टेल पर पानी मिलेगा। आज हरियाणा सरकार के अथक प्रयास से एक भी टेल ऐसी नहीं है जहां पर पानी नहीं पहुंचा हो। कृषि के क्षेत्र में

मुख्यमंत्री जी ने 30/-रुपए प्रति क्विंटल गेहूं पर और 20/-रुपये प्रति क्विंटल धान पर बोनस दिया है। हरियाणा में गन्ने का भाव देश में सबसे ज्यादा 110/-रुपए प्रति क्विंटल दिया है इस प्रकार सारे देश में हमारी सरकार ने एक मिसाल कायम की है। चेयरमैन महोदय, किसान को पहले अपनी फसल बेचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था लेकिन आज 6 या 8 किलोमीटर से दूर नहीं जाना पड़ता है। हरियाणा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 105 मुख्य मार्किट यार्ड, 179 सब-यार्ड तथा 158 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं। आज हरियाणा प्रदेश के किसानों को अपनी फसलें बेचने के लिए दूर-दूर तक नहीं जाना पड़ता है।

जन-स्वास्थ्य विभाग के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां हरियाणा में पहले लोगों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, अब हमारी सरकार ने आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति स्तर बढ़ाकर 40 से 55/70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह से हमारी सरकार ने लोगों के साथ न्याय किया है। चेयरमैन सर, मैं अपने हल्के कैथल की बात कहूंगा कि हमारे यहां पर नीचे का पानी खराब है जो कैनाल बेस्ड प्रोजैक्ट चल रहा है उसके लिए हमारी सरकार ने साढ़े तीन करोड़ रुपए देकर उसकी गति को तेज किया है। मुख्यमंत्री जी ने कैथल में 25 नए डीप ट्यूबवैल्ज दिए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 70 लाख रुपए की कैनाल बेस्ड स्कीम की आधारशीला भी रखी है, उसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं।

चेयरमैन सर, अब मैं हरियाणा के परिवहन विभाग के बारे में बात करना चाहूंगा। हमारा हरियाणा प्रदेश यू0पी0, पंजाब और राजस्थान से घिरा हुआ है। हरियाणा प्रदेश की बसें हरियाणा से अमृतसर, हरियाणा से आगरा और हरियाणा से गंगानगर तक जाती हैं। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, लोग सड़कों पर खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं कि कब हरियाणा रोडवेज की बस आएगी तब उसमें जाएंगे। आज हमारे युवा साथी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं और यहां आकर कहते हैं कि वहां पर बसें ऐसी थीं वैसी थी और बहुत ही आरामदायक बसें थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि वैसी ही बसें हमारे प्रदेश की हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, आज हर जगह पर एजुकेशन का दौर है, शिक्षा का दौर है। शिक्षा के क्षेत्र में आज हरियाणा ने जो तरक्की की है उसके बारे में यहां सदन में कहना ठीक नहीं है। यह कोई राजनीति की बात नहीं है। यह आज अपने आप में एक मिसाल बन गया है। आज दूसरे प्रदेश के लोग भी हरियाणा की शिक्षा नीति की तारीफ करते हैं और उसकी नकल करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश का एक जिला भी ऐसा नहीं होगा जहां पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज न हो, कोई पोलिटैक्निक कॉलेज न हो या कोई कम्प्यूटर की एजुकेशन संस्था न हो। इसी तरह से आज हरियाणा प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने प्राईवेट क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा के लिए लौहार माजरा, ईस्माईलाबाद और जींद जिले के उचाना में कॉलेजों को मान्यता दी है तथा इसी तरह से लड़कियों की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा शिक्षा के मामले में हिन्दुस्तान में सबसे आगे है। आज सरकार द्वारा स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए बहुत ही आसान नॉर्म्ज या शर्तें रखी गयी हैं। इन शर्तों को कोई भी स्कूल आसानी से पूरा कर सकेगा। अब सरकार द्वारा इस बारे में इस प्रकार का सिस्टम बना दिया गया है कि अब हमें भी इस बारे में सरकार को एप्रोच करने की जरूरत नहीं रह गयी है। जो भी स्कूल ये नॉर्म्ज पूरा करेगा वह अपने आप ही प्राईमरी से मिडल, मिडल से हाई स्कूल और हाई स्कूल से प्लस टू का स्कूल बन जाएगा। आज सरकार द्वारा हरियाणा में बहुत ही बढ़िया शिक्षा प्रणाली लागू की गयी

[श्री लीला राम]

है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री और हरियाणा सरकार का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी तरह से स्पोर्टस का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। आज हरियाणा प्रदेश में खेलों पर जिस प्रकार से तवज्जो दी गयी है वह काबिले तारीफ है। चौटाला साहब की सरकार बनने से पहले तो लोग खेलों को भूल ही चुके थे परन्तु हरियाणा प्रदेश की कमान चौटाला साहब के संभालने के बाद और उनके नेतृत्व में भाई अभय सिंह चौटाला ने जब से स्पोर्टस की कमान संभाली है तब से हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में छाए हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जब पंजाब के अंदर राष्ट्रीय खेल हुए तो उस समय हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने 17 स्वर्ण पदक, 20 रजत पदक और 30 कांस्य पदक प्राप्त किए जो अपने आप में एक इतिहास है। खेलों को और बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक और स्कीम बनायी है। अगर किसी गांव के लोग या उस गांव की पंचायत 25 प्रतिशत राशि इकट्ठा करती है तो 75 प्रतिशत राशि हरियाणा सरकार वहां पर स्टेडियम बनाने के लिए देगी। इस तरह के अनेकों स्टेडियम सरकार ने मंजूर किए हैं और उनमें से काफी बनकर भी तैयार हो चुके हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाली इस से बड़ी बात क्या हो सकती है। इसी प्रकार से खिलाड़ियों को नौकरियों में तीन प्रतिशत रिजर्वेशन का प्रावधान भी सरकार द्वारा किया गया है। मैं कहूंगा कि यह भी एक ऐतिहासिक काम है। भाई अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार से खिलाड़ियों को नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण दिलाने का काम किया है उसके लिए वे तारीफ के काबिल हैं। मैं उनकी तारीफ करने के साथ ही हरियाणा सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बिजली की बात है। बिजली आज इंसान की जिंदगी में एक जरूरत बन गयी है। मैं कहूंगा कि आज सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का है तो वह बिजली का है क्योंकि बिजली इस प्रकार की चीज है कि वह सभी के काम आती है। बिजली के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने जो तरक्की की है मैं उसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि बिजली के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कमान में तरक्की हुई है वह तारीफ के काबिल है। हमारी सरकार बनने से पहले इस मामले में जो हालात थे उनका सभी को पता है। चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे चौधरी बंसी लाल जी की सरकार रही। बिजली के मुददे पर जब भी भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने धरना दिया कांग्रेस की सरकार के समय में टोहाना में किसानों को गोलियों से भून दिया गया। बंसी लाल जी की सरकार के समय में किसान शांति प्रिय ढंग से लोहारू में धरना दे रहे थे उस समय भी उनको गोलियों से भून दिया गया।

श्री राम किशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अभी बैठ जाएं। मैं आपको बाद में समय दूंगा।

श्री लीला राम : उपाध्यक्ष महोदय, लोहारू में किसान धरना दे रहे थे वहां पर किसान गोलीकांड में मारे गए। इसी प्रकार से सतनाली के अंदर मंडियाली, इगरा, कलायत, नरवाना और उचाना में किसानों को गोली से भून दिया गया। जैसे ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रदेश की कमान संभाली किसान को पहले की बजाय ज्यादा बिजली मिली और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को फुल वोल्टेज पर बिजली मिली। पिछले दो साल के अंदर एक भी किसान की मोटर नहीं सड़ी। कहीं किसान की अपनी गलती की वजह से मोटर सड़ी हो तो अलग बात है वरना वोल्टेज की वजह से कहीं कोई मोटर नहीं सड़ी। एक भी बल्ब फ्यूज नहीं हुआ। मेरे कैथल का उदाहरण है यहां पिछले दो साल के अंदर दस नये पावर हाउस बने हैं। हमने तो इस प्रकार

की सरकार भी देखीं कि कैथल में 1982 के अंदर 33 के0वी0 के एक पॉवर हाउस का शिलान्यास हुआ था और वह 1987 तक नहीं बना था उसे अब चौटाला जी ने बनाने का काम किया है। पहले तो पत्थर रखे जाते थे काम नहीं किया जाता था। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब की सरकार ने जमीन ऐक्वायर की है और अब कैथल में पट्टी अफगान में 440 के0वी0 का पॉवर हाउस बनने जा रहा है इसी प्रकार पाड़ला में 132 के0वी0, क्योंड़क में 33 के0वी0, कैथल सैक्रेटेरियेट में 33 के0वी0, जाखौली में 33 के0वी0, चीका में 220 के0वी0, क्वारथन में 33 के0वी0 और चक्कूलदाना में 33 के0वी0 के पावर हाउस तैयार हो गए हैं। बिजली के मामले में इस प्रकार का उदाहरण इस सरकार ने प्रस्तुत किया है और बिजली का सुधारीकरण किया है। इस प्रकार की सरकारें भी थीं जिन्होंने चुनाव से पहले लोगों को कह दिया कि 24 घंटे में ट्रांसफार्मर दे देंगे, ट्यूबवैल का कनैक्शन दे देंगे और जब किसान कनैक्शन मांगने के लिए आए तो उनको गोलियों के सिवाय कुछ भी न मिला। बिजली बोर्ड ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 16 हजार नये ट्यूबवैल कनैक्शन देने का काम किया है और नयी बिजली की लाइनें बिछाने का काम किया है इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। बिजली के पावर हाउस बनाने का काम शुरु करना था उसके लिए मुख्यमंत्री जी आए 132 के0वी0 के पावर हाउस को बनाने का काम पाड़ला में शुरु करना था और 33 के0वी का क्यौंड़क में शुरु करना था उस समय हरियाणा बिजली बोर्ड के उच्चाधिकारियों में मीनाक्षी जी भी उनके साथ थीं, उनसे पूछा गया कि बहन जी इसे कितने दिन में बनाकर तैयार कर देंगे। विशेषकर बिजली बोर्ड के अधिकारियों का भी मैं विशेष

13.00 बजे

रूप से इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो समय सीमा वहां पर दी गई थी उससे पहले उन्होंने हमारे उस पावर हाउस को बनाकर तैयार कर दिया है। एक ईमानदार और कर्मठ अधिकारी को बिजली बोर्ड में लगाया गया है अगर इसी प्रकार से दूसरे डिपार्टमैंटस में भी हो जाये तो हरियाणा प्रदेश की कायाकल्प हो जायेगी। मैं इस सरकार को और विशेषकर बिजली बोर्ड के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे पूरी ईमानदारी और लगन से काम कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अधिकारी चाहे वे एक्सियन हों, एस0डी0ओज0 हों उनसे अगर गांव का कोई भी आदमी ट्रांसफामर्ज की मांग करता है तो उसके गांव में पहुंचने से पहले ही ट्रांसफार्मर गांव में पहुंच जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण की बात हुई। मैं यहां पर कहना चाहूंगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण मुद्दा आदरणीय लोक नायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी से जुड़ा हुआ है। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है। हरियाणा प्रदेश में सत्ता सम्भालने से पहले चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को यह कहा करते थे कि ए बूढे मरना नहीं मेरी सरकार आयगी तो मैं बुढ़ापा पैंशन लागू करूंगा। जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृति पर पैंशन दी जाती है उसी प्रकार से बुढ़ापा पैंशन दी जायेगी। चौधरी देवीलाल की एक सोच थी कि किसान को, मजदूर को वृद्धावस्था पैंशन क्यों न दी जाये। इसी तर्ज पर आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही 100/-रुपए प्रति माह बुढ़ापा पैंशन प्रदेश के बुजुर्गों को देने की घोषणा की। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उस 100/-रुपये प्रति माह बुढ़ापा पैंशन को बढ़ाकर 200/-रुपये प्रति माह करने का काम किया। इसके अलावा आज हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरा काम किया है वह है वृद्ध आश्रम बनाने का, जिससे 300-400 वृद्ध आश्रम गांवों में बनकर तैयार भी हो गये हैं और 600-700 वृद्ध आश्रम बनाने का काम चल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि सांय के समय में गांव के 10-15 वृद्ध वहां पर इकट्ठे होकर अपने दुःख सुख की बात कर सकते हैं, अपने हितों की बात कर

[श्री लीला राम]

सकते हैं। हरियाणा सरकार जो अच्छे काम कर रही है उसके लिए वह बधाई की पात्र है। एक दूसरा सराहनीय कार्य जो इस सरकार ने किया है वह है हरिजन कन्या की शादी के समय 5100/-रुपये कन्यादान । इस बारे में हमारे विपक्ष के साथी मजाक किया करते थे परन्तु आज इस स्कीम से प्रभावित होकर पंजाब सरकार भी इस स्कीम को लागू करने के बारे में सोच रही है। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जच्चा-बच्चा के लिए 500/-रुपये की सहायता का प्रावधान करके अपने आप में एक मिसाल पैदा की है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हरियाणा प्रदेश में रोजगार की बात करना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि पिछली सरकारों के समय में जब भी कोई युवा बेरोजगार साथी किसी मंत्री, किसी एम0एल0ए0 या मुख्यमंत्री के पास जाता था तो उन सरकारों के समय में मुख्यमंत्री से लेकर कार्यकर्त्ता तक पैसे की बात किया करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कैथल शहर में देखा है। (**इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए**) जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार थी और पुलिस की भर्ती हुई थी उस समय तो किसानों ने मंडी के आढ़तियों का पैसा खत्म कर दिया था क्योंकि भर्ती के लिए वे जिस के पास भी जाते थे वह दो लाख या तीन लाख रुपये की मांग करता था। एक-एक मंत्री और एम0एल0ए0 के पास 300-300 आदमियों के पैसे जमा थे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का राज हरियाणा प्रदेश में हमने देखा है। परन्तु आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में 14 हजार के लगभग कॉलेज लैक्चरर्ज, जे0बी0टी0 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। 3600 के लगभग पुलिस की भर्ती की गई, 700 के लगभग अभी आई0आर0पी0 की भर्ती चल रही है। 300 के लगभग डाक्टर्ज की भर्ती की गई, 600 के लगभग मैथ टीचर्ज की भर्ती की गई, परिवहन विभाग में 400-500 ड्राइवर्ज भर्ती किये गये, इस प्रकार 28 से 30,000 से ज्यादा नियुक्ति की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन भर्तियों के लिए कोई साथी अगर चाहे तो विजीलैंस की इंक्वायरी करवा कर देख सकता है उसको कोई एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई पैसे देकर भर्ती हुआ हो। आज के इस दौर में इससे बड़ी उपलब्धि सरकार की और क्या हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों में नौजवान साथियों से भर्ती के लिए पैसे ले लिये जाते थे परन्तु वे भर्ती होते नहीं थे फिर वे पैसे वापिस मांगने के लिए उनके पास चक्कर लगाते थे। उनको धमकी दी जाती थी या 10-15 हजार रुपये महीना वह भी 20 परसैंट काटकर दिये जाते थे। इस प्रकार की व्यवस्था उस समय की सरकारों के समय में थी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून और व्यवस्था की बात है, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने कहा कि आज कानून और व्यवस्था की हालत खराब है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता भी जानती है कि जब चौधरी बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय नौजवानों के पास मोबाइल थे उनके नीचे एस्टीम या दूसरी गाड़िया होती थीं, उस समय हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवान एम0ए0,एम0बी0ए0 तक के विद्यार्थियों ने शराब बेचने का काम शुरु कर दिया था। पूरे हरियाणा प्रदेश पर यह एक कलंक था। उस समय का पनपा माफिया आज भी कहीं न कहीं कोई वारदात कर देता है। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा प्रदेश की तारीफ करना चाहूंगा, हरियाणा पुलिस की इस बात के लिए तारीफ करना चाहूंगा कि प्रदेश में चाहे कहीं पर भी कोई वारदात हुई हो कोई ऐसी वारदात नहीं जिसको ट्रेस न किया हो और वारदात करने वाले को जेल की सलाखों के पीछे न भेजा गया हो। वारदातें तो होती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था है कि हर क्षेत्र में आज तरक्की और उन्नति का दौर है।

श्री अध्यक्ष : लीला राम जी, आप वाइंड अप करें।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो आज हरियाणा प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के व्यापारी यह सोचकर आ रहे हैं कि उद्योग लगाने के लिए हिन्दुस्तान में हरियाणा प्रदेश से बढ़िया कोई सेफ जगह नहीं है। पिछले दिनों जब कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली से इंडस्ट्रीज को बाहर निकाला जाए। दिल्ली से उजड़कर सबसे ज्यादा उद्योग यहां हरियाणा प्रदेश में आकर स्थापित हुए हैं। डॉ0 हरबक्श सिंह जी बता रहे थे कि एक दिन में 1400 एप्लीकेशंज औद्योगिक प्लाट्स के लिए उनके पास आई हैं उससे शायद 1400 करोड़ रुपये का रैवेन्यू हरियाणा सरकार को मिला है। अध्यक्ष महोदय, आज देश का व्यापारी तथा मिल मालिक इस बात को देखता है कि कहां कानून और व्यवस्था अच्छी है और कहां बिजली की पोजीशन अच्छी है, कहां श्रमिक अच्छे हैं वह उसी प्रदेश में जाना चाहता है। आज ये सभी चीजें हरियाणा में मौजूद हैं इसलिए हिन्दुस्तान का कोई भी मिल मालिक हो, या व्यापारी हो वह हरियाणा प्रदेश में अपना काम धन्धा करने के लिए भागता है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर इतना ही कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में विकास का दौर चला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिला कैथल की बात रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि कैथल जिला इंडियन नैशनल लोकदल का गढ़ रहा है। अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे समय में भी कैथल जिले के लोग चौधरी देवीलाल जी के साथ रहे और अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पीछे हैं। इसलिए अब जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने हैं तो कैथल की जनता भी सोचती है कि क्यों न इस विकास के दौर में हमारे भी काम बनें। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय कैथल गए थे और रैस्ट हाउस में रुके थे तो वहां पर प्रैस के साथी आ गए। प्रैस से जुड़े लोगों ने जब उनसे कहा कि हमारे पंचायत भवन से लेकर पी0डब्ल्यू0डी0 रैस्ट हाउस तक की सड़क बहुत खराब है तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसी समय प्रैस के साथियों के सामने इस सड़क को बनवाने के लिए अधिकारियों को और डी0सी0 को आदेश दिए और कहा कि इस सड़क का एस्टीमेट बनाकर दो। उस सड़क का एस्टीमेट एक करोड़ 18 लाख रुपये का बना। अध्यक्ष महोदय, यह सड़क वास्तव में कैथल हल्के की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की सड़क है। कैथल जिले के ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश से व्यापारी, कर्मचारी और आम जनता इस सड़क से आती जाती है। सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और जींद आदि की जनता भी इसी सड़क से चण्डीगढ़ आती है इसलिए इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र रोड पेहोवा चौक से हुड्डा तक काफी नीची है, बरसात के दिनों में इसमें काफी पानी भर जाता है यदि यह रोड भी सीमेंट की बन जाये तो बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, कैथल के अंदर गंदे पानी के कुछ नाले भी हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पटियाला रोड तथा पट्टी अफगान से चौक तक सीमेंटिड बना दिये जायें तो अच्छा होगा। इसी तरह कैथल के अंदर कुरुक्षेत्र रोड से अर्जुन नगर तक गन्दे पानी का नाला बना दिया जाये तो मैं सरकार का बहुत आभारी रहूंगा। चंदाना गेट से रेलवे लाईन तक की सड़क व नाला दोनों सीमेंटिड बना दिये जायें तो वहां के लोगों को परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से बिजली बोर्ड चौक से जाट स्कूल तक ओल्ड बाई पास सड़क व नाला दोनों बना दिए जायें तो वहां के लोगों को भी सुविधा हो जायेगी। इसी तरह जाट कॉलेज से कुरुक्षेत्र रोड़ तक सड़क व नाला दोनों बन जायें तो अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, कैथल के अंदर बड़ी-बड़ी कालोनियां हैं जिनके अंदर सीवरेज व गलियां पक्की करवाने के बारे में मैं सरकार से

[श्री लीला राम]

अनुरोध करूंगा। बलराज नगर, शक्ति नगर, राधा स्वामी कालोनी व अर्जुन नगर कालोनियों के अंदर गलियां पक्की कर दी जायें और सीवरेज या नालियां बना दी जायें तो मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करूंगा। अध्यक्ष महोदय, कैथल के अंदर सीवरेज सिस्टम नाम मात्र का ही है क्योंकि वहां पर पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया इसलिए यदि कैथल के अंदर रामनगर, रजनी कालोनी, सुभाष नगर, नानकपुरी आदि जगहों पर सीवरेज सिस्टम कर दिया जाये तो सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, कैथल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी और वहां पर स्टेडियम बनाने के लिए सर्वे भी किया गया था लेकिन स्टेडियम बनाने के लिए जो नार्म्ज थे वे पूरे न होने के कारण वहां स्टेडियम नहीं बन सका। अब मैं सरकार से दोबारा से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर फिर से सर्वे करवाकर स्टेडियम बनवाया जाये। क्योंकि चाहे कबड्डी हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो या फुटबाल हो कैथल जिले के लड़के व लड़कियां हर खेल में आगे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि कैथल शहर की आबादी 1.25 से 1.50 लाख के करीब है और वहां पर एक भी पार्क नहीं है इसलिए वहां पर एक अच्छा पार्क बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, कैथल शहर तीन तरफ से बाई पास से घिरा हुआ है लेकिन जींद सड़क से खनौरी तक बाई पास नहीं है इसलिए यहां पर भी बाई पास बनाने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कैथल शहर के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है और माननीय परिवहन मंत्री श्री अशोक अरोड़ा जी यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कैथल शहर का बस स्टैंड शहर से बाहर बनाया जाये और वहां पर ट्रांसपोर्ट नगर भी बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत हरियाणा प्रदेश में लगभग 5 हजार कि0मी0 नई सड़कें बनाने का काम किया है। हमारे कैथल हल्के के अन्दर 18 नई सड़कें बनीं हैं उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारी 4-5 सड़कें हैं उन्हें भी शीघ्र बनाया जाये। युन्धरेहड़ी गांव से सोट गांव तक एक सड़क बनाई जाये। इसी प्रकार से फ्रांसवाला से भानपुरा तक की सड़क को भी बनाया जाये। क्योंडक गांव से बरोट तक की एक सड़क है वह भी बनाई जाये। यह सड़क अम्बाला से बरोट तक तो बनी हुई है क्योंडक से जाकर सड़क पर चढ़ जाती है। क्योंडक से सुलतानपुर तक सड़क बनाई जाये। अध्यक्ष महोदय, बाबा लदाना से गढ़ी तक की एक सड़क है। गांव भुजाना से कुलतारन तक की भी एक सड़क है और गांव गुड़ना से दिलवा वाली की सड़क भी बनाई जाये। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से एक मांग करना चाहूंगा। हमारे कैथल जिले की यह सबसे बड़ी मांग है जो बहुत उचित भी है। कैथल जिले के अन्दर एक भी गवर्नमैंट कॉलेज नहीं है वह अवश्य बनाया जाये। कैथल डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है। वहां पर इर तरफ से हजारों छात्र कैथल से या तो चीका जाते हैं या पुण्डरी जाते हैं या फिर पेहवा आते हैं या फिर कैथल से कुरुक्षेत्र आते हैं। कैथल बड़ा शहर है। वहां पर पाई में व कलायत में कोई कालेज नहीं है और न ही आसपास के क्षेत्र में ऐसा कोई कालेज है। इसी प्रकार से राजौंद में भी कोई कालेज नहीं है। वहां बड़े-बड़े कस्बे लगते हैं लेकिन सरकारी कॉलेज कोई नहीं है। इसलिए मेरी पुरजोर मांग है कि कैथल के अन्दर एक गवर्नमैंट कॉलेज अवश्य बनाया जाये। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि मेरे हल्के के जो 3 बड़े-बड़े गांव हैं, मानस, गुड़ना, क्योंडक। इन गांवों के अन्दर

कोई भी सड़क तथा गली नहीं बनी हुई है। मेरी मांग है कि इन गांवों के विकास के लिए 10-10 लाख रुपये दिए जायें ताकि वहां पर गलियां आदि बनाई जा सकें। अध्यक्ष महोदय, आज सारे प्रदेश में विकास की उन्नति की झड़ी लगी हुई है। मैं भी आपके माध्यम से सरकार से आशा रखता हूं कि मैंने अपने हल्के की जो मांगे रखी हैं इन सब पर हरियाणा सरकार गौर करेगी और इनको पूरा करेगी। स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

डॉ0 बिशन लाल सैनी (जगाधरी) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 4 मार्च को जो अभिभाषण दिया मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने सदन में अभिभाषण पढ़ कर सुनाया, मैं उसी विषय में बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि जब से सरकार की बागडोर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सम्भाली है तब से हरियाणा प्रदेश के अन्दर सभी गांवों में एक प्रकार से विकास कार्यों की झड़ी लग गई है और बड़ी भारी संख्या के अन्दर विकास के काम हुए हैं। अध्यक्ष जी, विकास के जो काम हुए हैं वे बहुत तीव्रगति के साथ हुए हैं। आज प्रदेश के किसी भी गांव में जा कर देखें किसी गांव में गन्दे पानी का नाला बना कर उस गांव के गन्दे पानी को निकालने का काम चल रहा है, किसी गांव में हरिजन चौपाल बनाने का काम था तो हो चुका है या काम चल रहा है, किसी गांव में जा कर देखते हैं कि गांव की जो फिरनी है वह पक्की करवाई जा रही है और कहीं पर वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, जो श्मशान घाटों के रास्ते हैं वे पक्के करवाए जा रहे हैं। अगर मैं सारे काम गिनवाने लगूं तो इसमें बहुत समय लग जायेगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस सरकार का नेतृत्व करना शुरु किया है इस अढाई साल में जितने भी काम हुए हैं उनको तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और जब से हरियाणा प्रदेश बना है और जितनी भी सरकारें या उनके मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने जितने भी विकास के काम आज तक करवाए हैं उनको तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाए तो अध्यक्ष जी, वे सारे काम जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने किए हैं उनका पलड़ा भारी दिखाई देगा। अध्यक्ष जी, इस से भी बढ़िया एक बात जो सी0एम0 साइब ने की है वह यह है कि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि इस क्षेत्र से कांग्रेस का एम0एल0ए0 बना है यहां पर काम नहीं करवाए जाएंगे। इन्होंने कभी यह भी नहीं सोचा है कि इस क्षेत्र से बी0एस0पी0 का एम0एल0ए0 बना है इसलिए यहां पर काम नहीं करवाए जाएंगे, इन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि यहां से इनैलो का कैंडीडेट बना है इसलिए यहां पर ज्यादा काम करवाए जाएंगे। सभी विधान सभा क्षेत्रों में उन्होंने बढ़िया काम करवाए हैं, अध्यक्ष जी, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। अध्यक्ष जी, जो काम पिछली सरकारें शिलान्यास करके चली गई उन कामों को भी इस सरकार ने पूरा करवाने का काम किया है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र जगाधरी का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। जो पिछली सरकार थी, इस समय चौधरी बंसी लाल जी सदन में नहीं हैं, इनकी सरकार के दौरान मेरे क्षेत्र के दो गांव पड़ते हैं तलाकौर और कलावड़ ये दोनों गांव बड़े गांव हैं। इन दोनों गांवों के लोगों की डिमाण्ड पर इन की सरकार में जो मंत्री थे उन्होंने तलाकौर से बाल छप्पर और कलावड़ से सटारी की सड़कों के लिए पत्थर लगाए और शिलान्यास किया। अध्यक्ष जी, उन दोनों जगहों पर पत्थर ही लगे रह गए लेकिन काम शुरु नहीं हुआ, हां इतना जरूर हुआ कि कुत्ते आया करते और पेशाब करते। (विघ्न)

एक आवाज : वे पत्थर किस के राज में लगे थे। (विघ्न)

डॉ0 बिशन लाल सैनी : वे पत्थर चौधरी बंसी लाल जी के समय में लगे थे।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, उनका नजरिया जनसेवा न हो कर कुत्तों की सेवा करने का रहा लगता है उन्होंने कुत्तों की सुविधा के लिए ऐसा किया होगा। (हंसी)

डॉ0 बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष जी, सड़क बनाने के लिए वहां पर न तो एक टोकरी मिट्टी की डाली गई और न ही कहीं रोड़ी बिछाई गई। जब सरकार बदली और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आई और 'सरकार आपके द्वार' जो कार्यक्रम चलाया उसके दौरान जब मैंने चौधरी साहब से इन दोनों सड़कों के बारे में बात की तो चौधरी साहब ने एक मिनट में दोनों की दोनों सड़कें मन्जूर कीं और वे दोनों सड़कें बन कर अब तैयार हो गई हैं। अध्यक्ष जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इससे बढ़िया और भी काम गांव-गांव में विकास समितियां बनाने का किया है। जब विकास समितियां बनाने का काम शुरु हुआ तो मेरे बहुत से साथियों ने, जो आज यहां पर बैठे हुए नहीं हैं, बड़ा विरोध किया। ग्राम पंचायतों और सरपंचों से कहा कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके पैरलल नई पंचायतें बनाई जा रही हैं, इससे पार्टीबाजी पैदा हो जाएगी और न जाने क्या-क्या बातें कहीं। जब विकास समितियां बन गई और उन्होंने काम करना शुरु किया और जब उनके रिजल्टस सामने आए तो ये लोग दबी जुबान से कहते हैं कि विकास समितियां काम तो बहुत बढ़िया कर रही हैं और तीव्र गति से काम कर रही हैं। यह बहुत बढ़िया बात है कि विकास समितियां बनाई गई हैं। पहले क्या होता था कि गांव के लोगों को और गांव की पंचायतों को पता ही नहीं लगता था कि कितना पैसा आया और कितना खर्च हो गया। लेकिन जब से ये विकास समितियां बनी हैं, सरकार के द्वारा डिवैल्पमैंट के लिए जो चैक दिया जाता है वह सीधा विकास समितियों को दिया जाता है इससे उनको काम करने का पता चलता है, कितने दिनों में काम हो गया और कितने पैसे लग गए हैं यह सब पता रहता है। आज विकास का सारा काम विकास समितियों के हाथ में है। (विघ्न)

प्रो0 राम भगत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है, चौधरी बंसी लाल जी ने खनन के बारे में जो आरोप लगाए हैं कि वहां पर जो पहाड़ लीज पर गया है वहां पर बड़ी जबरदस्त लूट चल रही है। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से या सम्बन्धित विभाग के मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि वे इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें ताकि हरियाणा की जनता के सामने एक सही तस्वीर आए। बंसी लाल जी ने कहा कि वहां से ट्रैक्टर, ट्रक और ट्रेलर बजरी या रोड़ी के भर कर जाते हैं तो रास्ते में लठैत और बदमाश आदमी 1000/- रुपए या 2000/- रुपये की पर्चियां काटते हैं। यह सरकार पर बहुत ही संगीन आरोप है। इसके बारे में एक बार फिर से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी राम भगत जी ने जो बात कही है इस बारे में जब बंसी लाल जी बोल रहे थे तो हम उसी वक्त स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बंसी लाल जी बोल रहे हैं इनको बीच में इन्ट्रप्शन क्रिएट न करें। इसके अलावा खुद चौधरी बंसी लाल जी ने कहा कि मुझे बोलने दें। अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण हमारे पास है, जब मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे उस टाईम पूरा जवाब दे देंगे। लेकिन अब माननीय सदस्य ने इस बारे में चिन्ता जाहिर की है तो मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण स्पीकर सर, आपके सामने इस सदन में देना चाहता हूं। जहां तक खनन के बारे में चौधरी बंसी लाल जी ने कहा है कि वहां पर लूट मची हुई है, पर्चियां छप रही हैं, यह हो रहा है वह हो रहा है, इसके बारे में मुझे यह कहना है कि खानों के बारे में पहले कोई पॉलिसी नहीं होती थी। आपकी सरकार के आने के पहले चाहे चौधरी भजन लाल जी की सरकार रही हो या चौधरी बंसी लाल जी की सरकार रही हो, उस वक्त अपने मंजूरेनज़र लोगों की ही दरख्वास्तें लेते थे और उनको ही लाईसैंस दे दिए जाते थे। स्पीकर सर, उनको लाईसैंस देने के बाद स्टेट को क्या आमदनी जाती थी वह मैं आपको बताउंगा। अब मैं स्टेट के बारे में ज्यादा न कहते हुए खानों की बात करना चाहता हूं। खानों से सालाना 25 से 30 लाख रूपए की आमदनी होती थी। अब आपकी सरकार ने जो फैसला लिया उसकी वजह से एप्लीकेशन के ऊपर अपने मंजूरेनज़र लोगों को लाईसैंस नहीं दिया जाएगा। स्पीकर साहब, यह स्टेट का संसाधन है, स्टेट के रिसोर्सिज हैं और स्टेट के रिसोर्सिज पब्लिक इन्ट्रस्ट के लिए खर्च किए जाने चाहिए, पब्लिक के डिवैल्पमैंट के लिए खर्च होने चाहिएं। यह कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। खानों के पहाड़ वे चाहे फरीदाबाद में हों या गुड़गांव में हों, ये स्टेट की प्रोपर्टी है और स्टेट की प्रोपर्टी स्टेट के इंट्रस्ट में ही खर्च होनी चाहिए। उनका दोहन अगर इसी तरह से अनस्क्रप्टलैस टाईप के लोग सरकार के साथ मिलकर करते रहेंगे तो एक तरफ तो स्टेट की जायदाद खत्म हो जाएगी और दूसरी तरफ कुछ ही व्यक्ति पलते रहेंगे। इस तरह के व्यक्ति सत्तासीन लोगों की वजह से पलते हैं चाहे उन व्यक्तियों को चौधरी भजन लाल ने या चौधरी बंसी लाल जी ने पाला है। पहले स्टेट को तीस लाख की आमदनी होती थी। अब जब मैं आंकड़े बताऊंगा तो उनको सुनकर सबको हैरानी होगी। हमारी सरकार ने मंजूरेनजर लोगों को छोड़कर इस मामले में यह नयी पोलिसी बनायी है कि अखबारों में इस बारे में एडवरटाईजमैंट देकर ओपन ऑक्शन की जाए। इस बार हमने ओपन ऑक्शन की है और सबको जानकर हैरानी होगी कि जो खनन के पहाड़ हैं जहां से पहले आमदनी केवल 25-30 लाख रुपये के करीब होती थी अब वहां की ऑक्शन 8.79 करोड़ रुपये में गयी है। अध्यक्ष महोदय, कहां 8.79 करोड़ रुपये और कहां 25-30 लाख रुपये। इसका मतलब साढ़े आठ करोड़ रुपया सरकार के मंजूरेनजर लोगों की जेब में जाता था। उन सरकारों में जो लोग मुख्य पदों पर बैठे हुए थे मेरा इस मामले में उन पर सीधा चार्ज है और जो उस समय खुद राजनीतिक लोग सत्ता में थे उनकी जेबों में वह पैसा जाया करता था। स्पीकर साहब, वह पैसा अब सरकारी खजाने में आया है। किसी व्यक्ति विशेष के खजाने में नहीं आ रहा है। वह सारा पैसा स्टेट की डिवैल्पमैंट पर खर्च हो रहा है। स्पीकर साहब,यह पैसा तो केवल ऑक्शन से आया है इसके अलावा जो सेल्ज टैक्स आएगा वह अलग से आएगा। जितनी खुदाई के लिए उनको खानें दी गयी हैं अगर उससे ज्यादा में वे खुदाई करेंगे तो उस पर अलग से रॉयल्टी आएगी। स्पीकर साहब, 8.79 करोड़ की बात है तो यह करीबन-करीबन 18-20 करोड़ जाकर बैठेगा और कहां पहले तीस लाख रुपया

[प्रो0 सम्पत सिंह]

होता था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले की सरकारें क्या किया करती थीं। स्टेट के संसाधनों को मिसयूज किया जा रहा था। यह मिसयूज किसके लिए करना, केवल अपने लिए मिसयूज करना, व्यक्ति विशेषों के लिए मिसयूज करना, अपने रिश्तेदारों के लिए मिसयूज करना और अपने निजी लोगों के लिए मिसयूज करना उस समय की सरकारों की आदत थी लेकिन आज की सरकार जो कर रही है वह पब्लिक इंट्रस्ट मे कर रही है और इसी से इस सरकार की इस बारे में नीति साफ हो जाती है। सारी स्टेट में जो ऑक्शन की गयी है अगर उसके बारे में आप आंकड़ें जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पहले जहां 16-17 करोड़ रुपये की ही आमदनी होती थी वहां पर आज लगभग 70 करोड़ रुपये यानी चार गुणा पर ठेके छोड़े गये हैं और जो माल ज्यादा निकलेगा उसकी रॉयल्टी अलग से आएगी एवं सेल्ज टैक्स बगैह जो आएगा वह भी अलग से आएगा। स्पीकर साहब, चौधरी बंसी लाल जी ने पर्चियों का भी जिक्र किया। वे इतने सीनियर आदमी हैं उनको कुछ तो सोचना चाहिए। इसी तरह से कल फौजी साहब ने भी इसी तरह की पर्चियों की फोटो कापी दिखायी थी और कहा था कि उन पर एप्लाईड फोर लिखा हुआ है। स्पीकर साहब, कोई भी लाईसैंस हो चाहे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो या चाहे आप कोई और लाईसैंस लेना चाहते हों, आपको पहले एप्लाई करना होगा और सरटेन कंडीशंज पूरी करने के बाद ही आप एप्लाई करेंगे। उसके बाद डिपार्टमैंट वैरीफाई करेगा और उस पर जो भी उसकी सिक्योरिटी या श्योरिटी बगैह है वह पूरी होने के बाद ही वह लाईसैंस जारी करेगा। लेकिन जहां तक वैलेडिटी का मामला है, एप्लाईड फोर की वैलेडिटी और जिसके पास लाईसैंस है दोनों की वैलेडिटी एक जैसी है। उसकी जो वैलेडिटी है वह बकायदा है और वे चार्ज भी डैं वन से ही कर रहे हैं। इस तरह का सारा टैक्स सरकारी खजाने में जमा होता है। चौधरी बंसी लाल जी ने यह भी कह दिया कि पर्ची सेल्ज टैक्स के लोग ले नहीं रहे हैं। स्पीकर साहब, उनको इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि जो रिटर्न फाईल की जाती हैं उनकी क्या इस तरह से रोजाना दफ्तरों में पर्चियां दी जाती हैं ? रिटर्न क्वार्टली फाईल करते हैं और जो क्वार्टली रिटर्न फाईल की जाती हैं उसके अंदर चाहे व्यापारी हो या चाहे लाईसैंसी हो, वे अपने काम की रिटर्न फाईल करते है, अपनी सेल की रिटर्न फाईल करते हैं और उसके बाद ही डिपार्टमैंट इस बारे में इन्वैस्टीगेशन करता है। अगर कोई कमी पायी जाती है तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है। स्पीकर सर, स्टेट का एक पैसा भी इस तरह से रहने नहीं दिया जाएगा और यही कारण है कि आज सेल्ज टैक्स की कहीं पर भी चोरी नहीं हो रही है, अफसर एफीशिएंसी से काम कर रहें हैं और डीलर एवं व्यापारी का सरकार को पूरा सहयोग मिल रहा है। इन सब बातों की वजह से व्यापारियों के सहयोग से अधिकारियों की एफीशिएंसी की वजह से और सरकार की नीयत साफ होने की वजह से रैवेन्यू में इंक्रीज आ रही है। 15 परसैंट से ऊपर की टोटल इंक्रीज है जबकि चौधरी बंसी लाल जी के समय में प्वायंट 5 इंक्रीज थी और वह भी अप्रैल की रिकवरी मार्च में करके एक परसैंट इंक्रीज इन्होंने रैवेन्यू में दिखाई थी वरना तो माइनस प्वायंट 5 थी। इस तरह से थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैंने दिया है कि आज कोई भी नाजायज काम नहीं हो रहे हैं। सब काम जायज हो रहे हैं और पब्लिक इंट्रस्ट में हो रहे हैं जिसकी वजह से आज कई गुणा आमदनी हो रही है। चौधरी बंसी लाल जी के और चौधरी भजन लाल जी के समय में इनके निजी आदमी करोड़ों रुपये कमाया करते थे और उनकी जेबों में वह सारा पैसा जाया करता था। लेकिन आज वह पैसा उनकी जेबों में नहीं जा रहा है इसलिए इस बात की इनको तकलीफ हो रही है। यह मैं मानता हूं कि इनकी यह तकलीफ जायज

है लेकिन पब्लिक इंट्रस्ट में हमें किसी व्यक्ति विशेष की तकलीफ प्यारी नहीं है बल्कि हमें पब्लिक का इंट्रस्ट प्यारा है, पब्लिक की तकलीफ प्यारी है। हमें चौधरी भजन लाल या चौधरी बंसी लाल जी के आदमियों की तकलीफ प्यारी नहीं है। इनकी तकलीफों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको तकलीफ होती है तो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। अगर इनको यह नाजायज तकलीफ होगी तो हो लेकिन हमें तो स्टेट का इंट्रस्ट देखना है। सर, यही मैं कहना चाहता था।

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। चौधरी बंसी लाल जी ने भी कहा और मैंने भी कहा था कि हमें ये इस बारे में बता दें कि वहां पर पहाड़ कब खनन के लिए लिया गया और कब उसका ऐग्रीमैंट हुआ तथा रॉयल्टी किस पर लगती है ? यह रायल्टी रॉ मैटीरियल पर लगती है या तैयार माल पर लगती है ? इस बारे में ये हमें तारीख बता दें। इनको हमें यह भी बताना चाहिए कि यह पर्ची कौन से खजाने में गयीं ? स्पीकर साहब, मेरे पास 12.12 की पर्ची है। इन्होंने वहां पर * * * वाले बैठा रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह * शब्द हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस मामले की इंक्वायरी सी0बी0आई0 से हो। जनता के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार इस मामले की इन्क्वायरी नहीं करा रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरी ये मांग है कि इसका जो डायरैक्टर है उसको तुरन्त सस्पैंड किया जाए और इस मामले की इंक्वायरी की जाए। हम तो इसकी डेट लेना चाहते हैं कि कितनी तारीख को ऐग्रीमैंट हुआ और कितनी तारीख को इन्होंने पहाड़ तोड़ना शुरु किया ?

श्री अध्यक्ष : राम किशन जी, आप क्या चाहते हैं जो 25 लाख रुपये उसकी रॉयल्टी थी उसकी इंक्वायरी चाहते हैं या 8 करोड़ रुपये की इंक्वायरी चाहते हैं।

श्री करतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने जो चिट हाथ में ली हुई है उसे देखा जाए कि वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष : राम किशन जी, आप उस चिट को भिजवा दें।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, जिन ठेकेदारों का 3,4,5,9 के ऐवज में डेढ़ साल बाकी पड़ा था उसमें इनका क्या हक था वह ठेकेदार चाहे 100/-रुपये ले, 50/- रुपये ले, हजार रुपये ले या कुछ भी न ले। उसकी रॉयल्टी वापस क्यों ली जाए, धक्का शाही से क्यों ली जाए। अध्यक्ष महोदय, प्रति ट्रक से केवल 30 टन रॉ मैटीरियल की पर्ची कटती है भडाना साहब मंत्री हैं वे इस बारे में बात करें 30 टन का ट्रक दस टायर वाला क्रशर के ऊपर चढ़ा के दिखा दें खाली करा के दिखा दें।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट यानी 1 बजकर 50 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 10 मिनट यानी 1 बजकर 50 मिनट तक के लिए बढ़ाया जाता है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (प्रो0 संपत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, ये कोई रिकार्ड पेश करेंगे तो उसका बाकायदा जवाब भी देंगे, यूं पर्चियां लहराने से बात नहीं बनती। अध्यक्ष महोदय, मैं इनके टाइम का बता देता हूं। चौधरी बंसी लाल ने आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया था कुछ आदमी बदल दिए और अपने आदमी वहां बैठा दिए उससे जो 30 लाख रुपये आया करते थे उसकी जगह 52 लाख की आमदनी होने लगी थी। उस के बाद इन्होंने वहां क्या किया था, उस समय 1997 में उन्होंने क्या किया था कि जो लोग आलरैडी काम कर रहे थे उनकी जगह पर उनसे थोड़े बड़े लुटेरे बैठाए थे और उनको वह ठेके देने से सिर्फ 20 लाख रुपये की आमदनी बढ़ी थी। जो बड़े लुटेरे थे उन्होंने छोटे लुटेरों को कब्जा नहीं दिया था और चौधरी बंसी लाल जी ने इसके लिए 1997 में चार मुकदमें दर्ज करवाए थे और लोगों की बुरी तरह से पिटाई की गई थी सारा कुछ होने के बावजूद छोटे लुटेरे बैठे थे उन्होंने सरकार के साथ समझौता कर लिया था और वह मामला छोड़ दिया था उनको कब्जा भी नहीं दिलाया वरना 52 लाख रुपये आने थे। स्पीकर सर, आपकी सरकार ने जो लोग व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक लोगों से मिलकर नाजायज तौर पर अपना घर पालने के लिए पहाड़ पर बैठे हुए थे उनको हटाकर सही आधार पर ठेके दे दिए जिससे करोड़ों रुपये की आमदनी हुई है और बाकायदा सबको कब्जा दिलाया गया है। पहले इनके आदमी थे अब समझ में आया है कि इन भाइयों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। यह बारबार यह बात कह रहे हैं कि जो पहले बैठे थे उनको क्यों उठा दिया। अध्यक्ष महोदय, जिनका समय पूरा हो गया था उनको उठाना ही था। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है अब पता लग गया है कि इनको तकलीफ क्यों हो रही है। यह सही साबित हो गया है कि वहां इनके नेता के आदमी बैठे हुए थे। मुझे भी यह मालूम है कि राम किशन जी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जहां तक डायरैक्टर की बात है, वह तो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन करवाई है जिसकी वजह से स्टेट को पहले जो 30 लाख की आमदनी आ रही थी वह बढ़कर 8 करोड़ हो गई है यह आमदनी आ रही है उसके ऊपर से टैक्स आएगा वह अलग है। 30 लाख का कर लो 18-20 करोड़ का कर लो मुझे तो इतना हिसाब भी नहीं आता। लगभग 60 गुणा आमदनी बनती है और जो यह 60 गुणा आमदनी हो रही है इससे सड़कें बनेंगी, गांवों का विकास होगा, शहरों का विकास होगा, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, बच्चों को वजीफे मिलेंगे, कन्यादान के लिए लड़कियों को 5100/- रुपया मिलेगा, बुढ़ापा पैंशन मिलेगी। इन भाइयों को ये तकलीफ हो रही है। ऑक्शन होने से पता लग गया है कि इनको क्या तकलीफ हो रही है। यही तकलीफ थी।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : राम किशन फौजी की कोई बात रिकार्ड न की जाये

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

(शोर एवं व्यवधान)

श्री जसबीर मल्लौर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है चौधरी बंसी लाल जी जब बोल रहे थे तो ये मिस्टर शुक्ला जी की चिट्ठी सदन में दिखा रहे थे। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक नारा लगाते थे कि संजय, शुक्ला, बंसी लाल नसबन्दी के तीन दलाल। मैं

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

माननीय साथी राम किशन फौजी से यह कहना चाहता हूं कि ये चौधरी बंसी लाल जी से पूछ कर कल हमें बतायें कि क्या ये वही शुक्ला जी हैं जिनकी चिट्ठी को वे सदन में दिखा रहे थे।

श्री अध्यक्ष : मल्लौर जी आप बैठिये। सैनी जी आप वाईड अप कीजिये।

डॉ बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र कर रहा था पंचायत समितियों का पहले क्या हुआ करता था कि पंचायत का जो सरपंच होता था वह पंचायत के सैक्रेटरी को ढूंढता रहता था। उसके बाद रैजोल्यूशन पास करके किसी भी डिवैल्पमैंट के काम को कराने के लिए या पैसा निकलवाने के लिए बी0डी0ओ0 के आगे पीछे घूमता रहता था। तब जाकर वह पैसा निकलता था। उसके बाद वह काम पूरा होने से पहले ही वह पैसा खत्म हो जाता था। जब जे0ई0, एस0डी0ओ0 को कहते थे तो वे यह कहते थे कि पैसा खत्म हो गया है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने पंचायत की विकास समितियां बनाकर कितना बढ़िया काम कर दिया है कि कार्यवाही रजिस्टर के अन्दर रैजोल्यूशन को दर्ज करके दो पंचायत के सदस्यों के दस्तखत कराकर किसी भी बैंक में जाकर खुद पैसे निकाल सकते हैं। इससे बढ़िया काम पंचायत के लिए और क्या हो सकता है। इससे एक तो विकास का कार्य समय पर हो जाता है और ज्यादा पैसा भी नहीं लगता जबकि पहले काम पूरा होता नहीं था और पैसा पहले खत्म हो जाया करता था। कितना बढ़िया काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने पंचायत के लिए कर दिया है इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

श्री अध्यक्ष : सैनी जी, आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिये।

डॉ बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, जो अभी पैडी का सीजन गया है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े पैमाने पर हरेक मंडी में खुद जाकर किसानों से पूछा कि आपको अपनी फसल बेचने में कोई तकलीफ तो नहीं है। सरकारी एजैंसीज़ आपके अनाज को खरीदने में आना-कानी तो नहीं कर रही हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में उन्हें किसी किसान की कोई शिकायत नहीं मिली जिसने यह कहा हो कि उनका अनाज ठीक रेट पर नहीं बिका। अध्यक्ष महोदय, इससे बढ़िया किसानों के लिए कौन सी सरकार होगी। सिर्फ किसानों का सवाल नहीं है, मुख्य मंत्री महोदय ने मण्डियों में जाकर वहां के व्यापारियों और आढ़तियों से भी पूछा कि आपको कोई दिक्कत है तो बताओं। यहां तक कि जो लेबर का काम करते हैं, जो पल्लेदारी का काम करते हैं, उनको मुख्य मंत्री महोदय, ने इकट्ठा करके पूछा कि आपको कोई तकलीफ है तो मैं उसको दूर करने के लिए बैठा हूं। इसके अलावा अगर मौके पर उनके पास कोई शिकायत आई तो उन्होंने वहीं अधिकारियों को आदेश दिया कि इस शिकायत को दूर करो। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जन-स्वास्थ्य के बारे में पढ़कर बताया कि जो पानी पहले प्रति व्यक्ति प्रति दिन 40 लीटर मिलता था उसको बढ़ाकर 55 से 70 लीटर कर दिया है या करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रदेश में एक स्कीम दी हुई है जिसका नाम है 'पायलट प्रोजैक्ट स्कीम'। इस स्कीम के तहत अगर किसी गांव में पानी के लिए कोई नया ट्यूबवैल लगवाना है या कोई पाइप लाइन बिछानी है और इस काम को पब्लिक हैल्थ ने करना होता है तो उसके लिए 10 परसैंट रुपया गांव के आदमी खुद इकट्ठा करके पब्लिक हैल्थ के पास जमा कराएंगे और 90 परसैंट रुपया सरकार देगी। इस मामले में मैं सरकार से कहना चाहूंगा, और एक सुझाव देना चाहूंगा कि करनाल और यमुनानगर जिलों में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर टोटल आबादी हरिजनों की है। वे किसी भी काम के लिए 10 परसैंट

रुपया इकट्ठा करके नहीं दे सकते। जैसे कि ट्यूबवैल लगवाने के लिए 10 लाख रुपये का एस्टीमेट है तो उसमें से एक लाख रुपया गांव के लोग इकट्ठा करके देंगे और 9 लाख रुपया सरकार देगी लेकिन वे लोग बहुत गरीब हैं क्योंकि उनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है इसलिए यह मुश्किल है कि वे लोग गांव में से एक लाख रुपया इकट्ठा करके सरकार के पास जमा कराएं और वहां ट्यूबवैल लगवा सकें। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि करनाल और यमुनानगर में जो ऐसे गांव हैं उनको इस पायलट स्कीम से बाहर रखकर वहां अपनी तरफ से सारा पैसा मुहैया कराकर ट्यूबवैल लगवा कर पानी का इंतजाम कराएं।

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, on Thursday, the 7th March, 2002.

*13.49 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, on Thursday, the 7th March, 2002.

34759—H.V.S.—H.G.P., Chd.